हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

10 मार्च, 1989

खण्ड 1, अंक 12

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 10 मार्च, 1989

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(12)1
विभिन्न विषयों का उठाया जाना	(12)33
वर्ष 1989–90 के बजट पर सामान्य चर्चा	(12)36
वाक–आउट	(12)70
वर्ष 1989–90 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(12)71
बैठक का समय बढ़ाना	(12)86
वर्ष 1989–90 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(12)86
बैठक का समय बढ़ाना	(12)89
वर्ष 1989– 90 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(12)90

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 10 मार्च, 1989

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान सभा, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में प्रात 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहैंबान, अब सवाल होंगे।

Licences for the sale of Fertilizer, Seed and Insecticides

***903. Shri Surinder Kumar Madan :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) the district-wise number of licences issued for the sale of Fertilizer, Seeds and Insecticides during the period from 1980-81 to 1987-88 separately in the State ;

(b) whether any of the samples of the afore-said commodities were taken by the Agriculture Department during the period as referred to in part (a) above, for testing;

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative the district-wise number of such samples found substandard; and

(d) whether criminal proceedings have been launched against all the defaulting firms, if not the reasons thereof ?

Mr. Speaker : Extension has been asked for in respect this question which has been granted. The communication received from the Minister concerned in this connection reads as under :-

Interim Reply

D. 0. No. 556-AM-89

"**TAYYAB HUSSAIN**

Agriculture Minister, Haryana,

Chandigarh.

March 8, 1989

IMMEDIATE

ASSEMBLY BUSINESS

Sub. : Starred Assembly Question No. 903 regarding licences for the sale of fertilizer, seed and insecticides asked by Shri Surinder Kumar Madan, M. L. A. and fixed for reply on 10-3-1989 extension in time for submission of reply to the Vidhan Sabha.

Dear Sardar Sahib,

Kindly refer to the subject cited above.

2. This Starred Question (No. 903) has been fixed for reply on March 10, 1989. The information required to be given in the reply pertains to districtwise number of licences issued for the sale of fertilizer, seed and insecticides during the period from 1980-81 to 1987-88. Inspite of best efforts the

Department has not been able to collect the requisite information from all the districts. It requires thorough examination of all licencing cases pertaining to these three commodities for 8 years. It is a time-consuming and lengthy process and it may take another two weeks to compile the same.

3. In view of the position explained above, I request you to kindly grant two weeks extension for submitting the reply to the Vidhan Sabha.

With my warm regards,

Yours Sincerely,

Sd/-

(Tayyab Hussain)

Shri H.S. Chatha,

Speaker, Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh"

Upgradation of Schools in the State

***776. Shri Jai Singh Rana :** Will the Minister for Eduction be pleased to State—

(a) the number of schools upgraded from Primary to Middle and from Middle to High Schools in the State during the year 1988-89; and

(b) the number of schools out of these as referred to in part (a) above that have been upgraded in District Karnal

and in Nilokheri Constituency, separately?

खाद्य तथा पूर्ति मन्त्री (श्रीमती सुषमा स्वराज):

(क) 50 कन्या प्राथमिक विद्यालयों को स्तरोन्नत करके माध्यमिक तथा 25 कन्या माध्यमिक विद्यालयों को स्तरोन्नत करके उच्च बना दिया गया है।

(ख) जिला करनाल में तीन कन्या प्राथमिक विद्यालयों, को स्तरोन्नत करके माध्यमिक विद्यालय बना दिया गया है। नीलोखेड़ी विधान सभा क्षेत्र में कोई भी स्कूल स्तरोन्नत नहीं किया गया है।

श्री जय सिंह राणा: क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि करनाल में जो तीन स्कूल अपग्रेड किए गए हैं वे कौन–कौन से हैं और नीलोखेड़ी में कोई भी स्कूल अपग्रेड न करने का क्या कारण है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: स्पीकर साहब, करनाल में जो तीन स्कूल अपग्रेड किए गए हैं उनके नाम हैं मतलौडा, शहाजदपुर और शेरा। नीलोखेड़ी में किसी भी स्कूल को इसलिए अपग्रेड नही किया गया क्योंकि नीलोखेड़ी से अपग्रेडेशन की जो मांग आई थी या जो भी प्रस्ताव आए थे वे लड़कों के स्कूलों को अपग्रेड करने के आए थे। ये प्रस्ताव आठ स्कूलों को अपग्रेड करने के आए थे। चार प्राईमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल करने का प्रस्ताव था और चार स्कूलों को मिडिल से हाई स्कूल अपग्रेड करने का था। हमारे

पास कन्या स्कूल को अपग्रेड करने का प्रस्ताव नहीं आया। इसलिए नीलोखेड़ी में कोई भी कन्या स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया।

श्री जय सिंह राणाः क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि तरावड़ी के कन्या हाई स्कूल को 10+2 में अपग्रेड करने पर विचार किया जाएगा?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष हमने कोई भी स्कूल 10+2 अपग्रेड नहीं किया है। केवल प्राईमरी और मिडल स्कूलों को ही अपग्रेड किया हैं। लेकिन आगामी वर्ष में 25 हाई स्कूल सीनियर सैकेण्डरी स्कूल अपग्रेड करेंगे। ये अपना प्रस्ताव भिजवा दें। हम विचार करवा लेंगे। अगर वह आधार पर पूरा उतरेगा तो हम उस पर विचार कर लेगे।

श्री रणजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया ने बताया है कि केवल कन्याओं के स्कूल ही अपग्रेड किए गए हैं और ब्वायज का कोई स्कूल अपग्रेड

नहीं किया गया। कहीं इसमें महिलाओं के साथ पक्षपात की बात तो नहीं **श्रीमती सुषमा स्वराजः** अध्यक्ष महोदय, जहां तक महिलाओं के साथ पक्षपात की बात है, इस तरह का कोई सवाल ही नहीं उठता। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी यह महकमा टेक ओवर किया है। मेरे से पहले तो पुरुष ही इस विभाग के मन्त्री थे।

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, मेरी सारी कांस्टिचुऐंसी में केवल एक ही कन्या हाई स्कूल है। क्या मन्त्री महोदया उसको 10+ 2 में बदलने की कृपा करेंगी?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, हमारी पहली कोशिश यह होती है कि असंतुलन को समाप्त किया जाए और कहीं पर भी इम्बैलैसं न रहैं। अगर एक ही हाई स्कूल है तो अवश्य ही उसे 10 + 2 में बदलते में प्राथमिकता वेंगे अगर वह स्कूल नौर्मज पूरे करता होगा।

श्री मुनी लालः स्पीकर साहब, महैंन्द्रगढ़ जिले में मेरी कास्टिचुऐसी बावल में लड़कियों का कोई मिडल स्कूल नहीं है केवल पीतनवास में प्राइमरी स्कूल है। क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि इसको अपग्रेड करने पर विचार किया जाएगा?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने भागी राम जी के सवाल के जवाब में बताया है कि जहां इस तरह का असंतुलन है वहां सब से पहले स्कूल अपग्रेड किया जाएगा। अगर वहां ऐसा स्कूल नहीं है तो वहां के स्कूल को जरूर अपग्रेड किया जाएगा।

श्री रत्न लाल कटारियाः अध्यक्ष महोदय, रादौर में एक भी कन्या हाई स्कूल नहीं है। क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि इस ओर ध्यान दिया जाएगा?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बता दिया है कि जहां एक भी कन्या हाई स्कूल नहीं है वहां पर सब से पहले प्राथमिकता दी जाएगी अगर वह स्कूल नौमर्ज पूरा करता होगा?

श्री कान्ति प्रकाश भल्लाः अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदया ने बताया है कि मैंने यह महकमा अभी टेक ओवर किया है और पहले यह महकमा मेरे पास नहीं था। क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि अम्बाला जिले का कोई स्कूल इसीलिए अपग्रेड नहीं किया गया क्योंकि अम्बाला जिले का मिनिस्टर नहीं था और क्या अब अम्बाला जिले का ख्याल अपग्रेडेशन के मामले में रखा जाएगा?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह कहा था कि स्कूलों को अपग्रेड करते समय किसी तरह का कोई फेवर नहीं किया जाता। जिस इलाके से स्कूल अपग्रेड करने की मांग आती है और अगर वह स्कूल नौर्मज पूरा करता है तो उसको अपग्रेड किया जाता है। अम्बाला के साथ कोई फेवर नहीं किया जाएगा बल्कि इलाके की मांग और मैरिट को देखते हुए ही स्कूलों का अपग्रेडेशन किया जाएगा।

श्री शिव प्रशादः अध्यक्ष महोदय, अम्बाला छावनी और अम्बाला शहर में लड़कियों का कोई सरकारी विद्यालय नही है।

श्री अध्यक्षः अम्बाला में तो बहुत स्कूल हैं।

श्री शिव प्रशादः स्पीकर साहब, अम्बाला शहर में 10+2 का लड़कियों का स्कूल है। क्या मन्त्री महोदया उस लड़कियों के स्कूल को महाविद्यालय में बदलने पर विचार करेंगी?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, इस बार कालेज तो केवल तावडू और मंडी डबवाली में ही खोलने का प्रावधान है।

श्री अध्यक्षः मास्टर जी, वैसे यह सवाल कालेजिज के बारे में नहीं है।

श्री दुर्गा दत्त अत्रीः स्पीकर साहब, आपने कुछ दिन पहले एक आश्वासन दिया था कि बहन जी के माईक को ठीक करवा दिया जायेगा लेकिन आज तक वह माईक शायद ठीक नहीं हो पाया है। इसके क्या कारण हैं? (हंसी)

श्री अध्यक्षः उन्होंने कहा था कि वे चौकी रख लेंगी।

श्री योगेश चन्द शर्माः अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य मन्त्री महोदय 24 अप्रैल को जब फरीदाबाद बस स्टैण्ड का उद्घाटन करने के लिए गये थे तो उन्होंने बागपुर के मिडल स्कूल को अपग्रेड करने का आश्वासन दिया था मगर अभी तक उनकी इस घोषणा को क्यों नहीं इम्पलीमैंट किया गया? क्या मन्त्री महोदया यह बताएंगी कि कब तक इस बागपुर के स्कूल को अपग्रेड कर दिया जाएगा?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य महोदय कृपया यह बता दें कि वह स्कूल कन्याओं का है या को–ऐलुकेशनल है?

श्री योगेश चन्द शर्माः को–ऐजूकेशनल है।

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, पिछले साल की सरकार की जो नीति थी, उसमें यह नहीं पड़ता है लेकिन इस साल 1989 में जो नीति हम बनायेगे उसमें इस का प्रावधान करने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे और मुख्य मन्त्री महोदय जी ने जो आश्वासन दिया था उसका हम पूरी तरह से आदर करेंगे।

श्री जय नारायण खुडियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि जिला रोहतक के अन्दर लड़कियों के कितने स्कूल्ज अपग्रेड किये गये हैं और कलानौर के अन्दर भी कोई स्कूल अपग्रेड किया गया है या नहीं?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह बता देना चाहती हूं कि जिला रोहतक में 8 स्कूल्ज प्राइमरी से मिडल अपग्रेड किये गये हैं औंर उनके नामों की सूची मैं पढ़कर सुना देती हूं। भाई खुंडिया जी देख लें कि उनके हल्के से कौन सा स्कूल सम्बन्धित है। ये स्कूल्ज हैं नजरी, गुडियानी, माहरा, महमूदपुर, मसाना, खेड़ीखुआर, चिराना और विराही इत्यादि।

तारांकित प्रश्न संख्या 749

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री भगवान सहाय रावत, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Constitution of Committee to review enhancement in water rates, stamp duty etc.

***867. Shri Ranjit Singh : Will** the Minister of State for Local Government be pleased to State—

(a) whether it is a fact that the present Government has constituted a Cabinet Sub-Committee to review the increased water rates, development charges and stamp duty in the Urban areas in the State;

(b) whether the Sub-Committee, as referred to in part (a) above, has invited public objections; if so, date there of; and

(c) whether the Cabinet Sub-Committee, as referred to in part (a) above, has submitted its report to the Government; if so, the details thereof?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) :

(a) Yes .

(b) No .

(c) No. Not yet.

श्री रणजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो पैसा बढ़ाया गया है, जितना टैक्स इसमें बढ़ा है क्या इस पर लोगों का फेवरेबल रिऐक्शन है? इसमें कोई किसी प्रकार– की दिक्कत तो नहीं आ रही हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, वाटर रेट्स, औक्ट्राय रेट्स व सीवरेज रेट्स रिवाईज करने की प्रोपोजल थी, जिससे पब्लिक में रिजैन्टमैंट हुई थी। इसीलिये सरकार ने इसके लिये कैबिनैट की एक सब कमेटी नियुक्त की है जोकि जन–प्रतिनिधियों की है और वह कमेटी सारे मामले पर गौर कर रही है।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की हैं जोकि सभी मामलों को गौर करने के बाद निपटाएगी। क्या मन्की महोदय बताएंगे कि हाउस टैक्स लगाने की जो सीमा 1000 रुपये तक की वार्षिक आमदनी की है उसे बढ़ाकर कम से कम 5000 रुपये करने की बात सरकार के विचाराधीन है? अगर नही है, तो चूंकि आज हाउसिंग की कीमत काफी बढ़ चुकी है इसलिये क्या सरकार मेरे इस सुझाव पर गौर करने के लिये यह मामला भी उस कमेटी को सौंपेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, उस कमेटी के सामने वही मुद्दे हैं जिन पर लोकल सैल्फ गवर्नमैंट ने टैक्स रिवाईज किये

थे। वाटर रेट्स, औक्ट्राय रेट्स व ई० डी० चार्जिज वगैरह के मुद्दों पर ही यह कमेटी विचार करेगी।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस सब–कमेटी का फैसला कब तक हो जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंहः जल्द ही हो जाएगा।

डा० बृज मोहनः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या स्टैम्प डियूटी भी बढ़ाई गई है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः उसकी भी इन्क्रीज हुई थी। इसीलिए वह भी अन्डर कसिड्रेशन है।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने पार्ट 'ख का उत्तर 'न' में दिया है। फिर इन्होंने बताया कि ये टैक्स बढ़ाने से जनता में रोष आया और उसको देखते हुए एक कमेटी बनाई गई। दूसरे जिस ढंग से ये टैक्स बढ़ाए गए हैं क्या ये संतुलन के मुताबिक ज्यादा नहीं हैं, क्योंकि इससे जनता में आक्रोश पैदा हुआ? तीसरे यह कमेटी कब बनाई गई थी और इसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी और इसमें जनता के लोगों को एतराज या राय के लिए क्यों नहीं बुलाया गया?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, लोगों का मैमोरैडंम आया हुआ है जिसे वह कमेटी ऐग्जामिन कर रही है। अगर कमेटी

आवश्यकता महसूस करेगी तो विभिन्न और्गेनाइजेशज के रिप्रजैटेटिवज को जरूर बुलाएगी। दूसरी बात इन्होंने पूछी कि जो रिवीजन की गई थी क्या उसे यह कमेटी ठीक, समझ रही है? इस पर विचार हो रहा है और विचार के बाद ही किसी नतीजे पर कमेटी पहुंचेगी। तीसरे, इन्होंने पूछा कि कमेटी कब बनी थी, वह फरवरी के महीने में बनी थी और वह अपनी रिपोर्ट जल्दी दे देगी।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, क्या मन्त्री जी बताएंगे कि आदरणीय मुख्य मन्त्री जी ने ऐसे भी आदेश दिए हैं कि जब तक कमेटी का फैसला न हो जाए तब तक वसूली बन्द कर दी जाए लेकिन उसके बावजूद भी बड़े हुए वाटर रेट्स की वसूली हो. रही हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, सब तरह की वसूली बन्द कर दी गई है।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वाटर चार्जिज और डिवैल्पमैंट चार्जिज बढ़ाते हुए शहरी आबादी के अन्दर वेतन भोगी लोगों और मजदूरों की इन्कम का भी कोई क्राइटेरिया रखा गया या नहीं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, यह सारा मामला कमेटी के जेरे गौर है। क्या क्राईटेरिया था, क्या नहीं था, इसको ठीक

तरह से फौलो किया है या नहीं, इन सारी बातों पर गौर करके कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी।

श्री कुन्दन लाल भाटिया: स्पीकर साहब, फरीदाबाद में कल तक पानी के बिल 12 रुपए की बजाय 55 रुपए लिये जा रहैं थे मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसको रोका जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, पहले ही रोक दिया गया है। फिर भी अगर कोई ऐसी बात हो तो भाटिया जी हमें लिखित रूप में दे दे, हम उस पर ऐक्शन लेंगे।

श्री रणजीत सिंह: स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जक् से मुख्य मन्त्री जी ने वसूली रोकने के आदेश दिए हैं क्या उसके बाद इस कमेटी की कोई मीटिंग हुई हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इस कमेटी की एक मीटिंग 6/2 को हुई थी उसके बाद कमेटी ने कुछ जिम्मेदारी कमेटी की आनरेबल सदस्या श्रीमती सुषमा स्वराज पर डाली, उन्होंने 1572 को मीटिंग की उसके बाद तीसरी मीटिंग नहीं हुई।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, क्या नकल लेने पर भी फीस बढ़ाई गई है, अगर हां तो क्या उस पर भी विचार करेंगे?

Shri Verender Singh : That is not within the purview of this Committee.

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री जी ने बताया था कि इसके मैम्बर जन प्रतिनिधि हैं। तो क्या उसमें विरोधी पक्ष का भी कोई मैम्बर है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, वह तो एक कैबिनैट सब–कमेटी है। उसमें विपक्ष के मैम्बर का सवाल कैसे आता है? कैबिनैट सब–कमेटी के मैम्बर भी तो जन प्रतिनिधि हैं

तारांकित प्रश्न संख्या 917

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री शिव लाल, इस समय सदन मै उपस्थित नहीं हैं।

Construction of bridge on Zair Drain

***737. Shri Yogesh Chand Sharma ;** Will the Minister for P.. W. D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any scheme under consideration of the Government to construct a bridge on the Zair Drain in Khadar area of district Faridabad during the year 1989-90; and

(b) if so, the time by which the work is likely to be started/ completed?

Public Works Minister, (Shri Om Parkash Bhardwaj)

(a) Government has decided to survey and invesitgate the feasibility of the project for the present.

(b) No time limit can be specified for the starting/ completion of the works.

श्री योगेश चन्द शर्मा: स्पीकर साहब, हमारी सरकार के बनने के फौरन बाद हमारे आदरणीय मुख्य मन्त्री जी ने इंजीनियर–इन–चीफ और दूसरे औफिसर्ज को यह हुकम दिया था कि इस पुल को बनाने के लिए ऐस्टिमेट्स बनाए जाएं और पिछले साल इस बारे में सारा सर्वे हो चुका है। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस पुल को बनाने के लिए उद्घाटन करने में कितना समय लगेगा और यह पुल कब तक कम्पलीट हो जाएगा?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाज: स्पीकर साहब, जैसे मैंने मेन सवाल के जवाब में बताया है, इस बारे में कोई टाईम लिमिट नहीं बताई जा सकती।

तारांकित प्रश्न संख्या 781

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री उदय भान, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Linking of Village with Main Road

***716. Comrade Harpal Singh :** Will the Minister for P. W. D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under conisderation of the Govt. to link the village Chillewal abadi in Tohana Constituency with the main Road; and

(b) if so; the time by which the aforesaid village is likely to be linked ?

Public Works Minister (Shri Om Parkash Bhardwaj)

(a) Yes.

(b) The road will be completed as early as possible depending upon the availability of funds.

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, सदन के अन्दर बार बार यह जिकर रहता है कि सड्कों को बनाया जाए। कुछ सड्कों को बनाने के लिए मैटीरियल भी वहां पर पड़ा रहता है और कई कई साल तक मैटीरियल वहां पर पड़ा रहने के बावजूद भी उस सड़क को 'नही बनाया जाता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांव चिलेवाल को सड़क से जोड़ने के लिये दो बार मिट्टी डल चुकी है। वह केवल दो तीन किलोमीटर का टुकड़ा है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उस सड़क को कमाने के लिए कोई टाईम बाउंड प्रोग्राम नही बनाया जा सकता कि इतने दिन में उसको बना दिया जाएगा क्योंकि मैटीरियल की कौस्ट भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, यह सड़क जून, 199० तक बना दी जाएगी लेकिन यह मानना पड़ेगा कि कामरेड साहब कब्र खोदने में बड़े माहिर हैं। (हंसी)

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सारे हरियाणा प्रदेश में ऐसे

कितने गांव हैं जो सड़क से नहीं जोड़े गए हैं क्योंकि हर बार सैशन में सरकार की तरफ से तो यह कहा जाता हैं कि हरियाणा प्रदेश में हर गांव सड़क से जुड़ा हुआ है लेकिन मैम्बर्ज साहैंबान कई गांवों को सड़क से जोड़ने की बात कहते हैं?

Mr. Speaker : Comrade Sahib, this is not the way. You may at the most put the supplementary regarding the villages of your constituency.

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मेरे हल्के में चिलेवाल गांव ऐसा है जो आज तक सड़क से नहीं जोड़ा गया है। मैं कोई कब बगैरह खोदने की बात तो नहीं करता मैं तो आपके द्वारा मन्त्री जी से यही जानना चाहता हूं कि उस सड़क को कब तक कम्पलीट कर दिया जाएगा?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाजः स्पीकर साहब, पूरे हरियाणा प्रदेश के 6745 गांवों में से केवल 34 गांव ऐसे हैं जो सड़क से नही जुड़े हुए हैं। माननीय सदस्य के हल्के में ऐसा कोई गांव नहीं है जो डायरैक्टरी विलेजिज में कवर न हुआ हो।

Outstanding Electricity Charges

***755. Shri Devi Dass :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether any arrear on account of Electricity charges are outstanding against any firms, factories, private houses in District. Sonipat as on 31-12-1988; and

(b) if so, the names and addresses, out of those referred to in part (a) above, against whom arrears of more than rupees 5000/- are outstanding

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) :

(a) Yes, an amount of. Rs. ,130.63 lakhs is outstanding.

(b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

The names and addresses of the firms, Factories and Private houses in Sonipat District against whom a defaulting amount of Rupees 5,000/ and above was out-standing as on 31-12-88 are as follows.

(A)" FIRMS AND FACTORIES

Sr. No.	Name	Address
1	M/s. Indo Malt	Industrial Estate Murthal
2	M/s. Indo Malt	Industrial Estate Murthal
3	M/s. B. M. Auto Industries	Murthal Estate Sonipat
4	MA. Haryana Electro Steel V. P. O. Larsoli	Prop. Pradeep Gupta 83-Anand Lok N. Delhi.
5	M/s. Haryana Steel	G. T. Road Muthal

	Alloys	
6	M/s. Haryana Steel Alloys	G. T. Road Murthal
7	M/s. Bharat Steel Tubes.	Ganaur
8	M/s. Ganaur Paper Board	G. T. Road Ganaur
9	M/s. Rama Ice Factory	Panchi Road Ganaur
10	M/s. Yogesh Cold Storage	G. T. Road Ganaur
11	M/s. Bajrang Bali Oil Mill	Village Kharkhoda
12	M/s. Bharat Ice Factory	Sampla Road Kharkhoda
13	M/s. Vijay Cotton	Kharkhoda Town
14	M/s. S.D.O. Drainage	Sonipat
15	M/s. SDO Drainage	Sonipat
16	M/s. SDO Drainage	Sonipat
17	M/s. SDO Drainage	Sonipat
18	M/s. SDO Drainage	Sonipat

19	M/s. SDO Drainage	Sonipat
20	M/s. SDO Drainage	Sonipat
21	Ashok Niwar Factory	Gohana City
22	Eastern Gases	G.T. Road Kundli Sonipat
23	Kirori Engg.	G.T. Road (Rai) Sonipat
24	Rajdhani Textile	Ind. Area Sonipat
25	N. K. Nirula	Ind. Area Sonipat
26	M/s. Tuna Jute	G. T. Road Kundli Sonipat.
27	R. P. Foundary	Sevli Road Rai Sonipat
28	Gram Panchayat	V. Bhyanpur
29	Gram Panchayat	V. Lalrara Sonipat
30	Santosh Industries	V. Lalrara Sonipat
31	Deepak Kumar	V. Lalrara Sonipat
32	R.R.I.	Bahalgarh Sohipat
33	R.R.I.	Bahalgarh Sonipat
34	Sonipat Woolen Mills	G.T. Road (Kundli) Sonipat.
35	Arihant Floor Mills	Bahalgarh Sonipat
36	Alkesh Cold Storage	G.T. Road Kundli

37	Param Rubber	Ind. Area Sonipat
38	Elaste Chemicals	Ind. Area Sonipat
39	Doya Springs	G.T. Road (Rai) Sonipat
40	Rollatainer	Narela Road Kundli
41	Subrat Chemical	Deopalpur Road, Bahalgarh Sonipat
42	Meta Chemicals	Bahalgarh Road Sonipat
43	ARC Electrodes	G.T. Road Kundli Sonipat
44	Gateway quoted	V. Kundli (Sonipat)
45	K.L. Steel	Bahalgarh Road Sonipat
46	Haryana Steel Feb.	Bahalgarh Road Sonipat
47	Jasbro & Co.	G.T. Road Rasoi (Sonipat)
48	Ajay Cables	Jatheri Road Rai Sonipat
49	Kashmir Katha	G.T. Road Kundli
50	Sabarwal Food	G.T. Road Rasoi Sonipat
51	Vikas Steel	Bahalgarh Sonipat
52	Om Weaving Ind.	Bahalgarh Road Sonipat
53	Jai Hanuman	Bahalgarh Road Sonipat
54	Sooraj Steel	Ind. Area Sonipat

55	Organ Chemical	Ind. Area Sonipat
56	M/s. R.R.I.	Bahalgarh Sonipat
57	E.C.E. T/F Divn.	Delhi Road Sonipat
58	M/s. Haryana Vanaspati and General Mills	Narela Road Sonipat
59	Gateway Speciality	Narela Road Kundli Sonipat
60	Atlas Auto	G.T. Road Rasoi Sonipat
61	R.K. Electricals	Jatheri Road Rai Sonipat
62	M/s, Singla Steel	Bahalgarh Sonipat
63	M/s. Gupta & Co.	Janti Road Kundli Sonipat
64	Haryana Arylic	Jatheri Road Rai Sonipat
	(B) PRIVATE HOUSES :	
1	Gram Panchayat	V. Rajpur
2	Ch. Bhupinder Singh	V. Larsoli Sonipat
3	Sis Ram	V. P.O. Rohat Sonipat
4	Jai Bhagwan	V.P.O. Kakroi Sonipat
5	Bhajan Lal	V. P.O. Gopalpur Sonipat
6	Dalel Singh	V. P.O. Rohat Sonipat

7	Gram Panchayat	V. P.O. Bhatgaow
8	Rameshwar Dass	V. Garhi Gohana
9	Raghvinder Singh	V. Bhanswal Kalain Gohana
10	Sarpanch Gram Panchayat	V. Busana Teh. Gohana
11	Raghvinder Singh	V. Bhanswal Kalain
12	Lajpat Rai	Gohana City
13	Tilak Raj	Gohana City
14	Jagdish	Gohana City
15	Jai Lal	Bhanswal Kalain
16	Garg Niwar Factory	Gohana City
17	Vijay Singh	Gohana City
18	Amar Nath Dewan	Gohana City
19	Om Service Station	Gohana Road Sonipat
20	Ram Kishan	Ind. Area Sonipat
21	Ashok Kumar	Ind. Area Sonipat
22	Jagdish Pal	V. P.O. Manauli
23	Bihari Lal	M/s. Bello Engg. Indl. Area Soninat

24	Gela Ram	Subhash Chowk Sonipat
25	Shankar	Gohana Road Sonipat
26	Nav chetan	G.T.Road Ratoi Sonipat
27	Raj Singh	V. P. 0. Kirnoli Sonipat

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, सदन के पटल. पर जो जवाब रखा गया है उसके पेज 3 पर आइटम नम्बर 5 में कोई भजन लाल नाम का आदमी है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि इसके खिलाफ कितना पैसा बकाया है और क्या यह आदमी भजन लाल वल्द खैराज है या कोई और हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, यह आदमी भजन लाल वल्द खैराज तो नही है लेकिन इस के खिलाफ 5612 रुपए 90 पैसे बकाया हैं।

श्री रणजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि 64 इण्डस्ट्रीज और 27 प्राईवेट हाउसिज ऐसे हैं जिनके खिलाफ विजली बोर्ड का 130.63 लाख रुपए का एरियर बिजली का बकाया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार ने इनसे रिकवरी के लिये क्या कार्यवाही की है? साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहूगा कि क्या ये केसिज 5 या 10 साल से पैंडिंग हैं या इससे अधिक की अवधि के हैं? यदि 'इस अवधि के केस पैंडिंग हैं तो बिजली बोर्ड ने क्या कार्यवाही की है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इस लिस्ट के मुताबिक एकाध केस तो 1976 से चला आ रहा है और अधिकतर केसिज ऐसे हैं जो 1984 के बाद के हैं। जहां तक बिजली बोर्ड द्वारा कार्यवाही करने का ताल्लुक है, इनमें बहुत से लोग कोर्ट में चले गए है और उनके केस अब कोर्ट में पैंडिंग हैं और कुछ कन्ज्यूमर्ज ऐसे भी हैं जिनके केसिज आर्बिट्रेटर के सामने हैं'?।

श्री देवी दासः अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि नम्बर 7 पर मैसर्ज भारत स्टील टयूब, गन्नौर, नं०24 पर राजधानी टैक्सटाईल, इण्डस्ट्रीयल एरिया, सोनीपत, नं० 52 पर ओम वीविग इण्डस्ट्रीज, बहालगढ रोड? सोनीपत नं० 54 पर सूरज स्टील इण्डस्ट्रीयल एरिया, सोनीपर, नं० 60 पर एटलस औटो, जी०टी० रोड रसोई, सोनीपत और नं० 64 पर हरियाणा अरलीक, जठेड़ी रोड राई, सोनीपत इण्डस्ट्रीज के खिलाफ कितनी कितनी राशि कब से बकाया है और इनसे रिकवरी के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, 7 नम्बर पर जो इण्डस्ट्री है उसके खिलाफ 7 लाख 12 हजार 212 रुपये 50 पैसे जुलाई 1987 से बकाया हैं और मुकदमा कचहरी में चल रहा है, 24 नं० पर जो केस है इस के खिलाफ 9,299. 80 रुपये जनवरी, 1987 से बकाया है और केस आर्बिट्रेटर के सामने है। 52 नं० पर जो केस है इसके खिलाफ 49,411. 89 रुपये अगस्त, 1987 से बकाया हैं और इससे रिकवरी की कार्यवाही चालू है। 54 नं० पर

जो केस है इसके खिलाफ 4,31, 262 95 रुपये जून, 1986 से बकाया हैं और कोर्ट में केस 'पै डिग है। 6० नम्बर पर जो केस है इसके खिलाफ छ, 28,545 रुपये मई, 1987 से बकाया हैं और केस आर्बिट्रेशन में पैंडिंग है और 64 नम्बर पर जो केस है इसके खिलाफ 1, 05, 228 रुपये जून, 1987 से बकाया हैं और केस आर्बिट्रेटर के सामने है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अभी कई इण्डस्ट्रीज के खिलाफ पैंडिंग अमाऊंट के बारे में बताया है। मैं उन से जानना चाहत हूं कि 5 और 6 नम्बर पर जो इण्डस्ट्रीज इनके हिस जिले की ही हैं, इनके खिलाफ कितना–कितना अमाऊंट कब से बकाया है और इनसे पैसा लेने के लि ये क्या कार्यवाही की जा रही है? मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या इन धन्ना सेठों से पैसों की इफैक्टिव रियालाइजेशन के लिये कोई कार्यवाही करने की योजना बना रहैं हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, नम्बर 5 और 6 के बारे में डाक्टर साहब ने पूछा है। नम्बर 5 के अगेन्सट 1, 17, 205. 50 रुपये की राशि फरवरी, 1986 से बकाया है और कोर्ट में केस पैडिंग है। नम्बर 6 के अगेन्सट 1, 80,391. 50 रुपये की राशि अगस्त, 1988 से बकाया है तथा कोर्ट में केस पैंडिंग है। स्पीकर साहब मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों की जानकारी के लि ये बताना चाहूंगा कि बिजली बोर्ड की बहुत बड़ी रकम डिफाल्टर्ज की तरफ बकाय है। प्राईवेट डिफाल्टर्ज के अगेन्सट इस स मय लगभग

22 करोड़ से भी०पर की रकम बकाया है जो कि बहुत पुरानी रकम है। हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कोर्टस हैं। कोर्टस से स्टे मिल जाता है और 10,10 या 15– 15 साल तक उन मुकद्दमों का फैसला नहीं हो पाता है। मौजूदा सरकार ने और कैबिनैट ने कल ही इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी ऐक्ट में तरमीम के लिये बिल ऐप्रूव किया है जो इसी सैशन में ही आ जाएगा। इस में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के पास अगर बिल आ जाए और उसको उस पर किसी प्रकार का कोई औब्जैक्शन हो तो कोर्ट उस को तभी एण्टरटेन करे जब वह व्यक्ति टोटल बिल की 50 फीसदी रकम बोर्ड के पास डिपौजिट करवा दे। वही एक ऐसा रास्ता बैन सकेगा जिससे बिजली बोर्ड की इस अथाह रकम की अदायगी कुछ हद तक हो पाएगी।

श्री रणजीत सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो 64 इण्डस्ट्रीज, इन्होंने बताई हैं क्या इनमें से कोई इण्डस्ट्री ऐसी भी है 'जिसका स्टे वैकेट हो गया हो और उसकी अटैचमैंट के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की हो?

श्री वीरेन्द्र सिंहः ऐसा है, स्पीकर सर, मैंने माननीय सदस्यों को पहले ही सूचित किया है कि इन 64 इण्डस्ट्रीज में से कुछेक के अगेन्सट तो कोर्ट केसिज हैं। कोर्ट केसिज में स्टे मिल जाता है जो काफी समय बाद ही वैकेट होताहै। कुछ केसिज ऐसे हैं जो आर्बिट्रेटर के सामने आर्बिट्रेशन के लिये पैंडिंग हैं।

आर्बिट्रेटर चूंकि बिजली बोर्ड का ही औफिसर होता है इसलिये ऐसे केसिज जल्दी ही डिस्पोज औफ हो जाते हैं लेकिन कोर्ट केसिज लम्बे चलते हैं।

श्री मंगल सैनः माननीय स्पीकर सर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई नोबल पर्सन और देशभक्त ऐसे भी हैं जिन के बिल 1976 से बकाया पड़े हैं, यदि हां तो क्या उस नोबल फर्म या देश भक्त का नाम बताने की कृपा करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इन 64 डिफाल्टर्ज में से नम्बर 25 पर जो फर्म है वह 97,75 से डिफाल्टर है और प्राईवेट होउसिज के नम्बर 20 पर है। जो राम किशन जी हैं इनका बकाया 20 मई, 1976 से पैंडिंग पड़ा है।

डा० बृज मोहनः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि डिफाल्टर्ज की जो यह लिस्ट है क्या इसमें कोई भूतपूर्व विधायक या भूतपूर्व मन्त्री भी हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि यह जो लिस्ट है इसमें फैक्टरी का नाम ही दिया हुआ हैं। किस फैक्टरी में कौन–कौन मालिक या हिस्सेदार हैं इस बारे में कोई जिक्र नही है।

कामरेड हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसे ऐग्रीकल्चर सैक्टर

में डिफाल्टर होने पर बिजली के कनैक्शन काट दिए जाते हैं इस लिस्ट में कितने ऐसे केसिज हैं जिनकी डिफाल्टर्ज होने के कारण सप्लाई काट दी गई है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, सभी के कनैक्शन्ज कन्टीन्यू, कर रहै हैं क्योंकि कोर्ट से स्टे हो जाता है। कई बार हम सप्लाई काट भी देते हैं परन्तु ये लोग कोर्ट से स्टे ले आते हैं।

ई० जगपाल सिंह चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपुके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सारी किस्म के कन्जयूमर्ज, सरकारी और गैर सरकारी दोनों को मिला कर, के०पर कितने करोड़ रुपये की रकम बकाया है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः 31–12–1988 तक टोटल रकम जो कन्जयूमर्ज की तरफ बकाया थी वह 105 करोड़ 89 लाख 23 हजार है।

10.00 बजे

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि मैसर्ज भारत स्टील ट्यूबज की तरफ सात लाख से अधिक की राशि बकाया है। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सात लाख रुपया कितने दिनों का बिल है और यह सात लाख रुपया बकाया होने तक कनैक्शन काट दिया गया था या नहीं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः मैंने अभी बताया था कि जुलाई सन् 1987 से कोर्ट में केस पैंडिंग है। यह. उससे पहले का बिल पैंडिंग होगा। होत क्या है कि ज्यों ही हम बिल भेजते हैं वे फौरन स्टे ले लेते हैं, कोई देरी नहीं लगाते।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि भानू इण्डस्ट्री की तरफ जो बड़ी भारी रकम बकाया है, वह कितनी बाकी रही है और उसकी क्या वसूली हुई है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः उसनें भी स्टे ले लिया। हमने उसका कनैक्शन डिस–कनैक्ट कर दिया था लेकिन कोर्ट ने रेस्टोरेशन के आर्डर कर दिये। स्टे हो गया, हमें दुबारा से कनैक्शन देना पड़ा। भानू इण्डस्ट्री की तरफ कितनी बकाया रकम है। I cannot tell the same off hand.

श्री शिव प्रशादः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा बिजली बोर्ड ने 105 करोड़ के करीब रुपया लेना है लेकिन बोर्ड ने देना कितना है क्या मंत्री जी वह भी बतायेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः बिजली बोर्ड ने 105 करोड़ के करीब लेना है यह मैंने बताया है। इसमें डिफाल्टर गवर्नमैंट भी हैं। जैसे एम० आई० टी० सी० की तरफ 6 करोड़ 26 लाख रुपया बिजली बोर्ड का बकाया है। इरीगेशन विभाग की तरफ बिजली बोर्ड का 70 करोड़ के करीब रुपया बकाया है, पंचायत और म्यूनिसिपल

कमेटीज से 2 करोड़ 65 लाख, हरियाणा कौनकास्ट से 2 करोड़ 41 लाख रुपया लेना है। इस प्रकार से डिफाल्टर्ज गवर्नमैंट के डिपार्टमैट्स भी हैं।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि 105 करोड़ 89 लाख रुपया बिजली बोर्ड का बकाया है। कुछ इन्डस्ट्रीज अन्डर लिक्वी– डेशन हैं और उनकी तरफ जो अमाउन्ट है वह डैड अमाउन्ट कहलाता है। उदाहरण के तौर पर दादरी सीमेन्ट फैक्टरी की तरफ एक करोड़ से अधिक का अमाउन्ट बकाया है। डैड अमाउन्ट रिकवरेबल नहीं होता। क्या इस बकाया अमाउन्ट में वह डैड अमाउन्ट भी शामिल है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः वह इसमें शामिल नहीं है।

श्री भाग मलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिन फैक्टरीज की तरफ बिजली बोर्ड का पैसा बकाया है उनमें बिग, मीडियम और स्माल इन्डस्ट्रीज कितनी है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः बिग, मीडियम और स्माल इन्डस्ट्रीज कितनी हैं, ऐसी लिस्ट इस वक्त मेरे पास नहीं है। यह लिस्ट इन्डस्ट्रीज डिपार्टमैंट से उपलब्ध होगी लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि इंडस्ट्रीयल सैक्टर की तरफ 16 करोड़ 11 लाख 64 हजार रुपया बाकी है।

श्री कुन्दन लाल भाटिया: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि जब किसी केस में कोर्ट से स्टे मिल जाता है तो उसके बाद बिजली के बिल की पेमैन्ट होती है या नहीं?

श्री वीरेन्द्र सिंह: ऐसे केसिज में कोर्ट की तरफ से आर्डर हो जाते हैं कि इसका कनैक्शन रैस्टोर कर दें और पिछले बिल के लिये मुकदमा लड़े। फरदर बिलिंग पार्टी की तरफ होती रहती है, केवल डिसप्युटिड अमाउन्ट का केस चलता है।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि रूल्ज में कोई अमैंडमैंट करके रिकवरी को इफैक्टिव नहीं किया जा सकता?

श्री वीरेन्द्र सिंह: मैंने अभी यहां हाउस में बताया था कि हम इसी सत में बिल ले कर आ रहैं हैं लेकिन उस बिल को हमें गवर्नमैंट आफ इंडिया के पास भेजना पड़ेगा। इसमें प्रैजीडेन्शियल असैन्ट जरुरी है क्योंकि मेन ऐक्ट गवर्नमैंट औफ इंडिया का पास किया हुआ है।

ई० जगपाल सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इरीगेशन एंड पावर मंत्री जी ने बताया है कि लगभग 105 करोड़ रुपये के जो टोटल एरियर्ज हैं, उसमें 90 फीसदी डिफाल्टर्ज गवर्नमैंट डिपार्टमैट्स या सैमी–गवर्नमैट डिपार्टमैंट्स हैं। क्या मन्त्री जी बताएंगे कि उनके खिलाफ भी कोई केस दायर किये गये हैं। अगर

नहीं किए गए हैं तो प्राइवेट पार्टीज के साथ यह डिस्क्रिमीनेशन क्यों है।

Shri Verender Singh : Speaker Sir, when the Irrigation Minister is defaulter towards the power Minister तो कौन किस पर मुकदमा करेगा?

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने यह बताया है कि लगभग 105 करोड़ रुपया बिजली बोर्ड का कंज्यूमर्ज की तरफ बकाया है.। इससे यह दिखायी देता है कि बिजली बोर्ड का जो इतना घाटा है, वह डिफाल्टर्ज की वजह से है। इसके अलावा बिजली की चोरी भी होती है लेकिन टैरिफ बढ़ाकर लोगों पर बोझा बढ़ाया जाता है। क्या मंत्री जी बतायेगे कि टैरिफ को न बढ़ाकर रिकवरी करने के लिये कोई इफैक्टिव सिस्टम बनाया जायेगा?

श्री वीरेन्द्र सिंहः इसमें बिजली के टैरिफ का कहां से सवाल आ गया?

श्री अध्यक्षः कामरेड साहब, यह सवाल रैलेवैन्ट नहीं है, आप कृपया बैठिए।

Anti-Corruption Board

792. Pandit Vasu Dev Sharma & Shri Hira Nand Arya : Will the Chief Minister be pleased to refer to the reply to Starred Question No. 549 answered on 8-4-1988 and to state the outcome of the investigation of each of 18 cases

involving corruption detected by the Anti-Corruption Board, together-with the action taken there-on ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : Out of 18 cases involving corruption detected by the Anti-Corruption Board, in ,13 cases untraced reports have been submitted to the Courts, in one case the challan has been put in the court and the remaining 4 cases are still under investigation.

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो केसिज अन–ट्रेस्ड डिक्लेयर किये हैं, वे ऐन्टी करप्शन बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर अनट्रेस्ड डिक्लेयर किये हैं या इसका कोई दूसरा कारण था? दूसरे, जिनका चालान किया गया है, क्या ये उनके अलग–अलग से नाम बताने की कृपा करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः जो केसिज अन–ट्रेस्ड हैं, उनमें suffiicient evidence was not available. चालान किया गया केस केवल एक है जिसका एफ०आई० आर० नं० 33 है। उसमें एक्यूज्ड रणजीत सिंह और लछमन हैं and the case has been registered under sections 264, 265, 267, 420 and 120-B I.P.C. at Police Station Sadar Thanesar.

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि ऐवीडैन्स के न मिलने की वजह से इतने सारे केसिज को अन–ट्रेस्ड डिक्लेयर किया गया। जब बोर्ड बड़ी मुस्तैदी से किसी पर जांच करने के लिये केस बनाता है तो उस में

ऐवीडैन्स होनी ही चाहिये। लगता है ये केसिज जान–बूझकर गलत बनाये गये थे या किसी सरकारी दबाव की वजह से ये अन–ट्रेस्ड डिक्लेयर हुए हैं। क्या मन्त्री जी उनके नाम बताने की कृपा करेंगे जिनके केसिज अन–ट्रेस्ड डिक्लेयर हुए हैं ?ऋ

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह जी को यह बताना चाहता हूं कि जो केसिज अन–ट्रेस्ड डिक्लेयर किये है, वे ऐवीडैन्स के सफिशिएट न होने के कारण ही किये है। किसी के दबाव का तो कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। ऐन्टी करप्शन बोर्ड मौजूदा सरकार ने बनाया है। इनके टाईम में तो यह था ही नहीं। यह इसलिये बनाया है कि चौधरी देवी लाल जी का संघर्ष में जो स्लोगन चा वह स्टार्ट ही इस तरह से 'होता था कि भ्रष्टाचार बन्द और बिजली पानी का प्रबन्ध। (व्यवधान) इनका स्लोगन उलटा था कि भ्रष्टाचार का प्रबन्ध और बिजली पानी बन्द। अध्यक्ष महोदय, केसिज जो अन–ट्रेस्ड डिक्लेयर हुए हैं उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम बताना ठीक नहीं है। क्योंकि विधान सभा में न होने के कारण they cannot defend themselves.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, हमारे संसदीय कार्य मन्त्री महोदय ने बजा फरमाया है कि इस सांझा मोर्चे की सरकार का यह संकल्प था कि भ्रष्टाचार बन्द और बिजली पानी का प्रबन्ध किया जाए। बिजली पानी का प्रबन्ध तो इन्होंने कर दिया और भ्रष्टाचार का भी करने लग रहैं हैं। लेकिन स्पीकर साहब, मैं

आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि बड़ी मेहनत से तो वे लोग जाल में फंसे थे लेकिन ऐवीडैन्स सफिशिएट न होने के कारण वे बच निकलेंगे। क्या ये कोई ऐसा प्रबन्ध करेंगे जिससे उन पर पक्का ही हाथ डल सके और ऐवीडैन्स सफिशिएंट न होने के आधार पर केसिज अन– ट्रेस्ड नही जाने देंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः हाथ तो पक्का ही डाला जाता है लेंकिन जब accused cannot be linked with evidence तो बात रह जाती है।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने तेरह केसिज अन–ट्रेस्ड बताए हैं और कहा है कि उनका नाम बताना जनहित में नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, जब एफ० आई० आर० दर्ज हो गई तो वह पब्लिक डौकूमैंट बन जाता है 'और नाम बताने में कोई हर्ज रही होता। इसलिये क्या मन्त्री महोदय इन लोगों के नाम बताने की कृपा करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, कई दफा जब एक० आई० आर० दर्ज हो जाती है तो इन्वैस्टीगेशन में एक ऐक्यूज्ड का नाम छोड़ दिया जाता है और कई बार दूसरे नाम और दर्ज कर दिए जाते हैं। इसलिये नाम बताना जनहित में नहीं है।

कामरेड हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया है कि कई बार किसी ऐक्यूज्ड का नाम निकाल दिया जाता है और कई बार एफ० आई० आर० दर्ज होते के बाद और नाम आ

जाते हैं। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इसमें नाम बताने में क्या हर्ज हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, केवल हर्ज यह है कि वे लोग जिनका नाम एफ० आई० आर० में दर्ज है वे विधान समा में नहीं हैं और they cannot protect themselves from the criticism.

श्री हीरा नन्द आर्यः क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इनमें क्या कोई मिलावट के केसिज भीं हैं ओर क्या कोई बौर्ड या काप्रोरेशन भी इंवौल्वड है ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, इनमें मिलावट के केसिज भी हो सकते हैं क्योंकि कई केसिज असैनशियल कमोडीटीज ऐक्ट के तहत दर्ज हैं और कुछ प्रिवैन्शन औफ करप्शन ऐक्ट के तहत दर्ज हैं। जो केसिज असैनशियल कमोडीटीज ऐक्ट के तहत दर्ज हैं उनमें मिलावट के केस भी हो सकते हैं।

श्री दुर्गा दत्त अत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो ऐन्टी करप्शन बोर्ड बनाया था वह तो कानून से परिचित था। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो केसिज अनट्रेस्ड चले गए वे किस कमी की वजह से चले गए?

Mr. Speaker : There can be so many reasons for this. There may also be insufficient evidence.

श्री दुर्गा दत्त अत्री: क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इसका मतलब यह तो नहीं है कि कहीं उनके खिलाफ झूठे केस बनाकर उनको पकड़ लिया गया हो?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, कई दफा सोर्स की बिना पर केस अनट्रेस्ड रह जाते हैं। एन्टी करप्शन बोर्ड के पास कोई कम्पलेन्ट आ गई, उन्होंने केस दर्ज कर लिया, कोई खबर आ गई केस दर्ज कर लिया और मेरे जैसा और आप जैसा आदमी बता गया तो केस दर्ज कर लिया लेकिन जब इन्वैस्टीगेशन करते हैं तो इन्वैस्टीगशन में ऐवीडैसं सफीशिएन्ट नहीं मिलती और केस अनट्रेस्ड रह जाता है।

डा० बृज मोहन: अध्यक्ष महोदय, जो तेरह केसिज अनट्रेस्ड पाए गए इनके बारे में शिकायत आई होंगी और वे शिकायत सही नहीं पाई गई। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कोई ऐक्शन लिया जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह: यह कोई जरूरी नहीं है कि शिकायत सही नहीं पाई गई। इसका कारण यह हो सकता है कि ऐवीडैन्स अवेलेबल नहीं थी।

श्री हीरा नन्द आर्य: क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये शिकायतें किन किन विभागों से सम्बन्धित थीं?

Mr. Speaker : How is it possible to give this

information offhand? यह तो सब विभागों से सम्बन्धित होगी।

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, विभाग तो इसमें भिन्न भिन्न हैं। सभी विभाग तो नहीं हैं। लेकिन कई विभागों के खिलाफ शिकायतें हैं जैसे ऐक्साइज एण्ड टैक्सेशन और फूड एण्ड सिविल सप्लाइज डिपार्टमैंट्स।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, ये केसिज गवाही की कमी के कारण नहीं चल सके। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार क्या कदम उठा रही है जिससे भविष्य में भ्रष्टाचार खत्म हो और जो चौधरी देवी लाल ने भ्रष्टाचार बन्द करने का नारा दिया है, इसको सुचारू रूप से पूरा किया जा सके?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से कई ऐजेन्सियां हैं जोकि भ्रष्टाचार को रोकने का काम करती हैं। सरकार ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटती है। भ्रष्ट लोगों केलिए ऐन्टी करप्शन बोर्ड है। सरकार के पास विजीलैन्स डिपार्टमैंट है। कई बार सी० आई० डी० को इंक्वायरी के लिए केसिज दिए जाते हैं। सरकार के पास पुलिस भी है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी ऐजेन्सीज भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जुटी हुई हैं। यह तो बहुत पुरानी बीमारी है। ये कांग्रेस के लोग इसको फैलाकर गए थे। आहिस्ता–आहिस्ता इसको सुधारा जा सकेगा।

श्री योगेश चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि कुछ केसिज में ऐवीडैन्सिज नहीं मिल सकीं लेकिन जो अधिकारी भ्रष्टाचार के केसिज से सम्बन्धित थे क्या उनके खिलाफ सरकार ने विभागीय कार्यवाही करने की कोई प्रोपोजल बनायी है ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सके और उन्हैं सजा दी जा सके?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, कई केसिज में रूल 7 और 8 के तहत विभागीय कार्यवाही रिकमैन्ड की गयी है और बाकायदा कार्यवाही चल रही

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने फरमाया कि भ्रष्टाचार बन्द किया जाएगा, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को सख्ती के साथ कुचल दिया जाएगा और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन को अवश्य ही सजा दी जाएगी। लेकिन मन्त्री जी आपके बोर्ड ने छापे मारे परन्तु उसके बावजूद भी कई भ्रष्ट अधिकारी बच निकले। क्या भविष्य में आप कोई ऐसे पग उठायेंगे जिससे भ्रष्ट आदमी किसी प्रकार से बच न निकले और ऐवीडैन्सिज भी मिल जाएं?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, डाक्टर मंगल सैन जी ने ताजा ताजा ला किया है और मैं इनका ध्यान काडीनल प्रिंसीपल औफ ला की तरफ दिलाता हूं जिसका भाव है कि 100 गुनाहगारों को तो बेशक छोड़ दिया जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा न दी

जाए। हमें रूल आफ ला जिस तरह इजाजत देता है उसके अनुसार ही हम चल रहैं हैं।

Construction of houses under Indira Awaas Yojana

***825. Shri Bhag Mal :** Will the Minister for development and Panchayats be pleased to state—

(a) the villagewise number of houses constructed under the Indira Awaas Yojana during the year 1981-82 to-date, together with the estimated cost of each house ; and

(b) the number of houses, out of those referred to in part (a) above, which have been occupied by the allot-tees so far ?

विकास मन्त्री (श्री हुक्म सिंह):

(ए)

तथा विवरणी सदन के पटल पर रखी जाती है।

(बी)

STATEMENT

DISTRICT AMBALA

Sr. No.	Village where houses constructed	No. of Houses constructed	No. of houses occupied.	

1.	Tobha	34	33	
2.	Samlehri	30	30	The estimated cost of each house till 1987-88 was Rs. 9000-/ and thereafter it was raised to Rs. 10,2001– for all districts.
3.	Tejli	20	20	
4.	Aziz pur	11	11	
5.	Chorahi	20	—	
6.	Mandhore	22	22	
7.	Udepur	16	16	
8.	Milk Khas	22	22	
9.	Manglore	24	—	
10.	Gharauli	20	18	
11.	Ismail Pur	33	33	
12.	Bhaunli	12	12	
13.	Bora Khera	14	14	
14.	Manak Tabra	16	16	
15.	Sambalkha	20	20	
16.	Alipur	20	20	
17.	Bhagwanpur	20	—	
18.	Malikpur Khadar	20	--	

19.	Kurali	20	—	
20.	Miyanpur	20	20	
21.	Ber Kheri	16	—	
22.	Binjal Pur	20	—	
23.	Ganauli	10	—	
24.	Bahadurpur	20	—	
		480	307	

DISTRICT BHIWANI

Sr. No.	Village where houses constructed	No. of Ho uses constructed	No. of houses occupied.
1.	Bond Kalan	46	46
2.	Tigrana	20	20
3.	Bamala	20	20
4.	Kairu	20	20
5.	Lohani	33	28
6.	Sungarpur	12	12
7.	Alampur	20	20

8.	Nimariwali	20	
9.	Chaiher Khurd	20	
10.	Barwa	20	
11.	Dag Kalan	20	
12.	Modi	20	
13.	Chandbass	22	
14.	Uket Khera	20	
		313	166

DISTRICT FARIDABAD

Sr. No.	Village where houses constructed	No. of Ho uses constructed	No. of houses occupied.
1.	Bhankri	20	20
2.	Pali	20	—
3.	Ladyiarpur	20	12
4.	Mujheri	40	—
5.	Ghagot	20	20
6.	Teekri Brahaman	28	—

7.	Mitrol	40	40
8.	Pinger	20	--
9.	Gehlab	31	31
10.	Kot	47	40
		286	163

DISTRICT GURGAON

Sr. No.	Village where houses constructed	No. of Ho uses constructed	No. of houses occupied.
1.	Shahpur Nangli	20	20
2.	Pataun Udaipuri	20	20
3.	Jhund Srai	20	20
4.	Khandewla	20	20
5.	Kherla	20	20
6.	Bichore	20	
7.	Jharsa	33	
8.	Khera Khalilpur	20	
9.	Indri	33	
10.	Singar	20	

		226	100

DISTRICT HISAR

Sr. No.	Village where houses constructed	No. of Ho uses constructed	No. of houses occupied.
1.	Balawas	34	34
2.	Jakhod Khera	34	34
3.	Jamalpur shekhan	34	34
4.	Siswal	20	20
5.	Adampur	31	31
6.	Dhani Thakriyan	25	25
7.	Puthi Mangal Khan	21	21
8.	Puthi Samain	46	46
9.	Kapro	20	20
10.	Sulkhani	23	23
11.	Sewani Bolan	23	23
12.	Kamoli	23	23
13.	Bansinga	20	-
14.	Gunjar	18	18

15.	Bhiwani Bohila	18	18
16.	Kheri Roze	18	18
17.	Uklana	18	18
18.	Rehanwali	18	18
19.	Chaundrawal	18	18
20.	Bangram	17	17
21.	Nangpur	17	17
22.	Burak	15	
23.	Kharakpunia	17	
24.	Jandali Khurd	6	
25.	Mahomadpur sotar	14	14
		558	490

DISTRICT JIND

Sr. No.	Village where houses constructed	No. of Ho uses constructed	No. of houses occupied.
1.	Lajawana Kalan	22	22
2.	Rohera Majra	22	22
3.	Muawana	22	22

4.	Rajond	22	22
5.	Morkhi	22	22
6.	Phulian Kalan	22	22
7.	Kandela	22	22
8.	Bikhewala	20	20
9.	Batta	20	20
10.	Jhanj Kalan	20	20
11.	Ghorian	20	4
12.	Dalamwala	22	22
13.	Pajukalan	22	
14.	Gatouli	22	
15.	Rohera	22	
16.	Kalaran	44	
17.	Amargarh	22	
		388	236

DISTRICT KARNAL

Sr. No.	Village where houses constructed	No. of Ho uses constructed	No. of houses occupied.

1.	Mundh	20	20
2.	Barana	60	60
3.	Chand Samand	20	20
4.	Chulkana	20	.20
5.	Geela Khurd	20	20
6.	Sambli	20	20
7.	Sambhi	20	20
8.	Kavi	19	19
9.	Salarpura	20	
10.	Kaukhani	20	20
11.	Pardhana	19	19
12.	Garhi Khazoor	20	20
13.	Rajapur	22	22
14.	Ardana	23	-
		323	280

DISTRICT KURUKSHETRA

Sr. No.	Village where houses constructed	No. of Ho uses constructed	No. of houses occupied.

1.	Shanti Nagar	20	20
2.	Rarhera	20	20
3.	Saunti	20	20
4.	Deora	20	20
5.	Jotisar	20	20
6.	Cha mu Kalan	20	20
7.	Murtzapur	20	20
8.	Kakheri	20	
9.	Rasina	20	—
10.	Ma hwakheri	20	-
11.	Khajuri	20	
		220	140

DISTRICT NARNAUL

Sr. No.	Village where houses constructed	No. of Ho uses constructed	No. of houses occupied.
1.	Blaha Kalan	16	16
2.	Nangal Kalia	20	20
3.	Turkiyawas	20	20

4.	Odhi	20	20
5.	Madhogarh	20	20
6.	Kheri	20	20
7.	Palahawas	20	20
8.	Jakhni	20	20
9.	Khatoti Khurd	20	20
10.	Sayana	20	20
11.	Sangwari	20	20
12.	Bhagthala	20	20
		236	236

DISTRICT ROHTAK

Sr. No.	Village where houses constructed	No. of Ho uses constructed	No. of houses occupied.
1.	Bhambhewa	20	20
2.	Chhara	20	20
3.	Silana	20	20
4.	Chamarian	20	20
5.	Shayam Nagar	24	24

6.	Aakedi Madanpur	20	20
7.	Bhainsaru Kalan	20	20
8.	Sundana	19	19
9.	Bahu Akbarpur	18	18
10.	Safipur	30	30
11.	Patsani	24	24
12.	Bhaini Bhairon	20	20
13.	Dulhera	18	18
14.	Gamri	20	20
15.	Ismaila B-II	20	20
16.	Khungai	20	20
17.	Kharkara	20	
18.	Saimpal	20	
19.	Paharipur	20	
		393	333

DISTRICT SIRSA

Sr. No.	Village where houses constructed	No. of Ho uses constructed	No. of houses occupied.

1.	Bapp	20	20
2.	Mehana Khera	16	16
3.	Bahia	20	20
4.	Khari Suera	20	20
5.	Chaharwala	20	
6.	Nathusari Kalan	20	20
7.	Jodhakan	20	
8.	Dhotter	20	20
9.	Chamal	20	20
10.	Kharia	18	18
11.	Khuian Malkana	20	20
12.	Masitan	20	20
13.	Shergarh	20	20
		254	214

DISTRICT SONIPAT

Sr. No.	Village where houses constructed	No. of Ho uses constructed	No. of houses occupied.
1.	Ghar Shajhanpur	15	15

2.	Shahpur Turak		
3.	Badmalik	19	19
4.	Bindroli	20	20
5.	Palri Kalan		
6.	Bhigan	40	
7.	Dadsoli	25	
8.	Datouli		
9.	Sisana	14	14
10.	Silana	20	
11.	Kanwali		
12.	Mahra	20	20
13.	Chhetera	20	20
14.	Kohla	20	
15.	Thaska	20	20
16.	Ahulana	20	
17.	Bhanderi		
		253	128

श्री भाग मलः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने अम्बाला जिला की जो मकानों की स्टेटमैंट दी है उस के सीरियल नंग 5

और 9 से ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर लोगों ने मकान आकुपाई नहीं किये हैं। क्या मन्त्री जी बताएंगे कि इसके क्या कारण हैं?

श्री हुकम सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह बात इनकी सही है कि हरिजनों के जो मकान बनायें गये हैं उन में से कुछ हाउसिज आकुपाई नहीं किये गये हैं। हमने इस काम के लिए एक अफसर की डयूटी लगायी है कि वह गांव गांव जाकर के यह देखे कि क्यों ये मकान आकुपाई नहीं हुए हैं।

श्री रत्न लाल कटारियाः अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय उप मुख्य मन्त्री महोदय ने स्वयं हाउस के अन्दर यह माना है कि जो हरिजनों के लिये इन्दिरा आवास योजना के तहत कालोनीज बनायी गई हैं, वे मनुष्यों के रहने के काबिल नहीं हैं। सरकार की पालिसी के तहत अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को सरकार द्वारा 5 हजार रुपये की सहायता दी जाती है लेकिन डी० सी० व एस० डी० एम० द्वारा लो इन्कम ग्रुपस स्कीम के तहत लोगों को मकान बनाने के लिये 10 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। इस लिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि अगर सरकार स्वयं इन दोनों रकमों को इकट्ठा करके एक अच्छा मकान बनाकर दे तो वह ज्यादा बेहतर रहैंगा और वह लोगों के रहने के काबिल भी होगा। क्या सरकार इस तरह करने का विचार रखती है?

श्री हुकम सिंहः अध्यक्ष महोदय, सुझाव तो माननीय सदस्य का बहुत अच्छा है लेकिन हमें इस काम के लिये सारा रुपया भारत सरकार से मिलता है। हमें उनकी गाईड लाईनज के अनुसार ही मकान बनाने पड़ते है। यह ठीक है कि अमांउट थोड़ा है जिस से एक अच्छा मकान नहीं बन सकता लेकिन हमारी सरकार समाज कल्याण विभाग द्वारा इस परपज के लिये हरिजनों को 5000 रुपया अनुदान के रूप में देती है। वह पैसा हम इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमें पैसा भारत सरकार से आयेगा हमें उन्हीं की गाईड लाईनज के मुताबिक काम करना पड़ेगा।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, जो मकान आकुपाई नहीं हुए हैं उनकी संख्या मन्त्री महोदय ने 1237 बतायी है। साथ में यह भी कहा है कि इस काम को देखने के लिये सरकार ने एक अधिकारी भी नियुक्त किया है जो यह देखेगा कि मकान आकुपाई क्यों नही किये गये। क्या मन्त्री महोदय यह बताएंगे कि वह कौन सा अधिकारी है उनका शुभ नाम क्या है और कब तक उनको अपनी रिपोर्ट देने के लिये क्हा गया हैं?

श्री हुकम सिंहः अध्यक्ष महोदय, ज्वायंट डायरक्टर, श्री आर० डी० गर्ग इस काम को देखते हैं। हम ने उसकी डयूटी लगा रखी है कि वह किसी अफसर को इस काम के लिये नियुक्त करे। इसी काम के लिये ब्लौक लैवल पर भी हम एक कमेटी बना रहैं हैं जिसमें बी० डी० ओज० पंचायत अफसर, एस० डी० ओज० गांव

का सरपंच और एक हरिजन होगा जो औकुपेशन के बारे में अपनी ओर से सर्टीफिकेट देंगे लेकिन अभी तक वे सर्टीफिकेट हमारे पास नहीं आए हैं। अध्यक्ष महोदय, इस काम में बड़ी तेजी से कार्यवाही की जा रही है।

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, क्या मन्त्री जी बताएंगे कि उनके पास कोई शिकायत आई है कि हरिजनों की कालोनी गांव से अलग बनाई जा रही है और जो घर बनाकर दिया जा रहा है उसमें जगह बहुत थोड़ी सी है यानी एक कोठरी है और उसी में किचन वगैरह है। क्या यह भी ठीक है कि भारत सरकार की यह नीति हरिजनों को अलग रखने की हैं?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, ये मकान उसी जगह बनाए जाते हैं जहां हरिजनों को प्लौट मिले हुए हैं। ऐसी नीति नहीं है कि उनको अलग से रखा जाए। उनके प्लौटों पर ही मकान– बनते हैं।

श्री भाग मलः स्पीकर साहब, रम्बा में जो मकान बनाए गए हैं वे गांव से डेढ़ किलोमीटर दूर बनाए गए हैं। उनमें से एक भी मकान औकुपाई नहीं हुआ है। उनकी हालत रोज–बरोज खराब हो रही हैं। क्या सरकार उस कालोनी को बसीने का कोई इन्तजाम करेगी?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, पंचायतों ने हरिजनों को प्लौट दिए थे। जहां पंचायत को जमीन मिली वहां पर उसने प्लौट

काट कर दे दिए। जहां प्लौट हैं मकान तो वही बनेंगे, दूसरे की जमीन पर हम मकान कैसे बना सकते हैं?

श्री मुनी लालः स्पीकर साहब, मेरी कास्टीच्युऐंसी में बडथला गांव से बाहर जो कालोनी बनाई गई थी उसके मकान औकुपाई होने से पहले ही ढह चुके हैं। क्या मन्त्री जी बताएंगे कि उसके लिए संबंधित अफसरों को सजा दी जाएगी?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, महैंन्द्र प्रताप सिंह जी के राज में जब मकान बने थे तो उनमें मैटीरियल ठीक नहीं लगा था। इसलिए ढह गए होंगे। फिर भी जहां जहां से ऐसी कम्पलेंट्स आती हैं हम उनकी जांच करवाते हैं और अधिकारियों को सजा देते हैं।

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री जी ने बताया कि जहां हरिजनों को 4–4 या 8–8 मरले के प्लौट मिले हुए थे वहीं पर मकान बनाए गए हैं। क्या यह बात सही है कि वहां पर मकान न बना कर और जगह एक–दो कनाल जमीन में 30–40 मकान बनाए जाते हैं। ठीक है वह भी पंचायत की जमीन है लेकिन मकान असली प्लौटों पर नहीं बनाए जाते। क्या इसकी भी इंक्वायरी करवाऐने?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि पंचायत जो प्लौट हरिजनों को देती है उन्हीं पर मकान बनाते हैं, दूसरी जगह कैसे बना सकते हैं?

श्री रत्न लाल कटारियाः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आज से 50 वर्ष पहले पंडित जवाहर लाल नेहरु की पुस्तक 'प्रौमिजिज टू कीप'' तथा ''डिस्कवरी आफ इंडिया'' में यह लिखा है–

श्री अध्यक्षः कटारिया जी आप सवाल पूछें। पुस्तक में क्या लिखा है, इसका जिक्र न करें।

श्री रत्न लाल कटारियाः स्पीकर साहब, हमारे प्रधान मन्त्री 21वीं सदी में जाने की बात करते हैं। हमारी हरियाणा सरकार भी महसूस करती हैं कि जो मकान हरिजनों को दिए जा रहैं हैं, वे रहने के काबिल नहीं हैं। क्या सरकार ने इसके लिए मिस्टर क्लीन को कोई प्रोटैस्ट नोट भेजा है या अब भेजा जाएगा?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, नेहरु जी ने जो किताब लिखी वह तो मैंने पढ़ी नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो नारे थे, वे सारे झूठे हो गए। यह मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन् मकानों को बनाने के लिए शत प्रतिशत पैसा चूंकि भारत सरकार से आता है इसलिए ये मकान हमें भारत सरकार की गाईड लाईन्ज के मुताबिक ही बनाने पड़ते हैं, उससे बाहर हम नही जा सकते।

श्री मांगे रामः स्पीकर साहब, मेरे हल्के में 40 गांव हैं। उन गांवों में इन्दिरा आवास स्कीम के तहत कोई मकान नहीं बनाया गया। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मेरे हल्के के गांवों में भी इस स्कीम के तहत कोई मकान बनाए जाएंगे?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, ये मकान उन लोगों को बना कर दिया जाते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। इस बारे में सर्वे करवाया गया था। उससे यह पता लगा कि हरियाणा के अन्दर दो लाख ऐसे हरिजन हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। उन्हीं के लिए यह मकान बना कर दिए गए हैं।

सेठ लछमन दास बजाजः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि करनाल जिले में जो चमार खेड़ा और झटपुर गांव हैं और जिनमें हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं, क्या उन गांवों में भी ये मकान बनाए जाएंगे?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, ये मकान पिछड़ी जाति के लिए नहीं बनाए जा सकते क्योंकि यह स्कीम केवल हरिजनों के लिए ही है। अगर बजाज साहब के हल्के के गांव में ऐसे लोग रहते हैं जो. गरीबी रेखा से नीचे हैं तो वहां पर जरूर कालोनी बनाई जाएगी।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, पिछली सरकार के समय में इन मकानों कों बनाने में बहुत घटिया मैटीरियल इस्तेमाल किया गया है। मैं आपके. द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में कोई जांच करवाई गई थी, अगर जांच करवाई गई थी तो कितने कसूरवार लोगों को सजा दी गई? स्पीकर साहब, लोगों के मकान बनने थे और लोगों का ही पैसा उन मकानों को बनाने पर खर्च हुआ है। क्या मन्त्री जी बताएंगे

कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई जो पैसा खा गए और घटिया किस्म का मैटीरियल लगा दिया।

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, जिस गांव से ऐसी कोई कम्पलेंट आती है उस गांव की हम जांच करवाते हैं लेकिन अभी तक हमारे नोटिस में ऐसी कोई कम्पलेंट नहीं है। अगर माननीय सदस्य के नोटिस में ऐसा कोई गांव है जहां पर ऐसी कम्पलेटं है तो वह हमें लिख कर दे दें, हम उसकी जांच करवा लेंगे।

श्री दुर्गा दत्त अत्रीः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद इन 18 महीनों में इन्दिरा आवास स्कीम के तहत कितनी ऐसी कालोनीज बनाई गइं और जितने मकान बनाए गए क्या उन सभी मकानों का कब्जा लोगों को दे दिया गया है?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, यह सारा विवरण तो सदन के पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य उसको पढ़ लें।

श्री भाग मलः स्पीकर साहब, हमारे आदरणीय मुख्य मन्त्री जी बड़े दयालु हैं और इन्होंने हरिजनों को बसाने के लिए ठीक जगहैं दी है। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो पैसा भारत सरकार से इन मकानों को बनाने के लिए आ रहा है, क्या वह पैसा कर्जे के रूप में हरिजनों को दिया जाएगा

ताकि कुछ पैसा हरिजन लोग अपनी तरफ से मिला करके अच्छे मकान बना सकें?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, मैं पहले भी बता चुका हू कि यह पैसा भारत सरकार की तरफ से आता है और भारत सरकार की गाईड लाइन्स के मुताबिक ही हमें मकान बनाने पड़ते हैं, उससे बाहर हम नहीं जा सकते।

Power Houses at Chorkarba and Manjura

***883. Shri Risal Singh :** Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up Power Houses at Chorkarba and Manjura in District Karnal; if so, the time by which the above said Power Houses are likely to be set up?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह)ः नहीं।

श्री रिसाल सिंहः स्पीकर साहब, दोनों गांवों के लोग अपनी इच्छा से जमीन देने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी उस प्रस्ताव पर दोबारा विचार करके उसे मंजूर करने की कृपा करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने अपने मेन सवाल में दो गांवों का जिकर किया है। उनमें से एक गांव चोरकरबा है और इस गांव के पास ही एक गांव डाचर है जहां पर हम 33 के०वी० का सब–स्टेशन बनाने जा रहैं हैं जिससे इस गांव

चोरकरबा की भी प्रोब्लम हल हो जाएगी। इस सब स्टेशन को बनाने का काम अगस्त, 1989 में शुरू कर दिया जाएगा और एक साल के अन्दर काम कम्पलीट हो जाएगा। जहां तक माननीय सदस्य के दूसरे गांव मंजूरा का ताल्लुक है, जुण्डला में एक 32 के०वी० का सब स्टेशन बनाने का मामला विचाराधीन है। ज्यों ही वह सब स्टेशन कम्पलीट होगा इस गांव की प्रोब्लम भी हल हो जाएगी।

Mr. Speaker : Hon. Members, Question Hour is. over.

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, आज हाउस में आते समय हमारे दो माननीय सदस्यों श्री योगेश चन्द शर्मा और श्री सुरेन्द्र कुमार मदान के साथ पुलिस ने बड़ा मिसबिहैंव किया है। इनके यह बताने पर भी कि ये एम०एल०एज० हैं, वे सही ढंग से नहीं बोले और कहने लगे कि एम०एल०ए० कौन होता है। इस प्रकार के बहुत से अपशब्द उन्होंने माननीय सदस्यों को कहैं हैं। स्पीकर साहब, यह प्रिविलेज का मामला बनता है। इस मामले को आप प्रिविलेज कमेटी को भेजिए। इस बारे में मैंने एक ब्रीच औफ प्रिविलेज मोशन का नोटिस भी दिया है।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः स्पीकर साहब, हमारे बताने पर भी कि हम एम०एल०ए० हैं, उन्होंने हमारे साथ बड़ा मिसबिहैंव

किया है। इसलिए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। (शोर)

श्री अध्यक्षः डा० साहब, अभी–अभी एक दो मिनट पहले मुझे इस बारे में नोटिस मिला है। I will consider it and let the House know about it on Monday.

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, ये तो हमारे माननीय सदस्य हैं। इनके साथ अगर ऐसा हुआ है तो बड़ा गलत हुआ है। यहां पर यूनियन टैरेटरी की पुलिस ड्यूटी पर है। अगर वह इस तरह से व्यवहार करती है तो it is highly condemnable.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, इस मामले को प्रिविलेज कमेटी को दे दीजिए।

Mr. Speaker : Let me study it, I will not close my eyes.

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब, इनके साथ पुलिस ने ठीक व्यवहार नहीं किया क्योंकि उस समय मैं भी विधान सभा आ रहा था और इनकी गाड़ी पुलिस वालों ने रोकी हुई थी। मैं यह भी महसूस करता हूं कि पुलिस वालों का बिहैंवियर 'हमारे माननीय सदस्यों के साथ अप टू मार्क नहीं था।

Mr. Speaker : It is very sad and unfortunate.

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मेरा एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस था।

Mr. Speaker : That is under consideration

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने परसों कहा था कि मैटीरियल का सैम्पल ला कर उन्हें दिखाया जाए। मैं आज उस सैम्पल को लेकर आया हूं। (शोर)

श्री अध्यक्षः वह तो परसों के लिए कहा था, आज के लिए नहीं। यह कैसे पता लगेगा कि यह वही और सही सैम्पल है।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब, मौके पर मेरे साथ चलें और सैम्पल मिला कर देख लें।

Mr. Speaker : Harpal Singh ji, please take your seat. You can talk to the Minister in his office.

श्री रत्न लाल कटारियाः अध्यक्ष महोदय, इण्डियन ऐक्सप्रैस पेपर, बंबई के दफ्तर पर छापे मारे जा रहैं हैं। यह. प्रैस के साथ अन्याय है। मैंने इस संबंध में अपनी एक मोशन आपकी सेवा में भेजी थी, उसका क्या हुआ?

Mr. Speaker : That is under consideration.

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैंशन मोशन का नोटिस दिया था। केन्द्रीय सरकार के गुप्तचर हरियाणा में हरियाणा सरकार के खिलाफ कुछ षडयंत्र कर 'रहैं हैं ताकि यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सके। यह खबर अखबारों में छपी है। यह बहुत गम्भीर मामला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बारे में सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे ताकि

लोगों में जो गलत फहमी फैल गई है, वह दूर हो सके। हरियाणा की जनता ने इस सरकार को चुना है। इसलिए सरकार को इस बारे में तुरन्त अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः वह मैंने गवर्नमैंट के पास कुमैंट्स के लिए भेज दिया है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, आजकल पड़ौसी प्रदेश में बड़े खराब हालात है और कई बार यहां पर भी नाखुशगवार बात हो जाती है। इसलिए मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो सामान हाउस में लाये हैं, ये कैसे लाये और किस की इजाजत से लाये हैं? (शोर)

कामरेड हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मुझे परसों चूंकि सैम्पल ला कर दिखाने के लिए कहा गया था इसलिए मैं यह सैम्पल लाया हूं। (शोर)

श्री अध्यक्षः मैं भी यह सोच रहा हूं कि ये इसे लाये कैसे?

Shri Mangal Sein : It is a wrong practice, Sir.

Mr. Speaker : Yes, it is a wrong practice.

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, आपने भी इस सैम्पल को लाने के लिए कहा था।

श्री मंगल सैनः इससे तो स्पीकर साहब, ऐसा लगता है कि इनको चौक नहीं किया गया। It may lead to any disaster.

श्री कैलाश चन्द शर्माः स्पीकर साहब, मैंने भी कई दिनों से एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया हुआ है, उसका क्या हुआ?

Mr. Speaker : That has been sent to the Govt. for comments.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरे भी कई काल अटैन्शन मोशंज पैंडिंग हैं, उनका क्या हुआ।

श्री अध्यक्षः डा० साहब, आपका एक कालिंग अटैन्शन मोशन जो रिवाइज्ड पैन्शन के ऐरीयर्ज की पेमेंट लौंग टर्म सिक्योरिटी डिपौजिट में करने के कारण पैन्शनर्ज में पाई जाने वाली रिजैन्टमैंट संबंधी है, 13 तारीख को लगा हुआ है और दूसरा मोशन गवर्नमैंट को कुमैंट्स के लिए भेजा हुआ है।

श्री मंगल सैनः समालखा के पास बारात पर जो हमला हुआ था उस बारे जो नोटिस दिया था उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्षः वह गवर्नमैंट के पास कुमैंट्स के लिए भेजा हुआ है।

वर्ष 1989 – 90 के बजट पर सामान्य चर्चा

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, अब वर्ष 1989– 90 के बजट पर जनरल डिस्कशन रिज्यूम की जाएगी।

श्री कैलाश चन्द शर्मा (नारनौल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले आदरणीय उप–मुख्य मन्त्री जी को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं स्वीकार करते हुए जो कर रहित बजट प्रस्ताव पेश किए हैं, उसके लिए वे बधाई के पात हैं। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में जब से चौधरी देवी लाल की सरकार ने हरियाणा की बागडोर संभाली है, सारा देश इस बात को देख रहा है कि कई ऐसी योजनाएं इस सरकार ने स्वीकार की हैं जो कि आम गरीब जनता को लाभ पहुंचाने वाली है। यह बजट सारे देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि इतनी जन–कल्याण की योजनाएं लागू करने के बावजूद भी इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आदरणीय सिंचाई मन्त्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिला महैंन्द्रगढ़ वास्तव में सारे हरियाणा में एक ऐसा जिला है जहां पानी की काफी आवश्यकता है। वास्तव में यह जिला सूखे के प्रभाव में सबसे अधिक रहता है। जे०एल०एन० कैनाल पर पम्प हाउस तो बने हुए हैं परन्तु इन पम्प हाउसिज को बिजली के कनैक्शन नहीं मिले हैं जिससे पानी अप–लिफट हो सकता है। इस कारण नारनौल के एक बहुत बड़े हिस्से में नहर का पानी अभी तक नहीं पहुंच पाया है। (इस समय भी उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

उपाध्यक्ष महोदय जिन गांवों में नहर का पानी पहुंचता है उन गांवों के लोगों को पानी के कारण बड़ा आनन्द प्राप्त होता है। लेकिन जिन गांवों में पानी नहीं पहुंचा है उन गांवों के लोगों को स्वाभाविक रूप से कष्ट होता है। नारनौल के गोदाना, माखती, धोल आदि कुछ बड़े गांव हैं जहां पर पम्प हाउस तो बने हुए हैं लेकिन इन पम्प हाउसिज को बिजली के कनैक्शन्ज नही मिल पाए हैं। इस बजट में 93.95 करोड़ रुपए सिंचाई के लिए रखे गये हैं। मुझे आशा है कि इसका एक अच्छा हिस्सा पम्प हाउसिज में बिजली का प्रबन्ध करने के लिए लगाया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक लम्बे अर्से से हर राजनैतिक पार्टी ये वायदे करती रही है कि महैंन्द्रगढ़ जिले के कार्य करेंगे, बिजली का प्रबन्ध करेंगे, सिंचाई की व्यवस्था करेंगे लेकिन इस पिछड़े हुए जिले को०पर उठाने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए। मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस जिला को०पर उठाने की कोशिश की है। उपाध्यक्ष महोदय सबसे पहले मैं चौधरी देवी लाल और चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने महैंन्द्रगढ़ में पहला पौलिटैक्नीक खोला। उपाध्यक्ष महोदय, जिला महैंन्द्रगढ़ ऐसा क्षेत्र है जो कृषि पर आधारित है। यहां पर सिंचाई के लिए अधिकतर बरसात पर निर्भर रहना पड़ता है और कुछ जमीन के अन्दर ट्यूबवैल लगा कर भी सिंचाई की जाती रही है। पिछले 10 साल में भयंकर सूखे के कारण वाटर लैवल बहुत नीचे चला गया है और किसान के लिए जमीन से पानी प्राप्त करना एक भयंकर समस्या बन गयी है। वहां

का नौजवान बेकार हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, महैंन्द्रगढ़, नारनौल, अटेली, नांगल चौधरी जैसे क्षेत्रों में कोई भी बड़ी फैक्टरी नहीं है। जो कुछ बड़ी फैक्टरियां है, वे धारूहैंड़ा में हैं। धारूहैंड़ा जी०टी० रोड के साथ लगता है इसलिए बहुधा फैक्टरियां वही पर ही लगी हैं। पिछड़े हुए क्षेत्र में एक भी फैक्टरी ऐसी नहीं है जिसकी लागत एक करोड़ रुपए हो। वास्तव में महैंन्द्रगढ़ और नारनौल एरिया में बेरोजगार नौजवानों को काम देने के लिए मैं उप–मुख्य मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस क्षेत्र में कोई न कोई बड़ा उद्योग लगाने के लिए सरकार विचार करे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के मुताबिक 1962 में यहां पर एक लोहैं का कारखाना लगाने की योजना थी जिसके लिए सर्वे भी करवाया गया था। यहां लोहा मिलने की सम्भावना भी बहुत ज्यादा थी इसीलिए इस प्रोजैक्ट पर विचार भी किया, गया था। उपाध्यक्ष महोदय, अरावली पर्वत के एरिया में कलई का पत्थर, मिनरल्ज वगैरा मिलने की काफी सम्भावनाएं हैं और बड़े उद्योग वहां पर स्थापित किये जा सकते हैं। मैं यह अनुरोध करुंगा कि इस हल्के में ज्योलोजिकल सर्वे करवाया जाए ताकि 1962 में महैंन्द्रगढ़ में लोहैं का कारखाना लगाने की जो प्रपोजल थी और जिसे बाद में हिसार में शिफ्ट कर दिया गया था, वह कारखाना यहां पर लगाया जा सके। इसी प्रकार से जो कली का पत्थर है, चूने का पत्थर है, उसे आज हम दादरी सप्लाई करते हैं। मेरा निवेदन है कि उपरोक्त जगहों के आसपास सीमैन्ट की फैक्टरी सरकारी स्तर पर लगायी जाये। यह फैक्टरी कम कीमत पर लग सकती है और सीमैन्ट की

कौस्ट औफ प्रोडक्शन भी कम आयेगी। उस एरिया में नौजवान बेकार हैं और रा–मैटीरियल मिल जायगा। इसलिए उस क्षेत्र में फैक्टरी लगाने का फैसला अवश्य करना चाहिए। मैंने जो तीन–चार क्षेत्र बताये हैं, वे सारे पिछड़े हुए हैं। इसलिए यहां पर फैक्टरी लगाने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये वहां पर सन 1962 में कुछ शैड्ज बनवाये गए थे लेकिन वहां पर ठीक प्रकार से कोई भी फैक्टरी नहीं चल रही है। वहां पर फैक्टरी न चलने के अनेक कारण हैं। जब कोई नौजवान फैक्टरी लगाने के लिए आगे आता है तो बड़ी–बड़ी शर्तें लिखी होती हैं, बड़ी– बड़ी बातें लिखी होती हैं लेकिन जब वे फील्ड में आते हैं तो उन्हैं बडी–बडी कठिनाइयां आती हैं। ऐसे नौजवान कई बार फैक्टरी या शैड्ज छोड़ देते हैं। उन्हैं फैक्टरी लगाने से पहले कहा जाता है कि कुछ समय के बाद यानी दस साल के बाद हायर परचे ज पर शैड मि लेगा लेकिन जब वे अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब उद्योगपति या छोटा उद्योग चलाने वाला छोटा सा एक कमरा बना ले या अपनी आवश्यकता के अनुसार, काम की रिक्वायरमैट के अनुसार थोड़ी सी भी कन्स्ट्रक्शन कर ले तो उसी वक्त औफिसर्ज नोटिस दे देते है कि यह क्यों बनाया है? मेरा ख्याल है कि सन 1962 के बाद उनकी रिपेअर पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कली करने और मेन्टीनैन्स रखने की तो बात होती ही नही है। उन्हैं उत्साहित किये जाने की बजाये निरुत्साहित किया जाता है। ये शैड्ज वहां इसलिए बनाए गये थे कि इन्डस्ट्रीज को बढ़ावा देना है। उनकी ठीक मैन्टेनैन्स होनी '

चाहिए जो बेकार नौजवान फैक्टरी लगाने के लिए आते हैं, उनके लिए यह प्रयत्न होना चाहिए कि उनकी अधिक से अधिक सहायता की जाये। वे कालेज की पढ़ाई छोड़ कर आये हैं। वे बिजनैस की सारी बातें बारीकी से नहीं जानते। लेकिन उनके सहयोग की बजाए लैग्ग पुलिंग की बात होती है, उन्हैं तंग किया जाता है। व्यापार का काम कठिन है। इसमें हर व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। जिला महैंन्द्रगढ़ को यदि लाभ मिलेगा तो उस लाभ का हिस्सा महैंन्द्रगढ़ के सारे क्षेत्र को भी अवश्य मि लेगा। जहां बड़े उद्योग नहीं है, वे क्षेत्र विशेषकर नांगल चौधरी, अटैली और महैंन्द्रगढ़ उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में एक बात यह भीं कही गई है कि उचित मूल्य की दुकानें सारे हरियाणा प्रदेश में खोली जायेगी। वास्तव में यह बड़ी अच्छी बात है। सरकार चाहती है कि सारे प्रदेश में उचित मूल्य पर सामान मिले। गरीब लोगों को गांवों से दो किलोमीटर से अधिक दूर न जाना पड़े लेकिन हमारे सामने कुछ दिक्कतें हैं। इन दुकानों के बारे में मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। सरकार भ्रष्टाचार बन्द करने के लिए प्रयत्नशील रही है और आदरणीय मन्त्री जी ने भी कोशिश की है लेकिन ये जो कनज्यूमर्ज स्टोरज हैं, सस्ते दर की दुकानें हैं, इनके बारे में मैं आदरणीय उप–मुख्य मन्त्री को कहना चाहता हूं कि अनेक बार समाचारपत्रों में चर्चा चलने से इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। बार–बार समाचारपत्रो में विशेष आइटम्ज के बारे में आया है। कभी कम्बल का नाम दे कर कहा जाता है कि मार्किट में सस्ता है। वहां पर इतनी कीमत हैं और मार्किट में इतनी कीमत

है। इसी प्रकार से साबुन की बात है। वह भी मार्किट में सस्ता है और इन दुकानों पर महंगा मिल रहा है। उनकी कीमतों में बड़ा अन्तर दिखाया है। जो गांवों के आम भोले भाले लोग हैं उनके दिमाग में दूसरी दुकानों वाले यह बैठाना चाहते हैं कि जो ये सस्ते दर की दुकाने है इनकी कीमतों में बड़ा भारी अन्तर है। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि इस बढ़िया छवि वाली सरकार की पोजीशन खराब न हो। गलत अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। नारनौल में जो कन्जूयूमर स्टोर हैं, उसमें 70 हजार से०पर की दवाईयां है। उनकी डेट एक्सपायर हो गई है, आज तक उनके बारे में पता नहीं चला कि कौन जिम्मेदार है? किसी अधिकारी को डिप्यूट नहीं किया गया जो पता लगा सके कि किस की जिम्मेदारी है। आखिर उनकी डेट क्यों एक्सपायर हुई? उन्हैं समय पर क्यों नहीं बेचा गया? इसी प्रकार से कनज्यूमर स्टोर में डेढ़ लाख रुपये का कपड़ा०ंचे भाव पर खरीदा गया, वह कपड़ा भी पड़ा हुआ है, उसे खरीदने वाला कोई नहीं है। सारे कनज्यूमरर्ज स्टोर्ज घाटे में जा रहैं हैं जिसके कारण लोगों में बेचौनी पैदा हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बार बजट के अन्दर यह बात रखी गयी है कि गांव में पंचायतों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिये शराब की हर बोतल पर एक रुपए का हिस्सा मिलेगा। इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है क्योंकि एक बड़ी भारी समस्या थी कि पंचायतों के पास जरा सा भी पैसा नहीं था।

वह विकास कार्य नहीं कर सकती थीं। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से आदरणीय उप मुख्य मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में आज हमारे हरियाणा में पंचायतें कुछ नही कर रही हैं। पंचायतों 'का जैसा सिस्टम पिछले दिनों से चल रहा है, वास्तव में उसमें पंचायतों को बिल्कुल ही पंगु बना कर रख दिया गया है। यह देखा जाये कि क्या उसके पास गांव में कोई विकास कार्य करने के लिए अधिकार है। वास्तव में उसके पास विकास कार्य करने के लिये कोई अधिकार ही नहीं है। केवल सरपंच के पास एक जिम्मेवारी है कि वह जो काम गांव में हो रहा है उस को देखे कि वह ठीक हो रहा है या नहीं। ईंट कैसी लग रही है, सीमेंट ठीक लग रहा है या नहीं। परन्तु वह अगर गलत हो, उसको रोक नहीं सकता। जितना भी काम वहां पर डी० आर० डी० ए० या एन० आर० ई० पी० के माध्यम से होता है, उसमें अगर गलत काम हो जाये तो उसको फंसाने की जिम्मेवारी जरुर बनती है। उसका नाम जिम्मेदारी में जरूर डाल दिया जाता है। सारा काम बी० डी० ओश करता है। पंचायत के पास इस बारे में कोई अधिकार नहीं है। एक और बड़ी भारी समस्या है कि सरपंच चुनाव लड़ने के लिये बहुत पैसा खर्च करता है, चुनाव जीतने के लिये बहुत मेहनत करता है, बहुत हिम्मत करता है। परन्तु क्य वह सरपंच की कुर्सी पर जाकर बैठता है तो वह केवल नाममात्र का सरपंच रह जाता हैं। डी० सी० उसको सस्पैडं कर सकता है। यहां तक कि पंचों को भी बिना किसी उचित कारण बताये सस्पैडं कर दिया जाता है। इस प्रकार से हमारे जो प्रजातंत का ढांचा है, वह

कमजोर होता है। पंच और सरपंच यह महसूस करते हैं कि किसी प्रकार से बी० डी० ओ० को खुश रखो। किसी प्रकार से डी० सी० को खुश रखो। उसके दिमाग में गांव की सेवा की बात पीछे रह जाती है। उसके दिमाग में यह बात रह जाती है कि अगर उसका बी० डी० आ० नाराज हो गया तो वह दो आदमियों से इस किस्म की ऐप्लीकेशन लेकर, उसको सस्पैड करवा देगा। उसका सारा समय इन अफसरों को खुश करने में ही लग जाता है। मेरा इस बारे में एक सुझाव है। इस प्रकार की व्यवस्था की जाये कि चुने हुए सरपंच को सस्पैडं कोई अधिकारी कर सके, यह अधिकार नहीं होना चाहिये। कम से कम चुने हुए सरपंच के वोटरों का 10 प्रतिशत अगर ऐफीडैविट देता है तो उसकी जांच होने के बाद और उसको नोटिस देने के बाद ही उस पर यह कार्यवाही होनी चाहिये। यह मेरा सुझाव है ।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के मामले में यह सरकार बड़ी जागरूक है। मैं इस सरकार को बधाई देता हूं कि इसने कन्याओं की शिक्षा की ओर ध्यान दिया है। परन्तु शिक्षा के अन्दर जो महत्वपूर्ण भाग है, वह प्राथमिक शिक्षा का है। प्राइमरी शिक्षा एक बालक के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पहली से पांचवीं तक उस बालक की नींव का समय होता है। अगर उस समय उसकी नींव मजबूत न हो पाये तो वह बालक शिक्षा से भागने लगता है। वह०पर की कक्षा तक पहुंच ही नहीं पाता। यदि वह पहुंच भी जाता है तो वह नकल करने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से

पिछले 40 साल के कांग्रेस के राज के इतिहास में इस प्राइमरी शिक्षा की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया। मैं इस बारे में नारनौल की बात ही बता सकता हूं। वहां पर 10 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनमें 10 में से 10 में ही कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं है। कोई धर्मशाला में चल रहा है और कोई एक कमरे में चल रहा है। वहां पर ही पांच क्लासिज चल रही हैं। कोई नीम के पेड़ू के नीचे चल रहा है। उनके पास न टाट है और न ही दूसरी सुविधाएं हैं। हम शिक्षा पर काफी पैसा खर्च कर रहैं हैं। मेरा कहना यह है कि शिक्षा पर खर्च होने वाले पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करना चाहिये। अगर इन प्राथमिक स्कूलों में बिल्डिंग हो, इनमें टाटों पर बैठने के लिये व्यवस्था हो, दूसरी सारी व्यवस्था ठीक हो, एक कमरे की जगह हरेक क्लास के लिये अलग से कमरा हो और वहां का वातावरण ठीक हो तभी असली मायनों में शिक्षा की प्रगति हो सकती है। तभी हम बच्चों का चरित्र निर्माण कर सकते हैं। इसलिये मेरा कहना यह है कि प्राथमिक शिक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपने आदरणीय उप मुख्य मन्त्री, श्री बनारसी दास गुप्ता जी और मुख्य मंत्री, चौधरी देवी लाल जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने यह जो बजट रखा है, यह बड़ा ही उपयोगी है और मैं समझता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं, उन को ध्यान में रखते हुए ये हमारे पिछड़े हुए इलाके का विशेष ध्यान रखेंगे।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महाराजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, कल से बजट पर चर्चा चल रही है।

श्री उपाध्यक्षः आप कितना टाईम लेगे?

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः आप मुझे तीस मिनट दे दें।

श्री उपाध्यक्षः आप दस मिनट मैं अपनी बात समाप्त करु लें।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः उपाध्यक्ष महोदय दस मिनट तो कम हैं।

उप मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी सवा घंटा चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः महैंन्द्र प्रताप जी, आप पन्द्रह मिनट में अपना भाषण समाप्त कर देना।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा करते हुए मेरे साथी मैम्बर्ज ने अपने–अपने विचार रखे हैं। बजट में जैसा कि जाहिरा तौर पर नजर आता है कोई कर नही लगाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर कर लगाने की बात को देखा जाए तो इस वक्त कर लगाने की कोई जरूरत भी नहीं थी। डायरैक्ट और इनडायरैक्ट तरीके से कर पहले ही लगा दिये गए हैं। बिजली की सिक्योरिटी, बिजली का टैरिफ और बसों के

किराये आदि में जो बढ़ौत्तरी की गई है, वह सब मिलाकर तकरीबन तीन सौ करोड़ रुपए के लगभग पहुंच जाते हैं।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री धीर पाल सिंह): क्या आप बंसी लाल के आकड़े दे रहें हैं? (शोर एवं व्यवधान)।

श्री बनारसी दास गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, जरा आप मैम्बर साहब को कहें कि ये गल्त फिगर न बताएं। इन्होंने अभी कहा है कि तीन सौ करोड़ के टैक्स लगाए हैं।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, सिक्योरिटी वगैरह सब मिलाकर लगभग तीन सौ करोड़ बनता है।

श्री बनारसी दास गुप्ता: सिक्योरिटी टैक्स नही है।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह: सिक्योरिटी –टैक्स तो नही है लेकिन सरकार के पास तो इतना पैसा आया है। मैंने यही कहा है कि सरकार को कुल मिलाकर इतनी आमदनी हुई है। (शोर एवं व्यवधान) मैंने कहा है टैक्स आदि जिसमें सिक्योरिटी भी शामिल है (शोर एवं व्यवधान)। यह सब रिकार्ड पर है। उपाध्यक्ष महोदय, इतने टैक्स का तो कोई औचित्य भी नहीं था जबकि 1990 में पार्लियामैंट के इलैक्शंज भी आ रहें हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथियों ने टैक्स, लगाने की जरूरत इसलिए महसूस नहीं की कि सत्ता में आने से पहले मेरे साथियों ने इतने वायदे कर डाले थे कि शायद अगर सही मायनों में देखा जाए तो वे तर्कसंगत तो हो सकते हैं लेकिन न्याय संगत नही हो सकते और उन वायदों को

पूरा नहीं किया जा सकता। सत्ता में आने से पहले इन्होंने 1200 करोड़ का कर्जा माफी का ऐलान किया था। वृद्धों को पैन्शन देने का वायदा किया था। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को 350 रुपया महीना देने का वायदा किया था और मैट्रिक को 150 रुपए महीना देने का वायदा किया था। इनके पुराने वायदे ही पूरे नहीं हो रहैं हैं, ये नये टैक्स किस कारण से लगाएं?

राजस्व मन्त्री (श्री सूरज भान): उपाध्यक्ष महोदय, ये गलत और कन्ट्रोवर्शियल चीजें कह रहैं हैं। ऐसी बात यह न कहैं तो ठीक रहैंगा। बारह सौ करोड़ रुपए के कर्जे माफ करने के लिए किसने कहा था?

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह: मैंने खुद अखबारों में पढ़ा है। ये सारी चीजें अखबारों में आई थीं। 1200 करोड के बाद अखबारों में पांच सौ करोड़ के कर्जे माफ करने की बात आई थी और उसके बाद आखिर में दो सौ सत्तर करोड़ के कर्जे माफ करने की बात आई थी। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं। जो कुछ मैंने अखबारों में पढ़ा था, वह मैं कह रहा हूं। पेपर्ज में बड़े–बड़े ब्यान दिए गए थे। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। मेरे पास कटिंग्ज हैं। अगर माननीय सदस्य कहैं तो वे कटिंग्ज मैं सोमवार को ला दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इजाजत के बगैर बीच में कोई न टोके।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने इतने वायदे किए थे कि इन वायदों को कोई भी सरकार पूरा नहीं कर सकती। इन्होंने इलैक्शंज से पहले कोई टैक्स नहीं लगाए यह तो समझदारी की बात कर रहैं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर गौर से देखा जाए तो बजट में कोई नई चीज नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1987–88 में जो बजट कांग्रेस शासन के समय में रखा गया था उसमें जो लाइन आफ एक्शन या योजना थी, तकरीबन उसी पर ही चलने की कोशिश की गई है सिर्फ पैन्शन आदि छोड्कर। किसी और तरफ चलने की कोशिश नहीं की गई है। डिप्टी स्पीकर साहब, 1987–88 का बजट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस बजट. को कुछ देने लेने का बजट कहा जाये तो गल्त नहीं होगा। 1987–88 में जो योजनाबद्ध व्यय था, उसमें 588 करोड़ रुपये रखे गये थे। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाह रहा हूं कि हरियाणा में कांग्रेस शासन के बजटों को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि वे बजट कितने योजनाबद्ध होते थे। मैं यह भी कहैं बगैर नहीं रह सकता कि कांग्रेस शासन में हरियाणा कहां से कहां पहुंच गया था और इस बात को नकारा नहीं जा सकता। ये लोग आज फख्र से कहते रहैं कि आज हरियाणा दूसरे नम्बर पर है लेकिन इसका श्रेय इनको नहीं जाता क्योंकि इन को बने तो जुमा–जुमा आठ दिन ही हुए हैं। (शोर) ये लोग एक मिसाल भी दे दें कि जहां कांग्रेस शासन में कोई विकास कार्य अवरुद्ध रहा हो। अगर पहले नम्बर पर आप हरियाणा को पहुंचा दें तो आपकी उपलब्धि मानी जा सकती है वरना उपलब्धि कांग्रेस की ही है।

(शोर) उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां हाउस में इनसे आग्रह कर रहा हूं कि जनता की आवाज को सुनो। अगर 1987 के बजट के बाद दो साल के अन्तर को देखा जाये तो आज का बजट कम से कम 800 करोड रुपये तक पहुंचता। (शोर) हमारे वित्त मन्त्री महोदय, श्री गुप्ता जी तो बहुत समझदार हैं। उन्होंने तो कांग्रेस शासन देखी है। मुख्य मन्त्री भी रहैं हैं। वे हमारी बात को अच्छी तरह से 'समझते हैं। अगर पुराने बजट को सिल– सिले वाइज ध्यान देकर गौर से देखा जाए तो पता चलेगा कि 80–80 व 100–100 करोड़ रुपये उसकी सालाना योजना दर को बढ़ाया गया। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Deputy Speaker : No body is allowed to speak without the permission of the Chair.

11.00 बजे।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, एक चीनी अर्थ–शास्त्री का ब्यान मुझे पता है। उसने कहा था कि हिन्दुस्तान आर्थिक क्षेत्र में 10 साल पिछड़ गया है। हर लिहाज से हर साल सरकारी राजस्व जो बढ़ा है वह तकरीबन 20 और 25 परसैन्ट बढ़ा है। क्रय विक्रय और नये साधन भी स्वाभाविक तौर पर बढ़ते रहैं हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 40–50 फीसदी का परिव्यय बढ़ना चाहिये था और आज इस बजट को कम से कम 800 करोड़ रुपये का हो जाना चाहिये था। आज बिना सोचे समझे यहां ऐसा कह दिया कि कांग्रेस वालों ने ही हरियाणा को इस नौबत पर ला

खड़ा किया है लेकिन पुराने वक्तों के बजट को अगर देखा जाए तो पता चलेगा कि कांग्रेस ने इसको बढ़ाया ही था, घटाया नहीं था। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो वही बात हुई कि नाच न जाने आगन टेढ़ा। जहां तक किसान की बात का सम्बन्ध है, हमारी सरकार ने 1987–88 में बिजली के लिए 1954 करोड़ –रुपए और सिंचाई के लिए 169. 75 करोड़ रुपए रखे थे यानी दोनों मदों के लिए तकरीबन 357.80 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। लेकिन आज दो साल के बाद इसके लिए 295. 95 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बजट का किसान और मजदूर से सीधा ताल्लुक है। उस वक्त इनके लिए योजना गत व्यय 61 प्रतिशत के करीब रखा गया था लेकिन आज 42 प्रतिशत रखा गया है, तकरीबन 20 प्रतिशत कम है। तो यह तो हमारी सरकार की किसानों के विकास की नीति है।

विकास मन्त्री (श्री हुकम सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्यायंट आफ आर्डर है। महैंन्द्र प्रताप जी जरा यह भी बता दें कि आप किसानों को बिजली कितनी दिया करते थे?

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में तो मैंने गवर्नर ऐड्रैस पर बोलते हुए भी माना है और इस बात को ऐप्रिशिएट किया है कि व्यवस्था में सुधार करके बिजली में सुधार किया गया है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता लेकिन इसका इनफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो वह सारी कांग्रेस शासन की देन है। यह रिकार्ड की बात है। बिजली की व्यवस्था काफी

हद तक ठीक करने की कोशिश हमने भी की थी और हमारी स्कीम काफी हद तक कामयाब भी हुई थी। (विघ्न)

श्री रणजीत सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। इन्होंने कहा कि बिजली का इनफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस की देन है, अगर ऐसी बात है तो ये इतनी कम संख्या में हाउस में क्यों आए?

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, यह तो समय की बात है। 1977 में ये साथी काफी संख्या में आए लेकिन 1982 में इनका पता भी नहीं चला कि कहां चले गए। तो इसके तो विभिन्न कारण हो सकते हैं। जनता को इन्होंने कर्जे माफ करने का लालच दिया और आ गए लेकिन जनता अपनी भूल को आज महसूस कर रही है। इसलिए इस बात के विभिन्न कारण हो सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एस० वाई० एल० के बारे में यहां बहुत कुछ कहा जाता है कि कांग्रेस शासन ने इसके लिए काफी कोताही की, कुछ नहीं किया। जहां तक एस० वाई० एल० का ताल्लुक है इसके लिए कांग्रेस शासन में जितना–जितना पैसा रखा गया था अगर उसको देखें फिर पता चलेगा। 1987–88 में हमने इसके लिए 71 4० करोड रुपए रखे थे लेकिन आज केवल 15 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इनके दोष देने की बात हैं कि एस० वाई० एल० के प्रति कांग्रेस या केन्द्र पूरी तरह से गम्भीर नही है, मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस शासन अगर इसको पूरा न करना चाहता तो इतना बड़ा नुकसान क्यों

उठाता? इसके लिए तो इन्दिरा जी ने अपनी शहादत तक दे दी। (विघ्न) उसका ताल्लुक आतंकवाद से भी जुड़ा हुआ है और इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। (विघ्न) यह बात शाह कमिशन के फैसले से भी जुड़ी हुई है। जिस वक्त कमिशन ने चण्डीगढ़ का फैसला दिया तो उसे नहीं माना गया। उसके बाद इन्दिरा जी ने अपना एवार्ड दिया लेकिन उसे भी नहीं माना गया।

श्री धीर पाल सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्यायंट ओफ आर्डर है। मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि केन्द्र में बैठे हुए इनके एक मंत्री एक समा में यह कह कर आए हैं कि प्रधान मन्त्री ने चूंकि एस० वाई० एल० नहर का पानी रोक लिया था और वे चण्डीगढ़ पंजाब को दे रहें थे इसलिए मैंने मुख्य मंत्री पद छोड़ा था। यह बात अखबारों में आई है।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अखबार में आई होगी। उपाध्यक्ष महोदय, इंदिरा जी ने तो अवार्ड दिया था कि चण्डीगढ़ पंजाब को दिया जाए और उसके बदले में फाजिल्का और अबोहर का एरिया हरियाणा को दिया जाए लेकिन आज जो मेरे साथी उस तरफ बैठे हैं, इन्होंने उस अवार्ड को नहीं माना था। इस बारे में गुप्ता जी को काफी मालूम है। आज जो मेरे साथी उस तरफ बैठे हैं इन्होंने उस अवार्ड को अपोज किया था जिसके कारण हरियाणा मे उस समय 4–5 आदमी भी मरे थे। परिणामस्वरूप उस अवार्ड को लागू नहीं किया गया। लेकिन आज वही लोग उस अवार्ड की पैरवी करते हैं। यह कितने अफसोस की बात है? उपाध्यक्ष महोदय,

जहां तक लौंगोवाल राजीव समझौते का ताल्लुक है उसको भी यह सरकार नहीं मानती। उस फैसले के मुताबिक चाडीगढ पंजाब को मिलना था और उसके बदले में हरियाणा को कुछ एरिया मिलना था और एस० वाई० एल० नहर का पानी तथा दूसरी चीजें मिलनी थी लेकिन इन्होंने उस फैसले को भी नहीं माना। जब यह सरकार लौंगोवाल राजीव के फैसले को ही नहीं मानती तो एस० वाई० एल० नहर की किस मुंह से पैरवी करती है?

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक जन स्वास्थ्य विभाग का ताल्लुक है, इसके लिए 1987–88 के बजट में लगभग 25 करोड़ रुपया रखा गया था। उसकी तुलना में अब 1989–90 के बजट में बहुत कम पैसे का प्रावधान किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, 1987–88 और 1989–90 में बहुत समय का अन्तर है। हमने 1987–88 के बजट में 480 गांवों को पीने का पानी मुहैया करने की योजना' बनाई थी जिनमें से यह सरकार पिछले साल 220 गांवों को ही पीने का पानी दे पाई शै और आज भी 400 गांवों को पीने का पानी मुहैया करवाने का इस सरकार का टारगेट है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक. सड्कों का ताल्लुक है, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि 1987–88 के बजट में 403 किलोमीटर नई सड़कें बनाने की योजना थी लेकिन इस बजट में इस सरकार ने केवल 220 किलोमीटर नई सड़कें बनाने का प्रोवीजन रखा है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते है कि इस बजट को विकासशील बजट किस दृष्टि से कहा जा सकता है? अगर इस

बजट को तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो पिछले दो साल का असर अगले चार साल पर पड़ता है यानी विकास की दृष्टि से हरियाणा प्रदेश चार साल पीछे चला जाता है। इनके– पास केन्द्र की सरकार को कोसने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नही है। उपाध्यक्ष महोदय, जब चौधरी बंसी लाल जी ने गद्दी छोड़ी, उस समय 40 करोड़ रुपया हरियाणा के खजाने में रहता था, यह रिकार्ड की बात है। (शोर)

श्री बनारसी दास गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह गलत बात कह रहैं हैं कि उन्होंने हरियाणा के खजाने में 40 करोड़ रुपया छोड़ा था।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, यह तो रिकार्ड की बात है। यह बात अखबारों में भी आई थी। इन्होंने भी माना था कि 4० करोड रुपया हरियाणा के खजाने में उन्हैंने छोड़ा था। आप लोग तो पिछली दफा यह भी कह रहैं थे कि आपने 227 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया लेकिन इस बजट में केवल 10 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने का प्रोविजन रखा है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कर्जे वाली बाल को दोहराना नही चाहता। जिस समय बजट की प्रति सदन के पटल पर रखी जा रही थी, उस समय मैं यह समझ रहा था कि. शायद 1200 या 500 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने का प्रोविजन रखा जाएगा लेकिन इन्होंने केवल 10 करोड रुपए का कर्जा माफ करने का प्रोविजन रखा है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, ये मेरे भाई कह रहैं हैं कि कांग्रेस वाले

भिवानी और दूसरी सभाओं में झूठे प्रचाररू फैला रहैं है कि इस सरकार ने किसी का कोई कर्जा माफ नहीं किया लेकिन काग्रेस वालों ने तो यह कहा है कि इस सरकार ने जनता के साथ जो वायदे किए थे उनको पूरा नही किया है। केवल जनता के आमू पोंछने के लिए ही इन्होंने यह वायदा किया था। कांग्रेस वालों ने तो सिर्फ इतना ही कहा है। मैंने इस बजट में देखा है कि इस सरकार ने केवल 6, 20 करोड़ रुपए का हरिजन कल्याण निगम और बैकवर्ड क्लासिज निगम का कर्जा माफ किया है। तकरीबन साढ़े सात करोड़ रुपए के कर्जे ट्रैक्टर्ज के माफ किए हैं और तकरीबन 33.61 परसैटं कोआप्रे– टिव बैक्स का कर्जा माफ किया है। यह फिगर साढ़े 47 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। पता नहीं यह सरकार किस बात का इतना बड़ा ढिंढोरा पीट रही है। (विघ्न) यह तो रिकार्ड की बान है। 1987–88 में जब कांग्रेस शासन था उस समय 120 करोड़ रुपये के लगभग किसान और मजदूरों का पैसा एकदम माफ कर दिया गया था लेकिन उसका हमने जिकर तक नहीं किया क्योंकि यह हमारा फर्ज था। इन्होंने 45–47 करोड़ रुपये के कजें अवश्य माफ किए हैं। यह अचीवमैंट इनकी उस मुकाबले में नही है जितना ये शोर मचा रहैं थे कि हम इतने कर्जे माफ कर देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने यह एलान किया कि हम कर्जे माफ कर देंगे तो जिन लोगों ने ट्रैक्टर्ज के लिए कर्जा ले रखा था चाहैं किसी ने 20 हजार ले रखा था या किसी ने 30–40 या 50 हजार रुपये का कर्जा ले रखा था या एक लाख रुपये का कर्जा ले रखा, था सभी ने अपनी किस्तें देनी बंद कर

दी। अब उन सभी का कर्ज माफ नही हुआ जिस कारण उन पर ब्याज पड़ गया और डिफाल्टर्ज की संख्या और ज्यादा हो गई। यदि वे अपनी किस्तें समय पर देते तो उन पर ब्याज भी न पड़ता और जो डिफाल्टर्ज की संख्या अब बड़ी है वह अधिक न होती। 10 हजार रुपये से कम कर्जे जो इन्होंने माफ किए हैं उनकी कुल राशि 45–47 करोड़ रुपये के आस– पास बैठती है जबकि इन्होंने यह राशि लगभग 250 करोड़ रुपये की बताई है।

श्री भागी रामः आप तो यह कहा करते थे कि एक पैसा भी माफ नहीं होगा लेकिन हमने माफ किए या नहीं इस बात को आप कलियर करो।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः मैं इस बात को तो अब भी कहता हूं कि एक नया पैसा भी कर्ज का माफ नहीं हो सकता। सरकार ने कहा से पैसा लिया हुआ है, वहा तो उसको देना ही पड़ेगा। इसलिए उस कर्जे को माफी की शकल में नहीं गिना जा सकता।

श्री रणजीत सिंहः आन ए प्वायंट औफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहब, अभी माननीय सदस्य चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह जी ने कहा कि कर्जे माफ 'नहीं हो सकते। मैं महैंन्द्र प्रताप सिंह की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आल इण्डिया रेडियो तो झूठा नही हो सकता, उसने कई बार घोषणा की कि महाराष्ट्र की सरकार ने कर्जे माफ किए हैं।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः वह बात तो मैं अब भी कह रहा हूं कि सरकार कर्जे माफ नहीं कर सकती, बल्कि उन कर्जो को अदा कर सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां इनको कोई चीज नजर नहीं आती वहीं पर केन्द्र सरकार को कोसा जाता है। अभी पिछले दिनों हरियाणा के 7–8 जिलों में भी बाढ़ आई थी। इन जिलों में फरीदाबाद भी शामिल है। मैं रिकार्ड की बात कह रहा हूं और माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने भी माना है कि केन्द्र ने हरियाणा को 32–33 करोड़ रुपये दिए हैं। उपाध्यक्ष महोदय पलवल, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में भी बाढ़ का काफी असर हुआ था। वहां पर फसलें तबाह हो गई थी और लोगों के घर तहस– नहस हो गए थे। वहां पर इतनी अधिक बाढ़ आई थी कि हमारे एक मंत्री श्री पुनिया साहब भी उस बाढ़ में घिर गए थे। उनका दो–तीन दिन? तक पता नहीं लगा कि वे कहां गए। यह खबर अखबारों में आई थी। इन्होंने आज तक केन्द्र सरकार की तरफ से इतनी राशि मिलने पर भी फरीदाबाद जिले को सिर्फ 20 लाख रुपये दिए हैं जिसमें से अभी तक सिर्फ 15 लाख रुपये ही बांटे जा सके हैं। (विघ्न) बाकी पैसा इन्होंने कहां खर्च किया हैं, ये जरा बताएं। यहां बैठ कर ये चाहैं कुछ भी बातें कह लें, लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल भी होता है या नहीं इसमें कुछ शक है और यह इन को ज्यादा मालूम है। उपाध्यक्ष महोदय, ये चीजें आपके माध्यम से में इस महान सदन के सामने लाना चाहता हूं। इनका कहना है कि केन्द्र ने मदद नहीं दी लेकिन केन्द्र ने जो मदद दी है, उस बारे अखबारों में छपा है। 217 या 270 करोड़

रुपये का ऋण सरकार दे रही है। 220 करोड़ रुपये अभी अदा भी करने हैं। इसके अलावा एस० वाई० एल० नहर के लिए भी पैसे दिये जा रहैं हैं। जहां तक आतंकवाद का ताल्लुक है, ये लोग केन्द्र को आतंकवाद के लिए दोषी ठहराते हैं और यह आरोप लगाते हैं कि केन्द्र आतंकवाद से निपटने के लिए मदद नहीं देता, जीपें नहीं देता, लेकिन केन्द्र ने मदद दी है, जीपें दी हैं। पता नहीं, ये लोग केन्द्र को किस ढंग से जिम्मेदार ठहराते हैं? उपाध्यक्ष जी, दूसरी बात यह कही गई कि कांग्रेस की वजह से आतंकवाद की घटनाएं हुई। दरियापुर कांड के बारे में भी आरोप लगाया गया कि यह कांड कांग्रेस ने करवाया लेकिन बाद में सच्चाई सब के सामने आई। इस प्रकार के आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। यह कहा जाता है कि दिल्ली के दंगे कांग्रेस ने करवाए और पंजाब में भी केन्द्र ही आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने भी कई बार कहा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए केन्द्र हथियार नहीं दे रहा, जीपें नहीं दे रहा, जितनी मदद मांगी थी उतनी नहीं दी गई। उपाक यक्ष महोदय, केन्द्र से जितनी मदद मांगी गई, हो सकता है केन्द्र ने उतनी मदद न दी हो, लेकिन मदद दी गई है। इस प्रकार की बातें करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचा जो सकता। मुझे पता नही कि मदद कम मिलती है या ज्य लेकिन यदि मदद कम भी मिलती है तो इस तरह की आक्षेपबाजी से अपनी जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। आतंकवाद और उग्रवाद की चाहैं कितनी भी घटनाएं हुई या नहीं हुई लेकिन कानून और

व्यवस्था पर काबू रखना चाहिए। आतंकवाद जैसी भय समस्या को अनुभव करना चाहिए और इस से निपटने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। एक–दूसरे पर जान बूझ कर आक्षेपबाजी हमें नहीं करनी चाहिए। चाहैं कोई भी पार्टी हो या कोई भी सदस्य हो, यह सभी की जिम्मे– दारी है कि पोलिटिकल और राजनैतिक बातें हम न करें बल्कि इस मामले में देश और प्रदेश के हित को सोच कर चलना चाहिए। हम सभी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आज मौजूदा हालात में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में सभी पार्टियों को सहयोग देना चाहिए। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः महैंन्द्र प्रताप सिंह जी, अब आप बैठिये आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए कुछ समय और दीजिए ताकि मैं अपनी बात कह सकूं।

श्री उपाध्यक्षः आप दो मिनट में अपनी बात पूरी करें।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः कल आदरणीय डाक्टर साहब ने एक बात कही। उन्होंने सच्चाई को कबूल किया। यह. उनकी खासियत है कि वे सच्चाई को मानते हैं? लेकिन अपने नम्बरों की खातिर थोड़ी–बहुत बात उन्हैं सरकार की भी कहनी पड़ती है परन्तु दिल से वे भी रोते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग गलत प्रचार करते हैं, आतंकवाद 'फैलाने में जिनकी भूमिका है, ऐसे लोगों को दण्डित करना चाहिए। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय', जहां

तक इनकी बात है, दण्डित? तो उन्हें करना चाहिए जो जनहित के कार्यों में, जनता के विकास में येन–केन–प्राकरेण बाधा पहुंचाते हैं। यहां बैठकर चाहें ये कुछ भी जवाब दे लें, कुछ भी कह लें क्योंकि यहां पर जनता नहीं है लेकिन कल को जनता उन लोगों को स्वयं ही दण्ड देगी। आज अराजकता की जिम्मेदारी और आतंकवाद की जिम्मेदारी किस पर हैं? प्रजातन्त्र की हत्या रोज–मर्रा हो रही है। इलैक्शन कमीशन ने बूथ कैप्चरिंग के बारे में फैसला दिया है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः अब आप बैठें।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः उपाध्यक्ष महोदय .....

श्री सूरज भानः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। यह बात कुछ दिन पहले भी हुई थी लेकिन रिकार्ड पर नहीं आई है। इसलिए अब भी यह चीज रिकार्ड पर नही आनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः ठीक है, यह बात रिकार्ड न की जाए। महैंन्द्र प्रताप जी अब आप बैठें।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे 4–5 मिनट का समय और दीजिए ताकि मैं प्वायंट वाईज उत्तर दे सकूं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, डा० मंगल सैन जी ने कहा कि 1990 में इलैक्शन आ रहैं हैं और कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, डा० मंगल सैन जी ने कहा कि किसी भी पार्टी

की शक्ति जनता के पास है। जनता ने सन 1977 में भी अपनी शक्ति का प्रयोग किया था और आगे भी करेगी। किसी भी पार्टी को जनता ही दंडित करती है। इस बात के लिए जनता ही अच्छा समाधान है लेकिन जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, उसके बारे में गुप्ता जी भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस का क्या तरीका है और इनका क्या हैं?

श्री उपाध्यक्षः महैंन्द्र प्रताप जी, आपको बोलते हुए लगभग आधा घण्टा हो गया है। जब आप बोलने के लिए खड़े हुए थे, उसी समय मैंने आपसे पूछ लिथा था कि आप कितना समय लोगे और आपने कहा था कि आप आधा घंटा लेंगे। चूकि आपको बोलते हुए आधा घंटा हो गया है इसलिए आप वाइन्ड–अप कीजिए। (विघ्न)

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब मेरे हल्के के मामले रह गये हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। अब मैं दूसरी बातों पर नही जाऊंगा। गुप्ता जी ने मेरे अपने हल्के की मांगे मांगी भी हैं इसलिए उनके बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही मिनट लूंगा। अभी खत्म कर देता हूं। सब से पहले मैं हुड्डा के बारे में थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा। हुड्डा जन विकास और गरीब जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्लॉटस की व्यवस्था करता है। फरीदाबाद में झुग्गी झोपड़ियां बहुत ज्यादा है। वहां पर हुड्डा की तरफ से छोटे मजदूरों को मकान बनाने के लिए प्लॉटस की कोई व्यवस्था नहीं

की गई है। वहां पर कुछ मकान बन रहैं हैं लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए वे पूरे नही हो सकते। वहां पर एक ऐसा सैक्टर बनाया जाये जिसमें छोटे प्लॉट्स हों और झुग्गी झोपड़ी वालों को वहां से उठा कर उस सैक्टर में बसाया जाये। इसके अलावा यदि कोआप्रेटिव सैक्टर को सरकार बढ़ावा देगी तो बहुत ही अच्छा होगा। आज अगर कोई आदमी सरकार द्वारा काटे हुए सैक्टर में प्लॉट लेगा तो उसे डिवैल्पमैंट चार्जिज लगा कर 400 रुपये गज के हिसाब से वह पड़ेगा। सैक्टरों में प्लॉट बहुत ज्यादा मंहगे पड़ते हैं। लेकिन वहां पर ऐक्स सर्विस मैन की जो कोआप्रेटिंव सोसाइटी है, उस सोसाइटी के सौ रुपये डिवैल्पमेंट चार्जिज आये हैं और वह कालोनी अब कम्पलीट हो गई है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः महैंन्द्र प्रताप सिंह जी, अब आप बैठिए।

श्री हीरा नन्द आर्यः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मेरा निवेदन यह है कि कुछ लोगों को गवर्नर ऐड्रैस पर भी बोलने का टाईम मिल गया था और आज बजट पर भी बोलने के लिए टाईम मिल गया हैं। मुझे गवर्नर ऐड्रैस पर भी बोलने के लिए टाईम नही मिला और अभी तक बजट पर बोलने के लिए भी टाईम नहीं मिला है। इसलिए अब मुझे टाईम मिलना चाहिए। मैं भी इस सदन का मैम्बर हूं। मुझे भी यहां बोलने का अधिकार है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः आप गवर्नर 'ऐड्रैस पर बोल चुके हैं।

श्री हीरा नन्द आर्यः आपकी यह इन्फर्मेशन गलत है। उपाध्यक्ष महोदय अगर मेरे बोलने पर पाबन्दी हो तो मैं सदन से चला जाऊं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः पार्टी की तरफ से आपका नाम नहीं आया, इसलिए आपको टाईम नहीं मिला। (विघ्न)

श्री धीर पाल सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, नौन–औफिशियल डे पर ये काफी टाईम तक रैजोल्यूशन पर बोलते रहैं हैं। (विघ्न)

श्री हीरा नन्द आर्यः उपाध्यक्ष महोदय, यह तो आपके अपने अधिकार की बात है। जो आदमी गवर्नर ऐड्रैस पर बोले हैं, वही बजट पर भी बोल रहैं हैं। उन लोगों को दो–दो बार टाईम दिया जा रहा है, मुझे आप एक बार भी टाईम नहीं दे रहैं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः धीरपाल जी कह रहैं हैं कि आप उस दिन रैजोल्यूशन पर बोल चुके हैं इसलिए आपको टाईम नहीं मिला। (विघ्न)

श्री हीरा नन्द आर्यः उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन तो मुझे ' जबरदस्ती बुलवाया गया था। (हंसी)

श्री उपाध्यक्षः आप उस दिन रैजोल्यूशन पर लगभग आधा घण्टा बोल चुके हैं।

श्री हीरा नन्द आर्यः उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा हूं कि मुझे उस दिन जबरदस्ती बुलवाया गया था। मैं उस दिन

बोलना नहीं चाहता था। मैं आज बोलना चाहता हूं, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन्साफ करें। मैंने अपने हल्के की भी बातें कहनी हैं।

श्री उपाध्यक्षः भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की तरफ से मेरे पास नाम? आये हैं लेकिन उसमें आपका नाम नहीं है। आप उस दिन रैजोल्यूशन पर बोले थे इसलिए आपका नाम नही आया।

श्री हीरा नन्द आर्यः उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन मुझे जबरदस्ती बुलवाया गया था।

श्री रणजीत सिंहः आन ए प्वायंट औफ आर्डर, सर। सर, यहां सदन में किसी को भी जबरदस्ती नहीं बुलवाया जाता। इसलिए माननीय सदस्य जो यह कह रहैं हैं कि मुझे जबरदस्ती बुलवाया गया, यह गलत कह रहैं हैं।

श्री हीरा नन्द आर्यः उपाध्यक्ष महोदय, अगर मुझे टाईम नही मिलना है, तो मैं चला जाता हूं। (विघ्न) मेरा अगर यहां बोलने का अधिकार ही नहीं हैं तो मैं चला जाता हूं। (विघ्न)

श्री धीर पाल सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, जो० फ नये मैम्बर्ज हैं, उनका ध्यान रखते हुए टाईम दिया जा रहा है।

श्री हीरा नन्द आर्यः सर, कोई मैम्बर ज्ञ क् नहीं है सब माननीय सदस्य हैं। इसलिए यह शब्द कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री उपाध्यक्षः यह शब्द रिकार्ड पर न लाया जाए।

श्री रणजीत सिंह (रोड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल से बजट पर चर्चा चल रही है। जितने भी माननीय साथियों ने चर्चा की, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं। सब लोगों ने बड़े कंस्ट्रक्टिव सुझाव दिये हैं। आपने चूंकि समय दिया इसलिये मैं भी अपनी बातें 5– 10 मिनट में कहूंगा। पहले तो मैं अपने आदरणीय उप–मुख्य मन्त्री, श्री बनारसी दास गुप्ता जी, को मुबारिकबाद देता हूं क्योंकि इन्होंने बहुत ही बैलैस्ड तरीके से, सूझ–बूझ से और बिल्कुल कर–रहित बजट इस सदन में रखा है। मैं समझता हूं कि बजट सरकार की पूरे साल की कारगुजारी का और सरकार ने जनता का किस तरह से प्रतिनिधित्व किया है, उसका एक दर्पण होता

Mr. Deputy Speaker : Chaudhri Ranjit Singh, wisdom lies in brevity.

श्री रणजीत सिंहः बहुत अच्छा जी, मैं 15 मिनट तक खत्म कर दूंगा। मेरे से पहले सदस्यों ने जिक्र किया कि किस तरीके से सरकार ने सूखे के लिये और बाढ़ के लिये अपने सीमित साधनों के बावजूद बड़ी मुस्तैदी से बढ़िया काम किया है। मैं भी इस बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा। मैं इस सदन की मार्फत यह कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने हरियाणा के साथ अन्याय किया है। राजस्थान जैसे प्रदेश को सूखे के लिये 400 करोड़ रुपया दे दिया गया जबकि हरियाणा को केवल 42 करोड़ रुपया ही दिया

गया। जब क्वैश्चन आवर मैं चर्चा हो रही थी, उस समय यह बताया गया कि हरियाणा को वास्तव में केवल 20 करोड़ रुपया ही दिया गया है। मैं यह समझता हूं कि हरियाणा सरकार के साथ यह केन्द्र की सरासर नाइन्साफी है। इसके आगे मैं इस सरकार की अचीवमैट्स की चर्चा करूंगा जिसकी बजट में भी चर्चा है। ओल्ड ऐज पैशन का बजट में चर्चा णै। यह एक नयी मिसाल है। इस सरकार ने यह लागू करके देश की दूसरी सरकारों को स्टैप इन करने के लिये एक माईल स्टोन कायम किया है। दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि हमारे माननीय सदस्य यह कहते थे कि बेरोजगारी भला नहीं दिया। मैं अपने कांग्रेसी भाइयों को, जिन्होंने इस –बारे में चर्चा की है, से यह कहुंगा कि इस बजट में लिखा है कि 6 कुछ करोड है जोकि सरकार ने अन–एम्पलायड यूथ्स के लिये रखा है। यह वाकई सराहनीय कदम है। पीछे बिजली की भी चर्चा रही। मैं चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी को मुबारिकबाद देता हूं क्योंकि इन्होंने इस सरकार के टेक ओवर करने के बाद बिजली में पौने दो साल में सुधार करके इसे ऐसे गांवों में भी मुहैया किया है, जहां पर कभी बिजली मुहैया नहीं की गयी थी। पिछले दिनों पावर मिनिस्टर्ज की मीटिंग थी। उसमें हमारे चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी भी गये थे। सारे ओफिसर्ज भी वहां गये थे और हमारे बाबू मूल चन्द जै न जी भी थे। पावर मिनिस्टर्ज की उस मीटिंग में चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने एक बड़ा ही बोल्ड स्टैप लिया था। ये वहां से वाक–आउट कर गये थे। इस तरह से इन्होंने हरियाणा प्रदेश के स्वाभिमान को जगाया है। जब हमारे प्रदेश के पावर

मिनिस्टर की बात को नहीं सुना गया तो ये वाक–आउट कर गये। मैं समझता हूं कि केन्द्र के रवैये के खिलाफ लिये गये इस स्टैप को हम सब को स्वीकृत करना चाहिये। दूसरे मैं एक और चर्चा करूंगा। एस० वाई० एल० कैनाल का मेरे से पहले साथियों ने जिक्र किया कि यह स्टेट के लिये सबसे अहम मसला है। मैं यह समझता हूं कि हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिये कि अभी यह कम्पलीट होगी। इस मामले को हमारे से पहले की सरकारों ने इतना उलझा दिया है कि मैं तो यह खुल कर कहना चाहूंगा कि. पंजाब का इसमें पोलिटिकल इन्ट्रैस्ट है और सैंटर का फाइनैंशियल इन्ट्रैस्ट है। पंजाब के इंजीनियर्ज ने इसे सोर्स औफ इन्कम बना लिया है। एक मिस्टर गिल हैं जो एस० वाई० एल० के इंजीनियर इन चीफ रहैं हैं। अभी पिछले दिनों उनके लड़के की शादी थी। इस सैचरी की यह सबसे ज्यादा कौस्टली शादी थी। भजन लाल के लड़के की शादी से भी ज्यादा कौस्टली थी। इसका प्रैस में भी बड़ा चर्चा हुआ था। सब लोगों को इस बात का पता है। आपके माध्यम से इस सदन की मार्फत मैं यह निवेदन करूंगा कि एस० वाई० एल० प्रोजैक्ट को हमारी सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये। हमारे इंजीनियर्ज वहां पर होने चाहिये'। सैटर से इस बात को टेक–अप करना चाहिये। हमारे आदरणीय मंत्री जी और दूसरे औफिसर्ज की टीम को महीने में कम से कम दो बार विजिट करना चाहिये ताकि पता लगता रहैं कि काम कहां रुका हुआ है। जिस ढंग से पुलियां बननी हैं, जिस ढंग से कल्वर्टस बनने है, और जिस ढंग से बैरेजिज बनने हैं, उसके अनुसार अगर

सारी नहर बन भी जाए लेकिन एक बैरेज भी रह जाए तो उस नहर बनने का कोई फायदा नही है। इस लिए मेरी प्रार्थना है कि इस तरफ अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए।

इसके बाद मैं पंचायत विकास कार्यों के बारे में खास चर्चा करना चाहूंगा। पंचायतों को ज्यादा पावर्ज देने की बात कही गई। सब माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि बी० डी० पी० ओ० को खर्च करने के लिए पैसा दिया जाता है। एक एम० एल० ए० अपने क्षेत्र की समस्याएं ज्यादा अच्छी तरह से जानता है। मेरा सुझाव है कि बी० डी० पी० ओं० को हिदायत दी जाए कि जब वह पैसा खर्च करे तो उस क्षेत्र के एम० एल० ए० को विश्वास में लेकर पैसा खर्च करे जिससे उस क्षेत्र की डिवैल्पमैंट ज्यादा से ज्यादा हो सके। बंगाल सरकार को इस बात का श्रेय है कि वहां इस ढंग से काम किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं खालों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। इस बारे में हरियाणा में काफी चर्चा है और हरियाणा का किसान सब से ज्यादा परेशान इन खालों की वजह से है। पहले प्रशासन के कुशासन की वजह से आज किसान को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पहले जितना भी पैसा खालों की मैंटेनैसं पर खर्च किया जाना था वह खर्च ही नहीं किया गया और वे लोग कमीशन खा गए। इस कारण जिस खाल की लाइफ बीस साल चलनी थी वह खाल पांच साल में टूट गया। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सब से ज्यादा प्रायरिटी बालों को देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह ने बिजली की डिवैल्पमैंट का सारा क्रैडिट कांग्रेस के खाते में डाल दिया।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः सारा नहीं पार्टली।

श्री रणजीत सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, वे कहते है कि इस सरकार के आने के बाद विकास कार्य कम हो गए। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार रेल कोच फैक्टरी हरियाणा के लिए मन्जूर हुई थी लेकिन वह रेल कोच फैक्टरी पंजाब को दे दी। यह छः सौ करोड़ रुपए का प्रोजैक्ट था और उससे कम से कम बारह हजार लोगों को ऐम्पलाएमैंट मिलनी थी। लेकिन वह कांग्रेस की सरकार ने पंजाब को दे दिया। यह सरकार तीन शूगर मिल्ज सैन्टर से लेकर आई है। अगर ये तीन शूगर मिल्ज भी पंजाब को चली जाती तो प्रदेश का कितना नुक्सान होता। उपाध्यक्ष महोदय, यह विकास की निशानी है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं गन्ने के भाव के बारे में चर्चा करूंगा। यह सरकार गन्ने का भाव 35 रुपए क्विंटल किसानों को दे रही है। किसी भी प्रदेश की सरकार इतना भाव गन्ने का गती दे स्की है। यह इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यू० पी०, बिहार और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्ज कहते हैं कि अगर इन प्रदेशों में गन्ना मिल्ज मुनाफे में चलानी है तो इनको ताऊ को दे दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं ऐजूकेशन के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। मैं बहन सुषमा जी को मुबारिकबाद देता हूं कि

उन्होंने इस विषय को बहुत बढ़िया तरीके से और डीपली ऐग्जामिन करके ऐजूकेशन पौलिसी को लागू किया है। काफी स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा स्कूलों को अपग्रेड करने की तरफ तवज्जह दी जानी चाहिए जिससे कि हरियाणा में शिक्षा का अधिक. से अधिक प्रचार और प्रसार हो। उपाध्यक्ष म होदय, सरकार ने स्कूल्ज का अलग और कालेजिज का अलग डायरैक्टोरेट बनाकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि सरकार एक– एक कास्टिचुऐंसी में दो मौडल स्कूल खोल दे। मैं यह तो नही कहता कि उनके लिए बिल्डिंग्ज भी बना दी जाए क्योंकि उनको बनाने में तो चालीस पचास लाख रुपया खर्च आएगा। जिस तरह से शहरों में प्राईवेट बिल्डिंग्ज में कौंन्वैट स्कूल चल रहैं हैं उसी तरह से प्राईवेट बिल्डिंग्ज किराये पर लेकर ये स्कूल्ज देहात में खोल दिए जाएं। इस वक्त देहात में जो स्कूल हैं, उनमें टीचर्ज बहुत कम हैं और पढ़ाई, का काम भी ठीक तरह से नहीं चल रहा हैं। ये मौडल स्कूल इंगलिश मीडियम के खोले जाने चाहिए जिस तरह से शहरों में कौंवैन्ट और पब्लिक स्कूल खुले हुए हैं ताकि देहात के बच्चे भी शहर के बच्चों की तरह से कम्पीट कर सकें। अगर सरकार ऐसा कर दे तो देहात के लोग सरकार के इस कदम की बहुत सराहना करेंगे और यह बहुत ही अच्छा कदम होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा सा जिकर स्पोर्टस के बारे में करना चाहता हू। पंजाब में कुछ स्पोर्टस इनसैनटिव दिया गया है। जो प्लेयर यूनिवर्सिटी या इंटर स्टेट टूर्नामैंट्स में फर्स्ट पोजिशन हासिल करते हैं उनको पंजाब सरकार 5– 5 हजार रुपया देती है। विदेशों में जो दूसरी पोजिशन पर आता है उस प्लेयर को पंजाब सरकार 10 हजार व जो गोल्ड मै डल हासिल करके प्लेयर आते हैं उनको 25 हजार रुपये वा इंसैन्टिव सरकार की ओर से दिया जाता है। सो मेरा अपनी सरकार से अनुरोध है कि इसी तरह के इंसैन्टिवज हरियाणा सरकार को अप नी स्टेट के नौजवान प्लेयर्ज को देने चाहिये। हरियाणा के नौजवान प्लेयर्ज फिजिकल फिटनैस के हिसाब से कि सी दूसरी स्टेट से कम नही हैं। इसी लये इस तरह का स्पोर्टस विभाग के अन्दर भी पैसे का प्रोविज न रखा जाए।

इसके बाद अब मैं वीडियॉ पारलर का भी जिकर करूंगा। विधानसभा में भी इसकी काफी चर्चा हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, आज एक सिनेमा प्लाट की कीमत लगभग 20 लाख है। चाहैं कोई आदमी किसी प्राईवेट पार्टी से खरीदे या हुड्डा से खरीदे, एक प्लाट खरीदने वाले को काफी पैसा लग पड़ता है। उसके बाद फिर सिनेमा के निर्माण, उसके आर० सी० सी० स्ट्रक्चर और मशीनों वगैरह के लिये लगभग 1 करोड़ से कम पैसा खर्च नही होता है। मतलब यह कि 1 करोड़ से कम आज सिनेमा नही पडता है लेकिन उन सिनेमा मालिकों को जगह –जगह वीडियो

पारलर खुलने के कारण काफी नु कसान उठाना पड़ रहा है। वीडियोज की वजह से सिनेमा इंडस्ट्री क्रिपल हो रही है। इस से सरकार को भी– टैक्स – का काफी नुकसान हो रहा है। एक सिनेमा से लगभग 2 लाख के करीब एक महीने का टैक्स सरकार को आता है जबकि वीडियो पारलर से केवल 25 हजार रुपया क्वार्टरली टै क्स सरकार को आता है। फतेहाबाद में इसी तरह की एक वीडियो पारलर चल रही है जिससे सरकार को क्वार्टर ली 25 हजार रुपया आ रहा है न इसलिय मेरा कहना है कि इस तरह की जो इंडस्ट्री है उस पर निगाह रखी जाए और कोई ऐसा हल निकाला जाए जिससे सिनेमा से आने वाले टैक्स से सरकार को ज्यादा आमदनी हो सके। एक सिनेमा घर से, उपाध्यक्ष महोदय, दो लाख के करीब टैक्स आ ता है और आप सोचिये कि सारी स्टेट में कितने सनेमा होगें। इस से सरकार की आमदनी काफी बढ़ सकती है।

इसके बाद मैं इडस्ट्रीज का जिकर करूंगा। आर्थिक विकास के लिये हमारी, सरकार की नीति औज ओद्योगिकरण को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान करती है। हमारी औद्येगिक नीति का लक्ष्य अपने राज्य में तीव्र औद्योगिक वकास के लये उदारता– पूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करन है। हम इंडस्ट्रीज मिनिस्टर श्री पुनिया साहब. ने बडी अच्छी इंडस्ट्रियल नीति बनायी है। बिक्री कर में डैफरमैन्ट लेने का विकल्प – दिय। गया है। छोटे–बड़े पैमाने के यूनिटों के लिये जैनरेटिंग सैट्स पर बैकवर्ड एरियाज में 25

परसैन्ट तक सबसिडी देने का एलान किया गया है। यह बड़ी अच्छी बात है लेकिन मैं तक और बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिस तरह से बंगाल के चीफ मिनिस्टर वेरियस कन्ट्रीज में जाते हैं और वहां के बड़े–बड़े इंडस्ट्रियलिस्टस को आमंत्रित करके आते हैं कि आप हम राज्य में आओ और वहां पर इंडस्ट्रीज लगाओ, हम आपको हर तरह की मदद देंगे और मैं दिल्ली में बैठकर आपके लायजन औफिसर का काम करूंगा। इसी तरह से मैं यह कहूंगा कि हमारी तरफ से भी इस तरह की कोई प्रोपोजल बनायी जानी चाहिये जिससे हम भी विदेशों में रहने वाले भारतीयों को अपने प्रदेश में आने के लिये आमंत्रित करें कि आप हमारे राज्य में इंडस्ट्रीज लगाओ। हम आपको सभी प्रकार के सहायता अनुदान देंगे। जितने भी हम भारत के लोग उधर रहते हैं, वे वहां के लोगों से धनाढ्य हैं। अगर सरकार आश्वासन देकर इनसैनटिव देने की बात उन से करेगी तो वे लोग अवश्य ही इधर आएंगे और अपना कारोबार स्थापित करेंगे जिस से सरकार का रेवेन्यू भी काफी बढ़ेगा। आशा है कि सरकार अवश्य ही मेरे इस सुझाव पर गौर करेगी।

इस के बाद मैं जिकर करूंगा उस लोन की आउट स्टैंडिंग–रिपोर्ट के बारे में, जोकि कल हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने इस हाउस में पढ़ी थी। उसमें हमारे कुछ पोलिटिकल आदमी इंवोल्वड थे। उनके खिलाफ आउट–स्टैंडिंग एरियर्ज की चर्चा थी जिसको सदन के सभी मैम्बरान ने ध्यान से सुना था होर प्रैस ने

भी स व कुछ सुना होगा क्योंकि उसका आज अखबारों में जिकर आय है। मैं समझत हूं कि पोलिटिकल इंस्टिच्यूशन के प्रति लोगों के मन में किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिये, किसी प्रकार का कोई भ्रम नही होना चाहिये। लेकिन यदि इस पोलिटिकल इंस्टिच्यूशन को ही करप्ट कर दिया जा ये तो इसके लिये दोषी पा ये जाने वाले व्यक्ति के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिये। हरियाणा फाइनैंशियल कारपोरेशन व एच० आई० डी० सी० से लोगों को लोन दिये गये ताकि वे कोई न कोई इंडस्ट्री लगाकर के अपना कारोबार शुरू कर सकें लोन देते वक्त एक दो बातों का खास ध्यान रखा जाता है कि इंडस्ट्रीज लगाने वाले को इंडस्ट्री लाईन का कोई न कोई ऐक्सपीरियैन्स अवश्य होना चाहिये। साथ में यह भी देख जाता है कि जिस जगह पर इंडस्ट्री लग रही है, आया वह जगह इस लिहाज से सही है या नहीं। लेकिन जब इस बात की पूरी जांच की गयी, छानबीन की गयी सौ पता चला कि लगभग 85 परसैन्ट ऐसे आदमियों को इंडस्ट्रीज लगाने के लिये लोन दिलवाया गया जिनके बाप–दादाओं ने भी कभी कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगाई थीं जैसा कि स्टेटमैंट से जाहिर है सभी कानूनों की उल्लंघना करके प्रदेश के पैसे को बुरी तरह से लूटा गया है। बगैर इन बातों की स्क्रूटिनी किये नासमझ लोगों को सरकार का पैसा दे दिया गया और इस पैसे से किसी की इंडस्ट्री नहीं चक रही। गवर्नमैंट को इसकी इन्कवायरी करवानी चाहिये कि इसके लिए कौन अफसर रिसपौसिबल थे जिन्होंने इतना पैसा बगैर सोचे समझे दे दिया। मैं आदरणीय सदन के नेता और उप मुख्य

मन्त्री जी के माध्यम से सदस्यों को निवेदन करूंगा कि जो पैसा पोलिटिकल आदमियों को दिया गया है, यह गलत प्रैक्टिस डाली गई है। इस पर सख्त कदम उठाए जाने चाहिएं और एरियर्ज की रिक्वरी की जानी चाहिए। यह कहकर मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपके मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

चौधरी श्री कृष्ण हुड्डा (किलोई): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय. उप मुख्य मन्त्री तथा विल मन्त्री जी ने जैसा वर्ष 1989– 90 का बजट पेश किया है ऐसा किसी भी दूसरी सरकार ने पेश नही किया है। यह टैक्स रहित बजट है लेकिन फिर भी स्टेट में इतने विकास कार्य हो रहैं हैं। हमारी सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देकर हिन्दुस्तान में एक मिसाल कायम की है। हमारी सरकार ने वृद्धों को पैन्शन दे कर सारे हिन्दुस्तान में एक ऐतिहासिक फैसला किया है। यह भी हमारी सरकार का बहुत बड़ा काम है।

अब मैं खेल विभाग के बारे में कहना चाहता हूं कि इसके लिये बजट. में बहुत थोड़ा पैसा रखा गया है। खिलाड़ी स्टेट का नाम रोशन करते हैं। राजेन्द्र सिंह पहलवान ने चार गोल्ड मैडल जीते हैं और इन्टरनेशनल मुकाबिले में चौथे स्थान पर आया था। उसको न तो कोई ईनाम दिया गया और न ही प्रमोशन दी गई। दूसरी तरफ हिन्दुस्तान की पी० टी००षा भी चौथे स्थान पर आई थी लेकिन उसको उसकी स्टेट ने बहुत सम्मान दिया। हमारी स्टेट में राजेन्द्र सिंह जैसा पहलवान है जिसने चार

गोल्ड मैडल लिये हैं हिन्दुस्तान में ऐसा कोई पहलवान नहीं जिसने चार मैडल गोल्ड के लिए हों। मेरे गांव सांघी के एक लड़के ने एशिया में कबड्डी में गोल्ड मैडल जीता लेकिन उसको भी कोई ईनाम नही दिया गया। मैं चाहता हूं कि इस. तरह के खिलाड़ियों को ईनाम दिए जाए ताकि वे और मेहनत करें और स्टेट का नामंचा करें।

इसके बाद मैं पशु पालन के बारे में कहूंगा। इसके लिए केवल 2. 25 करोड़ रुपए रखे गए हैं जो थोडे हैं। मैं चाहता हूं कि स्टेट में अच्छी नसल की गाय और भैंसे बनाई जाएं और मिनी डेरी खोली जाएं। इससे किसानों का भी विकास होगा और स्टेट की भी आमदनी बढ़ेगी।

मैं सेल्ज टैक्स के बारे में कहूगा कि हमारी स्टेट में फिएट कार, जीप और स्वराज ट्रैक्टर्ज पर सेल्ज टैक्स ज्यादा है जबकि चण्डीगढ़ और पंजाब में कम है। इस वजह से इन वाहनो को लोग ज्यादा पंजाब और चण्डीगढ़ से खरीदते हैं। ऐसा होने से हमारी सरकार को लौस. होता है। इस बारे सरकार को जरूर सोचना चाहिए और साथ की स्टेट के बराबर टैक्स होना चाहिए। ऐसा करने से हमारी स्टेट में ज्यादा खरीद होगी और स्टेट को टैक्स के रूप में ज्यादा पैसा मिलेगा।

इसके बाद मैं अपने जिले तथा हल्के की समस्या रखना चाहता हूं। रोहतक हमेशा अपोजीशन का गढ़ रहा है। पिछले

20–35 सालों से वहां पर विकास कामों में भेद–भाव रहा है। वहां कोई अच्छा विकास कार्य महीं हुआ। अब चूंकि हमारी सरकार आई है इसलिए मैं उप मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि रोहतक जिले की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। रोहतक जिले में किलोई कांस्टिचुएंसी की सब से ज्यादा अन देखी की गई है। जब पिछले साल कहत पड़ा था तो जोहड़ों में पानी जाने का भी प्रबन्ध नहीं था क्योंकि कई गांवों में नहर का पानी लगता ही नही है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करुंगा कि किलोई हल्के की बिजली की और पानी की समस्या को जरुर हल किया जाए। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बाढ की रोकथाम के लिए हमारी सरकार ने जो 13 करोड़ रुपए का प्रोवीजन किया है, यह हमारी सरकार का बहुत अच्छा कदम है। लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि बाढ़ की रोकथाम के लिए यदि थोड़ा और पैसा दे दिया जाए तो बहुत अच्छा रहैंगा क्योंकि बाढ़ के कारण किसानों की सारी फसलें बरबाद हो जाती हैं, मकान बर्बाद हो जाते हैं। जिस किसान मजदूर का मकान गिर जाता है उसकी मकान बनाने में कई पीढ़ियों की कमाई लग जाती है।

इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि पी० डब्ल्यू० डी० को जो सड़कें बनाने के लिये पैसा दिया है, यह बहुत कम पैसा है इस पैसे को बढ़ाया जाए क्योंकि जहां पर यातायात के साधन होंगे वहां पर सरकार की इन्कम भी ज्यादा होगी। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में पिछले साल जो कहत पड़ा, ऐसा कहत कभी

भी नहीं पड़ा। लेकिन हमारी सरकार ने कहत के समय में किसानों को 24 घंटे बिजली दी। हमारी सरकार ने उस समय किसानों को 24 घंटे बिजली दे करके काल का सिरे बिजली से फोड़ दिया। इस बात का श्रेय आदरणीय मुख्य मन्त्री चौधरी देवी लाल जी और आई० पी० एम० साहब को जाता है। आई० पी० एम० साहब के महकमे के कर्मचारियों की मेहनत से कहत के समय में हरियाणा के अन्दर 24 घंटे बिजली किसानों को मिली। इस बात के लिए मैं आई० पी० एम० साहब का धन्यवाद करुंगा। हमारे प्रान्त के साथ लगता हुआ पंजाब प्रान्त है। वहां पर हर रोज उग्रवादी वारदातें होती हैं लेकिन हमारी पुलिस इतनी चुस्त है कि इसने हमारी स्टेट को आतंकवाद से बचाया हुआ है। इसके लिए मैं प्रो० सम्पत सिंह जी को बधाई देता हूं। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

डा. बृज मोहन (जगाधरी): उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1989–9० के बजट पर चर्चा चल रही है। यह बजट हमारे आदरणीय उप मुख्य मन्त्री जी ने यहां सदन में प्रस्तुत किया है जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। गुप्ता जी ने बगैर टैक्स का बहुत बढ़िया बजट हरियाणा प्रदेश को दिया है। ऐसा बजट शायद पहले कभी भी नहीं आया। इस बजट के बारे में मेरे साथी चौधरी महैंन्द्र प्रताप जी ने जो बातें कही हैं, ऐसी बातें नहीं है, यह बहुत ही सराहनीय बजट है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि

सरकारी कर्मचारियों ने चौधरी देवी लाल जी की सरकार को बनाने में अपना पूरा सहयोग दिया है। लेकिन सरकारी, कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह ठीक बात है कि सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने कुछ राहत दी है। जिन कर्मचारियों की पे में अनोमली थी उनके लिए सरकार ने पे एनोमली कमीशन गठित किया। उसकी मीटिग्ज भी हुई। उप मुख्य मन्त्री जी ने सदन को यह भी बताया था कि उस आयोग की रिपोर्ट आ गई है और उसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों की जो कुछ मांगे हैं या उनकी पे में जों ऐनोमली है, उसको दूर किया जाएगा और उनको राहत दी जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय उप मुख्य मन्त्री जी से मेरा निवेदन? है कि पे ऐनोमली कमीशन की रिपोर्ट पर जल्द से जल्द विचार विमर्श करके लागू किया जांए वरना जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो प्रोफैशनल कर्मचारी हैं और जो टैक्नोक्रेट्स हैं उनमें बेचौनी होगी। मैं कर्मचारियों की बेचौनी का एक सबूत आपके सामने पेश करना चाहूंगा। हमारे पड़ोसी प्रान्त पंजाब में डाक्टरों की एक ऐजीटेशन चल रही है। उनकी यह मांग है कि सैन्टर के मुताबिक उन्हैं सर्विस में लाभ मिलने चाहिएं। सैन्टर ने अपने डाक्टर्ज के लिए उनकी सर्विस में जो चीजें तय कर रखी हैं उसके मुताबिक पंजाब के डाक्टरों को नहीं मिल रही हैं इसलिए वहां पर उनकी ऐजीटेशन चल रही है। हो सकता है उसका असर हमारे प्रदेश में भी पड़े क्योंकि उसका असर हिमाचल में भी पड़ा है। मैडिकल प्रोफैशन के साथ साथ इंजीनियरिंग में भी उसका असर आ रहाहै। माननीय उपमुख्य मन्त्री जी से मेरा निवेदन

है कि पे ऐनोमली कमीशन की रिपोर्ट पर जल्दी से जल्दी विचार–विमर्श करके उसको लागू करें ताकि उस रिपोर्ट के पैटर्न पर पंजाब के डाक्टर्ज के साथ उनकी सरकार बात करे और वे लोग उसको मान जाएं उससे पंजाब की इस सम्बन्ध में जो समस्या है, वह भी ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं एकु बात यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की एक और ऐनोमली है और वह ऐनोमली कौंफिडैंशियल रिपोर्ट की है। मैडिकल प्रोफैशन वालों को लें, इंजीनियरिंग साइड वालों को लें या ऐजूकेशन डिपार्टमैट वालों को ले लें या किसी और विभाग के कर्मचारियों को लें उनकी कौफिडैंशियल रिपोर्ट डिपार्टमैंट की तरफ से तो लिखी ही जाती है लेकिन उनके०पर एक और तलवार ऐग्जैक्टिव की भी लटकती रहती है। इस–लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो एग्जैक्टिव की तलवार इन पर कौफिडैंशियल रिपोर्ट लिखे जाने की होती हैय उसको समाप्त किया जाये कयोंकि बाकी स्टेटों में इस किस्म की तलवार सरकारी कर्मचारियों पर नहीं है। केवल सी० आर० डिपार्टमैटल ही चलती है और यह चलनी भी चाहिए। मैं आपके माध्यम से गुप्ता जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि जब पहली बार यह सरकार 1977 में सत्ता में आई थी तो उस समय चौधरी देवी लाल जी ने पुलिस वालों पर से ऐग्जैक्टिव द्वारा सी० आर० लिखने की प्रथा को समाप्त कर दिया था लेकिन जब बंसी लाल जी दुबारा मुख्य मन्त्री बने तो उन्होंने फिर उसको रिवर्स कर दिया और पुलिस कर्मचारियों की सी० आर० ऐग्जैक्टिव के अन्डर कर दी गई। अब

फिर इस सरकार ने सत्त में आने के बाद उसको समाप्त कर दिया। इसलिए मेरा अनुरोध है कि चाहें टैक्नोक्रेटस हों, ऐजूकेशन वाले हों या डाक्टर्न हों, सब की कौंफीडैशियल रिपोर्ट डिपार्टमेंटल ही होनी चाहिए ताकि कर्मचारियों की जो मांग है वह भी पूरी हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पब्लिक हैल्थ के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इस बजट मे पब्लिक हैल्थ केलिए जो प्रोविजन रखा गया है, मैं समझता हूं वह ठीक है। लेकिन इस बारे में मेरा सरकार से यह निवेदन है कि सरकार नें जो रुरल एरिया यानी देहात में पीने के पानी के लिये जो पैसा रखा है, उसके साथ–साथ शहरों की तरफ भी सरकार ध्यान दे। मैं म्यूनिसिपल कमेटी जगाधरी की बात आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं। जगाधरी की करीब दो तिहाई बस्ती ऐसी है जहां पर पीने के पानी की गम्भीर समस्या है। पिछले साल वहां पर सूखे के कारण वाटर लैवल काफी नीचे चला गया और वहां पर आम आदमी को पीने के पानी की बहुत समस्या हो गई थी। लोगों ने बस्ती से बाहर जा कर भी हैण्ड पम्प लगाये लेकिन सूखे के कारण चूंकि वाटर लैवल नीचे चला गया था इसलिये हैण्ड पम्प भी कामयाब नहीं हो पाये। उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम आज भी 42 साल की आजादी के बाद अपने लोगों को पीने का पानी उपलब्ध न करवा सकें तो हमें इसके लिए सोचना ही पड़ेगा। यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोगों को पीने का पानी मुहैया

करवायें। मेरे शहर जगाधरी में तो पीने के पानी की बहुत ही गम्भीर समस्या है। वहां पर सीवरेज की भी और पानी के निकासी की भी गम्भीर समस्या है। बारिश के दिनों में वहां पर पानी की निकासी ना के बराबर है। इस बारे में हमारे उप मुख्य मन्डी जी जानते भी हैं। बारिश के दिनों में वहां पर बस्तियों के बीच में से पानी जाता है और खड़ा रहता है जिसके कारण लोगों के घरों में पानी चला जाता है और लोगों को परेशानी होती है। आज यह एक गम्भीर समस्या वहां पर बनी हुई है। इस बारे में मेरा सरकार से अनुरोध, है कि म्यूनिसिपल कमेटी को दिल खोल कर ग्रान्ट दें ताकि सभी म्यूनिसिपल कमेटीज अपने–अपने एरिया में पानी की निकासी का व सिवरेज का सिस्टम ठीक कर सके क्योंकि अभी तक सभी म्यूनिसिपल कमेटीज पंगु बनी हुई थी। यह सारी पिछली कांग्रेस सरकार की देन थी क्योंकि पिछली सरकार के समय में 12– 13 सालों से एक ही आदमी राज करता आ रहा था और वही सारी म्यूनिसिपल कमेटीज को लूट रहा था और हालत यहां तक खराब हो चली थी कि म्यूनिसिपल कमेटी को अपने कर्मचारियों को पे तक देने के लिए पैसे नहीं रहैं। अब हमारी सरकार ने आने के बाद वहां पर चुनाव करवा कर एक अच्छा कदम उठाया है जिसके कारण उनकी माली हालत में कुछ थोड़ा बहुत सुधार होने की संभावना हुई है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सभी म्यूनिसिपल कमेटीज को ज्यादा से ज्यादा अनुदान दिया जाये ताकि वे अपना काम ठीक प्रकार से कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में भी कहना चाहता हूं। हमारे यहां पर जगहजगह पर प्राईमरी हैल्थ सेन्टर, सब सेन्टर और डिस्पेंसरिया खोली हुई हैं। लेकिन आबादी के हिसाब से जितनी सुविधा वहां होनी चाहिए उतनी सुविधा कई जगहों पर नही है। उदाहरण के तौर पर मैं अपने जगाधरी शहर का जिकर करना चाहूंगा। वहा पर अब तक सिर्फ 30 बिस्तरों का हस्पताल है। जगाधरी एक सब डिविजनल कस्बा है। वहां की पापुलेशन भी काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। पापुलेशन के हिसाब से 30 बिस्तरों का हस्पताल बहुत छोटा है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि आबादी को देखते हुए वहां पर कम से कम 50 बिस्तरों का हस्पताल अवश्य किया जाये ताकि वहां पर डाक्टर्ज की तादाद भी बढ़ सके और मरीजों को जो असुविधा होती है वह भी न हो सके। 50 बैड का हस्पताल करने से जो बैड्ज की कमी रहती है वह नहीं रहैंगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार स्वास्थ्य विभाग को और पैसा दे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद वृद्धावस्था पैशन के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। यह स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम है जो कि चौधरी देवी लाल की सरकार ने लागू की हैं। इस स्कीम की चर्चा देश में ही नहीं विदेशों में भी हुई है। इस स्कीम के बारे में कुछ लोगों ने जानबूझ कर ऐसा कार्य किया है कि जिन लोगों की उम्र 65 साल से कम थी उनको तो पैशन मिल रही है लेकिन जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा थी, उन्हैं पैशन नहीं मिल रही है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बारे ठीक प्रकार से छानबीन करवाई जाए और जिन लोगों ने इसमें गड़बड़ी की है या गडबडी कर रहैं हैं उन्हैं सजा भी मिलनी चाहिए। जो सही लोग हैं उनको पैशन भी मिलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद अगली बात मैं ऐक्साइज एण्ड टैक्सेशन के बारे में कहना चाहता हूं। आज ही हमारे ऐक्साइज एण्ड टेक्सेशन मिनिस्टर साहब का व्यान आया है कि टैक्स से सरकार की आमदनी बढ़ी है। पिछले साल की बजाय 90 करोड़ रुपये के टैक्स अधिक आये हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है। इसमें मेरे हल्के, जगाधरी का भी सहयोग रहा है। जगाधरी एक बहुत बड़ा इण्डस्ट्रियल टाउन है। पिछले सात्र सरकार ने टैक्स में थोड़ी–बहुत छूट दी थी जिस के कारण टैक्स की प्राप्ति ज्यादा हुई है। मैंने पहले भी कहा था कि सेल्ज टैक्स वाले जो नाजायज चौकिंग करते हैं उसको समाप्त किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई चर्चा के दौरान यह बात आई थी कि इस साल सरकारी तौर पर पण्डित जवाहर लाल नेहरु की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। इसी तरह के एक और महान व्यक्ति की जन्म शताब्दी हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, जहां भारतवासी रह रहैं हैं, मनाई जा रही है। वे हैं डा० केशव बलीराम हैडगेवार, जो आर० एस० एस० एस० के फाउंडर हैं उनकी जन्म शताब्दी 7 अप्रैल तक चलने वाली हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि हरियाणा में भी उनकी जन्म

शताब्दी मनाई जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इन बजट प्रस्तावो का समर्थन करता हूं और आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। (इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)।

श्री उपाध्यक्षः अब कान्ति प्रकाश भल्ला बोलेंगे।

श्री हीरा नन्द आर्यः उपाध्यक्ष महोदय, क्या मुझे बोलने का टाईम दिया जाएगा या नही?

श्री उपाध्यक्षः आप अपनी पार्टी से अपना नाम भिजवाए। मेरे पास जनता दल से भी नाम आए हैं और बी० जे० पी० की तरफ से भी नाम आए हैं।

श्री हीरा नन्द आर्यः मैं तो आपसे टाईम मांग रहा हूं क्योंकि आप कुर्सी पर बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्षः अपि अपनी पार्टी से अपना नाम भिजवाए मुझे क्यों पूछते हो?

श्री हीरा नन्द आर्यः उपाध्यक्ष महोदय, अगर मुझे टाईम नहीं दिया जाना है तो मैं चलता हूं।

श्री बनारसी दास गुप्ताः आर्य साहब, आप बैठिये आपको समय मिलेगा।

श्री हीरा नन्द आर्यः धन्यवाद जी।

श्री कान्ति प्रकाश भल्ला (कालका): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मन्त्री महोदय ने जो वर्ष 1989–90 का बजट पेश किया है उसके लिए उन्हैं बधाई दूंगा। यह बजट कर रहित है और जनता के लिए बहुत लाभदायक है। जब से चौधरी देवी लाल की सरकार सत्ता में आई है इसे कई दैवी विपत्तियों का सामना करना पड़ा है। पहले जबरदस्त ड्रौट आया और उसके बाद राज्य को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा जिससे राज्य का बहुत नुकसान हुआ। इन सबके बावजूद भी चौधरी देवी लाल की सरकार ने हरियाणा के लोगों को बहुत सी राहतें दी हैं। जहां एक ओर ओल्ड पैंशन की बात है तो दूसरी ओर कर्जे माफी की बात है। इस सरकार ने इस प्रकार की राहतें हरियाणा की जनता को प्रदान की हैं। सरकार के ये कार्य अत्यन्त ही सराहनीय हैं और इस सरकार ने जो बजट पेश किया है वह बहुत ही लाभदायक है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के की कुछ थोड़ी सी समस्याएं हैं जो मैं माननीय उप–मुख्य मन्त्री महोदय के जेरेगौर लाना चाहता हूं। हमारे बजट में इरीगेशन के लिए बहुत सी स्कीमें हैं। मेरा हल्का कालका पहाड़ी तलहटी में बसा हुआ है। इसके एक तरफ घग्घर नदी और दूसरी ओर सरसा नदी बहती है। यहां के लोगों की रोजी–रोटी खेती–बाड़ी पर आधारित है। सिंचाई के लिए नदियों में पानी उपलब्ध है। टयूबवैल्ज लगाने की तो आवश्यकता नही है। लिपट स्कीम से बहुत से गांव सैराब हो सकते हैं। सरसा नदी से भी 20–30 गांव सैराब हो सकते हैं। इस पर सरकार का ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा और बिजली भी

ज्यादा नहीं लगेगी। इसके अलावा निवेदन है कि घग्घर नदी से निकलने वाली बहुत सी कूले सरकार की तरफ से पक्की की जा चुकी हैं लेकिन बहुत सी कूले अभी मेरे हल्के में पक्की होने से रह गयी हैं। जो कूले बाकी रह गयी हैं उन्हैं किसी तरह से पक्का किया जाना चाहिए। हमारे इलाके में एक सकेतड़ी कूल है। वह कुछ एरिया को सैराब करती है। यह मिलटरी कैन्टोनमैंट चण्डी मन्दिर के बीच से गुजरती है। उसके लिए आज तक कोई फण्ड मुहैया नहीं किया गया है जिसके कारण वहां तीन चार गांवों में कच्चे खालों से आबपाशी होती है। यह कूल कैन्टोनमेंट सें गुजर कर मन्शा देवी मन्दिर में आती है। इस कूल का ज्यादा से ज्यादा सुधार किया जाये ताकि तीन चार गांवों जो चण्डीगढ़ के पास लगते हैं उनकी जमीन की भी आबपाशी हो सके। दूसरे इस पुल पर लिपट स्कीम भी चालू की जाये। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारे हल्के में बहुत से डैम बने हुए हैं और बनाये जा रहैं हैं लेकिन घग्गर नदी तकरीबन हमारे हल्के से शुरू होती है और टांगरी नदी भी हमारे हल्के से गुजरती है और इसमें कई और भी नदियां शामिल होती हैं। बरसात के दिनों में ये नदियां फतेहाबाद और सिरसा के एरिया में बहुत ज्यादा नुक्सान पहुंचाती हैं। काफी देर पहले घग्गर पर बान्ध बनाने की स्कीम तैयार की गई थी और चौधरी देवी लाल ने मोरनी के पास एक स्कीम बनायी हुई है या बनायी जा रही है। इसके बारे में उप–मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि टांगरी और घग्गर के०पर की तरफ डैम बना कर पानी को आबपाशी के लिए रोका जाये। एक तो वहां पर जो जमीन है

वह सैराब हो जायेगी और दूसरे फ्लड आते हैं उनके रोकने में काफी इमदाद मिलेगी। इस तरह की और भी स्कीमें बनायी गई हैं जिनके लिए इस साल बजट में पैसा रखा गया है। उसमें से कुछ पैसा स्पैशल तौर पर सैमी हिल्ली एरिया के लिए भी दिया जाये क्योंकि वहां से तेज रफ्तार से पानी आता है और डाउन एरियाज में फतेहाबाद और सिरसा के किसानों को नुक्सान पहुंचाता है।

12.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले बोलने वाले चौधरी रणजीत सिंह जी ने वीडियो के बारे में कहा। यह बात उनकी बिल्कुल दरुस्त है। जब से यहां पर वीडियो शुरू हुए हैं तब से सिनेमा फेल हो गये हैं और सरकार को जो ऐन्टरटेनमेंट टैक्स मिलता है वह बिल्कूल खत्म हो गया है। सिनेमा एयर–कन्डीशनिंग के बारे में

उप–मुख्य मंत्री महोदय से दरखास्त करूंगा कि उन्हैं एयर–कन्डीशन करने की आवश्यकता नहीं है। जो शहरों में सिनेमा हैं, उन्हैं एयर कन्डीशन करने की क्या आवश्यकता है क्योंकि अगर गर्मी के दिनों में सिनेमा को बिजली दी जायेगी तो उसका असर ऐग्रीकलचर पर पड़ेगा। मेरी दरखास्त है कि सरकार इस बात पर गौर करे और सरकार ने जो शर्त रखी है उसे डैफर किया जाये। हुड्डा के बारे में कल मेरे सवाल के जवाब में चौधरी वीरेन्द्र सिंह, आई० पी० एम० साहब ने कहा कि सरकार के पास

इतना रुपया नहीं जो सरकारी कर्मचारियों के लिए इतने ज्यादा मकान बुना सकें जितनी उनकी आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पंचकूला में बहुत सी ऐसी कोआप्रेटिव हाउसिंग सोसाइटीज है जिन्होंने सरकार से अपील की हुई है कि उन्हैं पूरी कीमत पर जमीन दे दी जाये, इस प्रकार की 60–70 हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो जमीन मांगती हैं। जमीन हमारे पास बहुत है। अगर कम है तो ऐक्वायर कर ली जाये। घग्गर के पार बहुत जमीन पड़ी है। इस किस्म की सोसाइटीज को जमीन दे दी जाये ताकि वे अपने पैसे से रहने के लिए मकान बना सके। ऐसा करने से मकानों की समस्या भी हल हो जाएगी और सरकार के सामने इस काम के लिए बजट की जो समस्या है, वह भी दूर हो जाएगी। ऐसा करना, उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारियों की भलाई के लिए एक बहुत बड़ा कदम है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से उप मुख्य मन्त्री महोदय से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हुड्डा द्वारा जितनी भी गांवों में जमीन ऐक्वायर की जाती है, वहां पर सरकार ने यह पालिसी बना रखी है कि लोगों को उजाड़ने से पहले उनको बसाने का काम किया जायेगा। उनको रिहायशी प्लाट्स दिये जायेंगे। उसैके बाद उनको वहां से उजाड़ा जायेगा। लेकिन कुछ इस तरह की बातें सामने आयी हैं जो इस पालिसी के अगेन्सट हैं। हमारे इलाके कालका के ही एक गांव की बात है, जो इसके बिल्कुल विपरीत है। रैली गांव के पास एक रैला गांव है, उसको

उजाड़ने से पहले वहां के लोगों को कोई न कोई प्लाट्स दिये जायें ताकि वहां के लोग अपना सामान उठाकर नयी बस्ती में जा सकें और अपना मकान तामीर कर सकें इंडस्ट्री के बारे में जो बजट रखा गया है, उस बारे में मैं दरख्वास्त करूंगा कि वह तो ठीक है लेकिन मैं अपने उप–मुख्य मंत्री महोदय की सेवा में एक और गुजारिश करूंगा। कालका हल्के का०पर का एरिया हिमाचल से लगता है औप, नीचे का एरिया पंजाब से लगता है। वहां पर इंडस्ट्रीज लगाने के लिये सबसिडी और दूसरी रियायतें और फैसिलिटीज दी जा रही हैं। देखना यह है कि इस बैल्ट के अन्दर जो हिमाचल और पंजाब के साथ–साथ लगती है, बहुत कम इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। कालका के पास बहुत बड़ा ऐसा एरिया पड़ा है जो बैरन और अन–इरीगेटिड है। वहां पर हिमाचल के साथ लगते हुए इलाके में इंडस्ट्रीज लगाने के लिये बढ़ावा देने के पश्चात अगर वहां पर इंडस्ट्रीज लगायी जायें तो इससे जहां सरकार को टैक्स का फायदा होगा वहां जनता की भी बेरोजगारी दूर हो सकती है। मैं इस बारे में सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कालका के एरिया में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिये परवाणु, बद्दी, बरोटीवाला, जोकि हिमाचल प्रदेश में है, जो रियायतें दी गई हैं, वैसी रियायतें और फैसिलिटीज कालका के साथ लगते हुए एरिया में इंडस्ट्रीज लगाने के लिये दी जायें ताकि वहां के एरिया की बेकारी दूर हो और सरकार को भी इससे लाभ हो सके। अभी बसिज के बारे में चौधरी धर्मबीर सिंह जी से मैंने बात की थी। मेरा इलाका सैमी हिल्ली एरिया है। उस इलाके में भी बसिंज

चलाई जायें–। खास तौर पर कालका का मैं जिक्र करूंगा। मेरे हल्का के कालका शहर में कोई बेस– स्टैड नहीं है। वहां पर भी यदि बसस्टैंड बनाने के बारे में ध्यान दिया जायेगा, तो मैं सरकार का धन्यवादी हूंगा।

एक बात मैं हैल्थ डिपार्टमैंट के बारे में कहना चाहूंगा। मेरे हल्के में दो जगहैं ऐसी हैं, जहां से डिस्पैसरिया शिफ्ट की जा रही हैं। एक डिस्पैसंरी गांव कजाना में है। वहां पर 20 साल से यह डिस्पैसंरी चल रही थी। लेकिन अब उसको शिफट करके गांव बाढ़गोदाम ले जाया जा रहा है। इसी तरह से दूसरी डिस्पैसंरी गांव भगवानपुर में 25 साल से चल रही है। उसको भी शिफ्ट करने के आर्डर जारी कर दिये गये हैं कि यह डिस्पैंसरी कोटियां में चली जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, 20–25 साल से जो डिस्पैसरिया वहां पर चल रही हैं, उनको वहीं पर चलने दिया जाये। सरकार अगर चाहैं तो वहां पर नयी डिस्पैसंरियां खोल दे जहां पर इन्हैं शिफ्ट किया जा रहा है। (घंटी) क्योंकि समय कम है, इसलिये मैं ज्यादा न कहते हुए जो बजट माननीय उप मुख्य मन्त्री ने पेश किया है, उसके लिये उनका धन्यवाद करता हूं।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): उपाध्यक्ष महोदय, आज बजट पर चर्चा चल रही है। जो बजट आदरणीय उप मुख्य मन्त्री महोदय ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खडा हुआ हू।

श्री उपाध्यक्षः आर्य जी, 5 मिनट में सारी बातें कह लेना।

श्री हीरा नन्द आर्यः ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी भी देश, प्रदेश या समाज के लिये सबसे जरूरी चीज शिक्षा होती है। शिक्षा के मामले में जब तक प्राथमिक विद्यालयों के स्तर पर शिक्षा में नुसार नहीं किया जाता उस वक्त तक कोई भी प्रदेश या समाज तरक्की नही कर सकता 1 हमारी सरकार ने प्राइमरी स्कूलों के लिये डायरैक्टोरेट की जो स्थापना की है, इसका 1978 में फैसला हुआ था और इस पर कार्यवाही भी शुरू की गयी थी लेकिन बीच में सरकार दूसरी आ गई जिसके कारण वह मामला लटक गया। इस बार हमारी सरकार ने आते ही दुबारा से मामला टेक अप किया और उस पर कार्यवाही शुरू की। इस विषय में जो काम किया गया है उसकी तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। देहात के बहुत से स्कूलों में चाहैं वह प्राईवेट स्कूल हैं या गवर्नमैंट स्कूल हैं उनमें टीचर्ज और स्टूडैट्स की रेशों बढ़ी है। यह रेशों ठीक नहीं है। शहरों में जो प्राईवेट स्कूल हैं उनमें फिकटीशियस नाम से टीचर्ज रख लेते हैं और रिकार्ड दिखाकर सरकार से ग्रान्ट लेते हैं। इस को रेशनेलाइज किया जाना चाहिए। देहात के स्कूल्ज में एक सौ पचास या दो सौ बच्चों पर एक ही टीचर होता हु इसलिए वहां पर और पोस्ट्स सैक्शन की जानी चाहिए। प्राईवेट स्कूलों को सरकार ग्रान्ट देती है लेकिन टीचर्ज की नई पोस्ट्स सैक्शन नही

की गई जबकि बच्चों की संख्या इस बीच काफी बढ गई है। इसलिए प्राईवेट स्कूलों को तब तक ग्रांट न दी जाए जब तक वे टीचर्ज की और पोस्ट्स सैक्शन न कर लें। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा जबरदस्ती नहीं दिलाई जा सकती। पढ़ाने के लिए अगर दिमाग शान्त न हो और टीचर की तसल्ली न हो तो ठीक प्रकार से शिक्षा नहीं दी जा सकती। हमारी सरकार ने टीचर्ज और दूसरे कर्मचारियों की बहुत सारी मांगे मान ली हैं लेकिन कई बार बहुत से ऐसे फैसले हो जाते हैं जिससे उनमें बेचौनी हो जाती है। उदाहरण के लिए एक बात मैं विल मण्डी महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं। सरकार द्वारा कैजुअल लीव और मैडिकल लीव के बारे में फैसला लिया गया है कि अगर कोई कर्म चारी एक दिन भी बीमार हो जाए तो उसको दस दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। कितनी हैरानगी की बात है कि एक दिन बीमार होने पर दस दिन की छुट्टी लेनी पड़ रही है। इस बात से कर्मचारियों में बहुत बेचौनी है और ऐसा करना बहुत ही अनावश्यक है। अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों ने राजसत्ता बदलने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और प्रदेश की तरक्की में भी कर्मचारियों का बहुत बड़ा हाथ है।

अध्यक्ष महोदय, डाक्टर्ज को नौन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाता है ताकि वे प्राईवेट प्रैक्टिस न करें। आज कल टीचर्ज काफी ट्यूशन करते हैं। वे स्कूल्ज में कम पढ़ाते हैं और ज्यादा

ट्यूशन करते हैं। मेरा सुझाव है कि टीचर्ज को भी नौन ट्यूशन अलाउंस दिया जाना चाहिए। उनको कहा जाना चाहिए कि वे ट्यूशन न करें और सरकार उनको नौन ट्यूशन अलाउंस देगी। यह अलाउंस इसी तरह दिया जाना चाहिए जैसे कि डाक्टर्ज को दिया जाता है। चटोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट में जो बातें दे रखी हैं उन बातों की तरफ ध्यान देकर तथा दूसरी बातों की तरफ ध्यान देकर सरकार को सारी बातें मान लेनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पहले भी कहा है कि धारा 311 कर्मचारियों पर लागू नहीं की जाएगी। मैं चाहता हूं कि सरकार कर्मचारियों को दुबारा आश्वासन दे कि जो धारा 311 है उसको कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जाएगा और किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे एक आदरणीय साथी ने जिक्र किया कि हर एक जिले में एक दो पब्लिक स्कूल खोले जाएं। अध्यक्ष महोदय, आज प्राईवेट और पब्लिक स्कूल वालों ने एक प्रकार से दुकानें खोल रखी हैं और उन्होंने लूट मचा रखी है। इसलिए उन दुकानों क्रो समाप्त किया जाना चाहिए। जब तक आप कौमन स्कूल की दशा नही सुधारेंगे तब तक आम आदमी की हालत नही सुधरेगी। अगर हम पब्लिक स्कूल खोलेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि जिन स्कूलों में 99 प्रतिशत जनता के बच्चे पढ़ते हैं वह स्कीम फेल हो गई। हमारा प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि जो प्राईवेट पब्लिक स्कूल हैं वे लूट न मचाएं।

स्पीकर साहब, अभी पिछले दिनों कोआप्रेटिव विभाग की भी काफी चर्चा होती रही। आदरणीय मुख्य मन्त्री महोदय व सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने सभी शिकायतों के खिलाफ इंक्वायरी इंस्टीच्यूट कर दी लेकिन फिर भी इसके बारे में काफी चर्चा चलती रही। स्पीकर साहब, इसी एक विभाग में घपले नही हैं और दूसरे कई विभाग भी हैं। आप ट्रांसपोर्ट विभाग को ही ले लीजियेगा। अगर इस विभाग की बाकायदा जांच पड़ताल की जाये तो काफी बातें आपके नोटिस में आ जाएंगी। इस विभाग में 50–50 सालों के बूढे, ड्राईवर सिफारिशी भर्ती कर लिये गये हैं जिससे इस विभाग के अन्दर जीवन के खतरे का भी सवाल उठ खड़ा हुआ है। आज जबकि सारे हिन्दुस्तान में हरियाणा ट्रांसपोर्ट का नाम मशहूर है वहाँ कहीं अब प्रदेश ट्रांसपोर्ट की बदनामी न हो जाए. इसलिये मेरी सरका से प्रार्थना है कि इस बात की जांच की जाए। यह बात भी हमारे नोटिस में आई है कि उनके पास ड्राइविंग लाइसैन्स भी जैनुअन नहीं हैं। कंडक्टर्ज भी नकली टिकटें लेकर चलते हैं। जब उन्हैं पकड़ा जाता है तो०पर का इशारा करके सब कुछ दबा दिया जाता है जिससे सरकार के खुजाने पर काफी बोझ पड़ता है। इस बात की जांच होनी चाहिये। मैंने 9 तारीख को मुख्य मन्त्री महोदय को एक पत्र भी लिखा था कि स्पेयर पार्टस में भी काफी घपला हो रहा है। जहां 16 गेज की चादरें चाहिये वहां पर 18 गेज और जहां 18 चाहिये वहां 20, 21 गेज चादरे बरती जा रही हैं। मतलब यह कि माल बड़ा ही इफीरियर इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से अकेले तालू गांव की बात मैं आपको बताता हूं। (शोर)

Mr. Speaker : Please wind up.

श्री हीरा नन्द आर्य: वहां के एक परिवार के लोगों को हैल्पर के तौर पर पहले रखा गया और फिर उनको कंडक्टर्ज बनाया गया। उसके बाद रेगुलर कर दिया गया। अगर इसी तरह से करना था तो फिर एस० एस० बोर्ड बनाने की क्या आवश्यकता है? स्पीकर साहब, अकेले भिवानी डिपो में 70 लाख के लगभग घाटा इस साल बताया जाता है। ऐसा इसलिये हुआ थैं कि जो ड्राइवर्ज भर्ती किये गये हैं, वे 50–50 सालों के बुजुर्ग हैं जो कि तीन–तीन बार ऐक्सीडैन्ट कर चुके हैं। एक गाड़ी छोड़ते हैं, दूसरी पकड़ लेते हैं।

Mr. Speaker : Arya ji, please wind up now.

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों भिवानी से अजमेर रूट पर जाने वाला एक कंडक्टर भी पकड़ा गया जिसके पास से 960 रुपये की नकली टिकटें पकड़ी गयीं। इस बारे में, मैंने सम्बन्धित मन्त्री महोदय को पत्र लिखा लेकिन आज तक मुझे उसका कोई उत्तर नहीं मिला। इस बारे में अखबारों में भी काफी चर्चा होती रही। सरकार को अवश्य इस मामले की छानबीन करनी चाहिए। इसी तरह से 28 फरवरी की बात है। हमारी पार्टी के एक वफादार कार्यकर्ता भिवानी से लोहारू जा रहैं थे। कोई लगभग 11 बजे का समय था बाई चांस रास्ते में ट्रैफिक मैनेजर टकर गया। उनको भी किसी तरह से यह जानकारी थी कि वह कंडक्टर गल्त प्रकार की हरकत करता है। लेकिन जब

इस कार्यकर्ता द्वारा उनके नोटिस में यह बात लाई गई तो सारी की सारी बस में लगभग तीन चार सौ रुपये की बोगस टिकटें, जिसे डिपार्टमैंट वाले खद्दर टिकटें कहते हैं, मिलीं। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी जानकारी के अनुसार उस कंडक्टर पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं बनाया गया। वे कहते हैं कि यह राजनैतिक मामला है और हम०पर तक देते हैं। (विघ्न) यह कितनी बुरी बात है? यह तो सरासर हमारी सरकार की बदनामी है। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह कहूंगा कि जहां चौधरी देवी लाल जी के नेतृत्व में यह सरकार अच्छे काम कर रही है वहां इस तरह का भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिये।

Mr. Speaker : Arya Ji, please take your seat now.

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर सर, मैं एक बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि किस प्रकार एक आई० ए० एस० कमिश्नर, रणजीत ईशर की ट्रांसफर की गयी।

Mr. Speaker : I won't allow it. Mr. Arya, please take your seat now. You were requested to speak for five minutes, but you have already taken more than 10 minutes. Now, please take your seat.

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मेरी बात तो आप पूरी होने दीजियेगा। (शोर) मैं दो मिनट में अपनी बात कह कर खत्म करता हूं। (शोर)

श्री अध्यक्ष: अब आप कृपया बैठें।

श्री हीरा नन्द आर्य: अगर आपकी यही इच्छा है, तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री जय सिंह राणा (नीलोखेड़ी): स्पीकर साहब, जो बजट हमारे उप मुख्य मन्त्री जी ने इस महान सदन के अन्दर पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह एक कर रहित बजट है इसलिए मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। इसमें जनता के हित की बातें हैं, आम जनता को लाभ पहुंचाने की बातें हैं। किसान और मजदूर के हित को ध्यान में रख कर यह बजट बनाया गया है। इसलिए उप मुख्य मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। अब मैं आपके द्वारा अपने हल्के की कुछ समस्याएं सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहले मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूं। जब से चौधरी देवी लाल की सरकार बनी है तब से बिजली ठीक मात्रा में लोगो को मिल रही है, यह बहुत सराहनीय बात है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नीलोखेड़ी में अमीन और सगा में दो 33–33 के० वी० के सब स्टेशन हैं जो ओवर लोडिड हैं। जब सभी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली मिलती है उस समय भी हमारे यहां कम बिजली मिलती है। उसका कारण इन सब स्टेशनों का ओवर लोडिड होना है। आई० पी० एम० साहब भी यहां बैठे हैं, मैं उप मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि उनकी क्षमता या तो बढ़ाई जाए वरना जब तक क्षमता नही बढ़ाई जाती तब तक बड़े ट्रांसफारमर लगा दिए. जाएं ताकि लोगों की समस्या खत्म हो सके।

अब मैं सड्कों के बारे में कहना चाहता हूं। सड्कों की हालत बहुत खस्ता है। कुछ तो इस साल अधिक वर्षा होने के कारण सड़कें खराब हुई हैं और कुछ पहली सरकार ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि मेरे हल्के में बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो चलने के काबिल भी नहीं हैं, उनकी मुरम्मत करवाई जाए। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कहना चाहूंगा कि यह एक बहुत जरूरी मामला है। मेरे हल्के नीलोखेड़ी में तरावड़ी में एक पी० एच० सी० है और नीलोखेडी में एक कम्यूनिटी सैटर है। मेरे ख्याल में तरावड़ी में जो पी० एच० सी० है उसका भवन 1947 से पहले का बना हुआ है। यहां पर मरीजों को ठहरने के लिए कोई जगह नही है। अगर है तो इस काबिल है कि मरीज को भी खतरा है और डाक्टर को भी खतरा है। इसी तरह से 1947 के बाद जब नीलोखेड़ी कस्बा बसाया गया तो उसके हस्पताल का भवन भी उसी समय का बना हुआ है। मैं चाहता हूं कि तरावडी और नीलोखेड़ी दोनों जगहों पर नए भवन बनाए जाएं क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश का सारा पानी उनके अन्दर आ जाता है और वहां पर मरीजों को ठहरने के लिए जगह नही रहती। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वहां पर नई बिल्डिग वनाई जाएं। इसके अलावा किरमच में पी० एच० सी० मंजूर हुआ है उसका काम जल्दी शुरू करवाया जाए। मेरे हल्के में सोंकड़ा, बहरसाल और भराणा ऐसे गांव हैं जिनकी चार या पांच हजार की आबादी है उनमें स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं। इस सरकार ने इस बजट में 400 गांवों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध

कराने के लिए टारगेट रखा है। मेरे हल्के में एक समाना गांव है जो जी० टी० रोड पर है। इतनी बारिश होने के बावजूद भी उस गांव का वाटर लैवल लगभग 70 फुट नीचे चला गया है। उस गांव के लोगों को पीने के पानी की बहुत भारी समस्या है। इसलिए मैं सरकार से विनती करूंगा कि उस गांव में वाटर वर्कस बनाने कौ इन्तजाम किया जाए ताकि लोगों की पीने के पानी की समस्या दूर हो।

अब मैं एक बहुत गम्भीर मामले के बारे में कहना चाहूंगा और वह है कानून और व्यवस्था का मामला। हमारी स्टेट की कानून और व्यवस्था बहुत सराहनीय है। हमारी स्टेट में उग्रवाद के कारण पिछले सालों में कई घटनाएं हुई और उन घटनाओं में बहुत बेकसूर लोग मारे गए लेकिन हमारी पुलिस ने स्टेट के अन्दर कानून और व्यवस्था को बरकरार रखा और जिन लोगों ने बेकसूर लोगों को मारा उनको गिरफ्तार करने में बड़ी तेजी और फुरती दिखाई। लेकिन पुलिस के बारे में मैं सदन में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हरियाणा की पुलिस ने एक ही समुदाय के कुछ लोगों को यातनाएं दी हैं जोकि एक बहुत ही गलत बात है। एक ही समुदाय के सारे लोग कसूर नही करते, सारे लोग अपराधी नही होते लेकिन पिछले कुछ समय में एक ही समुदाय के लोगों को हमारी पुलिस की यातनाएं सहनी पड़ी और हमारी पुलिस ने उन बेकसूर लोगों को उनके घरों से उठाया और उन्हैं यातनाएं दीं। सरकार से मेरा निवेदन है कि पीछे जो हो

गया सो हो गया लेकिन इस समय सरकार को ऐसी सावधानी बरतनी चाहिएं ताकि दोबारा ऐसी बातें न हों। इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मुझे भी बोलने के लिए टाईम दिया जाए क्योंकि मैं बजट पर नहीं बोला हूं। (शोर)

श्री अध्यक्षः आप कृपया वैठ जाएं। (शोर)

सेठ लछमन दास बजाजः स्पीकर साहब, बजट पर बोलने के लिए मेरा नाम तो पार्टी की तरफ से आपको दिया हुआ है इसलिए मुझे बोलने का समय दिया जाए। **श्री अध्यक्षः** आप कृ पया बैठ जाएं अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब रिप्लाई देंगे। (शोर)

वाक आउट

श्री कुन्दन लाल भाटियाः स्पीकर साहब, मैं काफी देर से बोलने के लिए खड़ा हो रहा हूं इसलिए बजट पर बोलने के लिए मुझे समय दिया जाए।

श्री अध्यक्षः अब चूंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने रिप्लाई देनी है इसलिए समय नही है। आप कृपया बैठ जाएं। (शोर)

श्री कुन्दन लाल भाटियाः अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल पांच मिनट ही बोलने दें।

श्री अध्यक्षः जी नहीं, आप कृपया बैठ जाएं। (शोर)

श्री कुन्दन लाल भाटियाः यदि मुझे बोलने के लिए समय नहीं दिया जाता तो मैं वाक आउट करता हूं। (शोर)

(इस समय श्री कुन्दन लाल भाटिया सदन से वाक आउट कर गए।)

वर्ष 1989– 90 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, बजट पर चर्चा हो रही है और बहुत से मैम्बर साहैंबान ने बजट के बारे में अपने अपने ख्यालातों का इजहार किया है। उनकी सभी बातों का तफसील से तो आदरणीय उप मुख्य मंत्री जी जवाब देगे, मैं तो केवल डाक्टर मंगल सैन जी ने अपने भाषण मे हुड्डा के बारे में जो बात कही उसके बारे में बताना चाहता हूं। डाक्टर साहब ने कहा कि जहां तक हुड्डा का ताल्लुक है उसकी छवि ठीक नहीं है। स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि हुड्डा के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी बिना पर यह कहा जाए कि उस महकमे की छवि ठीक नहीं है। शुरू शुरू में जब यह सरकार बनी उस समय कुछ अखबारात में यह बात आई थी, उसके बाद मेरे ख्याल में हुड्डा के बारे में अखबारों में चर्चा आनी बंद हो गई किसी प्रकार की. कोई बात हुड्डा की अखबारों में नहीं आई। अगर उस महकमे में ऐसी कोई बात है और डाक्टर साहब के नोटिस में वह है तो वे हमारे नोटिस में

उस बात को लाते। मैं यह कहना चाहता हूं कि हुड्डा महकमे में किसी प्रकार की कोई बात नहीं है और वह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। किसी प्रकार की कोई शिकायत किसी की तरफ से कम से कम सरकार को नहीं मिली है। उन्होंने बोलते हुए यह भी कहा कि उन लोगों के खिलाफ यानी उन आफिसर्ज के खिलाफ ऐक्शन लिया जाये जो किसी मिसिंग फाईल के लिए जिम्मेवार थे। मैं सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि उस पर चीफ सैक्रेटरी लैवल पर ऐक्शन के लिए विचार विमर्श हो रहा है, उस पर कार्यवाही हो रही है और जो भी कोई कसूरवार होगा उसको चीफ सैक्रेटरी साहब की तरफ से वाजिब सजा दी जायेगी। यहां पर मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि डाक्टर साहब ने बोलते हुए कहा कि कोई बिल इसी मौजूदा सत में फरीदाबाद और गुड़गांवा की अलग से अथौरिटीज बनाने के लिए सरकार की तरफ से लाया जा रहा है। यह सही बात है कि सैशन के इसी सत्र में गुड़गांव और फरीदाबाद के लिए इन्डीपैन्डैट डिवैल्पमैंट अथौरिटी बनाने के लिए एक बिल लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बिल लाया जाना जरूरी नहीं है। स्पीकर साहब, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यह जरूरी है क्योंकि गुड़गांव और फरीदाबाद में बड़ा भारी प्रैशर है और वहां पर पेस औफ डिवैल्पमैंट को ऐक्सलैरेट करने के लिए इन अथौरिटीज का होना जरूरी है ताकि सभी जरूरी फैसले उसी लैवल पर ले लिए जायें और बहुत कम फैसलों के लिए ही फाईल यहां पर आये। इन्टेग्रेटिड और फास्ट

डिवैल्पमैंट के लिए यह आवश्यक है कि ये अथौरिटीज बनाई जायें। जब यह बिल आयेगा और माननीय सदस्य बोलेंगे तो उस समय मैं इस बिल के बारे में बिस्तार से चर्चा करूंगा। एक बात उन्होंने यह कही कि अगर ये अथौरिटीज बनाई ही जायें तो जो दिल्ली के निकट के कोलोनाइजर्ज हैं उनको अटैच न किया जाये। डाक्टर साहब किन कौलोनाइजर्ज का जिकर करना चाहते थे उनका उन्होंने नाम नही लिया यानी डाक्टर साहब ने इस बारे में विस्तार से अपनी बात नहीं कही। साथ ही डाक्टर साहब ने एक बात यह कही कि हुड्डा के द्वारा जो प्लौट दिये जाते हैं उनको औक्शन कें द्वारा न दे करके लाटरी द्वारा दें। इस संबंध में मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हुड्डा ने इसके लिए बाकायदा एक पालिसी ले डाउन की हुई है, उसी के अनुसार प्लाटों को दिया जाता है। मौजूदा पालिसी के तहत कमर्शियल प्लौट तो औक्शन द्वारा दिए जाते हैं और रिहाडशी प्लौट जब कोई सैक्टर कटता है तो उसमें रेशो फिक्स की जाती है कि इतने प्लौट ओक्शन के जरिए जाएंगे और इतने प्लाट लाटरी द्वारा दिए जाएंगे। यह सिस्टम भली भांति चल रहा है। इसलिए इसमें किसी रद्दो–बदल की आवश्यकता नहीं है। साथ ही डाक्टर साहब ने यह कहा कि गुड़गांव और फरीदाबाद के लिए अलग से अथौरिटीज बनाते समय हुड्डा के एम्पलाइज के इन्ट्रैस्ट का पूरा ध्यान रखा जाये। इस संबध में मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि उनके इन्ट्रैस्ट का पूरा

ध्यान रखा जायेगा। किसी को किसी प्रकार का नुक्सान नहीं होने देंगे। सभी हुड्डा ऐम्पलाइज का इन्ट्रैस्ट हम वाच करेंगे।

उप मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, 8 मार्च को मैंने सदन में जो बजट प्रस्तुत किया था उसकी सर्वत्र सराहना की गई है। अनेक सदस्यों ने मुझे कर मुफ्त बजट प्रस्तुत करने पर बधाई दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का हृदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे कर मुफ्त बजट पेश करने पर बधाई दी है। मैं सभी सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस बधाई के वास्तव में यदि कोई पात्र हैं तो वे हैं इस सदन के नेता और हरियाणा के मुख्य मन्त्री चौधरी देवी लाल जी। चौधरी देवी लाल जी ने हरियाणा के लिए इन्साफ मांगते हुए जो संघर्ष किया था और उस समय जनता के साथ जो वायदे किए थे उनको पूरा करने के लिए एक प्रगतिशील नीति उन्होंने अपनाई थी उसकी घोषणा की थी। इस प्रगतिशील नीति को अमली रूप देने के लिए अध्यक्ष महोदय इस प्रकार का बजट सदन के सामने पेश किय गया। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारा प्रदेश, केवल प्रदेश ही नही बल्कि सारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी हमारा किसान है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप भी कृषि करते हैं, इसलिए आप जानते हैं कि सारे प्रदेश की अर्थ–व्यस्था कृषि पर निर्भर करती है। यदि किसान को हर प्रकार की सुविधा दी जाए, किसान को अच्छा पानी, अच्छा बीज, अच्छी बिजली दी जाए,

सुधरा हुआ बीज और खाद मिले तो खेती की पैदावार अच्छी होगी। किसान को ये साधन उपलब्ध करवाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमारा किसान सख्त मेहनत करता है। वह न सर्दी की परवाह करता है और न गर्मी की चिन्ता करता है। वह अकेला ही नहीं बल्कि परिवार के साथ रात–दिन खेती में जुटा रहता है। उसकी मेहनत की बदौलत खेती में भारी उत्पादन होता है। अगर किसान की हालत अच्छी होगी तो गांवों में खेतीहर मजदूर, भूमिहीन मजदूर और कृषि मजदूर तथा आर्टिजन जैसे खाती है, लोहार है, धोबी है, नाई है, तेली है सभी की हालत अच्छी होगी क्योंकि इन्हें तभी धन्धा मिलता है जब किसान के खेत में अच्छी पैदावार होती है। इसके अलावा किसान जब अपनी पैदावार को ले कर मण्डी में जाता है, शहर में जाता है तो शहर और मण्डी में भी रौनक आ जाती है। शहर में और मण्डी में बैठे जो व्यापारी हैं उनका धन्धा भी तभी चलता है जब किसान की पैदावार बिकने के लिए शहर और मण्डी मैं जाती है। इसके अलावा मजदूर, रिक्शा वाले, रेहड़ी वाले सभी को धन्धा मिलता है, काम मिलता है। इसलिए किसान प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था की धुरी है। किसान को प्रोत्साहन देने के लिए चौधरी देवी लाल की सरकार ने बजट में ज्यादा–से–ज्यादा प्रावधान किया है।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह द्वारा कही गई बातों का जवाव देना चाहता हूं जो ऐसी बातें बोल कर सदन से चले गये। वे इस समय यदि यहां बैठे होते तो

मैं उनको बतलाता कि वे सदन के अन्दर कितना गल्त बोल कर गये हैं। उनके नेता भी झूठ बोलते हैं। उनके नेता की पोल मुख्य मन्त्री महोदय ने यहां पर डौकुमैण्टरी प्रूफ दे कर सभी के सामने खोली है। उनके नेता ने पलवल की रैली में कहा कि एक भी व्यक्ति खड़ा हो कर बताये जिसका कर्जा माफ हुआ हो। लेकिन बाद में इनके नेता नें जीन्द की रैली में मान लिया कि 20 करोड़. रुपये के कर्जे माफ हुए हैं। आज चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह जी ने मान लिया कि 42 करोड़ रुपये के कर्जे माफ हुए हैं। तो इनकी सारी गलत बातें सामने आ गई और यह साबित हो गया कि यह कितना गलत बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत सी और बातें भी यहां बताना चाहता हूं और फिगर्ज दे कर सिद्ध भी करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि वर्ष 1986–87 की जो योजना बनी थी उसमें '' खेती के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए अधिक प्रावधान किया गया था लेकिन अब कम किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कम्पैरेंटिव स्टेटमैंट है मैं आकड़े सदन के सामने रखना चाहता हूं। वर्ष 1987–88 में कृषि के लिए 33 करोड़ रुपये रखे गये थे, 1988–89 में 38 करोड़ 60 लाख और इस वर्ष 51.88 करोड़ रुपये रखे गये हैं। 1987–88 में कांग्रेस के राज में जो बिजली के लिए योजना बनी उस में 135.70 करोड़ रुपये का प्रावधान था। हमने सन 1988–89 में 140 करोड़ रखा था और इस साल में 202 करोड़ रुपया रखा है। परिवहन के लिए सन 1987–88 में 25 36 करोड़ रुपया रखा गया था, सन 1988–89 में 30.65 करोड़ रुपया रखा गया और इस साल के लिए 37.51

करोड़ रुपया रखा गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए सन 1987–88 में 9520 करोड़ रुपया रखा गया था, सन् 1988–89 के लिए 194 93 करोड़ रुपया रखा गया और अब इस साल के लिए छ 53 18 करोड़ रुपया रखा गया है। सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण के लिए सन 1987–88 में 124.90 करोड़ रुपया रखा गया था, 1988–89 में 96.03 करोड़ रुपया रखा गया और इस मद के लिए 1989–90 के लिए 93.95 करोड़ रुपया रखा गया है। केवल सिंचाई एक ऐसी मद है जिसमें सन 1987–88 से कम प्रावधान किया गया है। इसका कारण यह है कि सतलुज यमुना सम्पर्क नहर पर जितना खर्च होता है वह केन्द्र सरकार देती है। सन 1987–88 में उस पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत थी और सन 1988–89 में कम खर्च करने की जरूरत पड़ी। अब उस नहर का काफी हिस्सा कम्पलीट हो चुका है इसलिए उसके लिए 15 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। यही कारण है कि सिचाई की मद में कम पैसा रखा गया है। (विघ्न) एस० वाई० एल० के लिए जो 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है इसमें हमारा दोष नहीं है। यह पैसा योजना आयोग की सलाह पर रखा गया है। बाकी बची नहर पर जितनी रकम खर्च होनी है उतनी रकम हमने केन्द्र सरकार से मांगी थी। एस० वाई० एल० की स्कीम सन 1987–88 में 366 करोड़ रुपये की थी लेकिन अब यह स्कीम 429. 77 करोड की बनायी गई है। इस एस० वाई० एल० प्रोजैक्ट को कम्पलीट करने के लिए 15 करोड़ रुपया योजना आयोग के निर्देश पर 1989–90 के बजट में रखा गया है। यह सारा खर्च केन्द्र

सरकार ने पूरा करना है। वास्तव में केन्द्र सरकार इस योजना को सन् 1989–90 में पूरा करने की नीयत में नही है। अगर केन्द्र सरकार की इसे पूरा करने की नीयत होती तो वह पूरा पैसा देती। सन 1988–89 तक इस योजना पर 297 करोड़ रुपया खर्च हुआ। इस बार 15 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अब तक हुआ सारा खर्च 312 करोड़ रुपये का बनता है। इस हिसाब से जितना पैसा बचता है वह इस साल के बजट में केन्द्र सरकार को देना चाहिए था तब यह नहर कम्पलीट होती। इससे साफ जाहिर है कि केन्द्र सरकार की नीयत नहीं है कि इस साल में इस नहर को पूरा करे। मैं हैरान होता हूं जब इनके नेता बंसी लाल की बात सुनता हूं। श्री महैंन्द्र प्रताप सिंह जी भी बोल कर चले गये। वे कहते हैं कि एस० वाई० एल० नहर इसलिए पूरी नहीं की जाती क्योंकि हमने राजीव लौंगोवाल समझौते को नहीं माना। मैं तो इनकी बात से हैरान हूं और मुझे दु:ख होता है क्योंकि हमने राजीव लोंगोवाल समझौता पूरा रिजैक्ट नहीं किया। हमने संघर्ष के समय जनता को विस्तार से बतलाया था कि हमने राजीव लौंगोवाल समझौते की धारा 7 और 9 को नहीं माना है। उन धाराओ के प्रावधान से हरियाणा के साथ बड़ी बे–इन्साफी हुई थी। जहां तक चण्डीगढ़ पंजाब को ट्रांसफर करने की बात है, इस बारे में सन 197० में उस समय की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ऐवार्ड दिया था कि चण्डीगढ़ पंजाब के हवाले कर दिया जाए और बदले में फाजिल्का अबोहर के 102 गांव हरियाणा को सुपुर्द कर दिये जाएं। सन 1970 में जब यह ऐवार्ड दिया गया तो पंजाब ने खुशी में दीवाली मनाई थी

लेकिन हमारे यहां रिजैटमैट शो की गई, ला एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा हो गई, और आठ जवान पुलिस की गोली से मौत के शिकार हो गये। लेकिन इसके बावजूद हरियाणा प्रदेश ने इस बात को गले उतार कर री–कनसाइल कर लिया, इस फैसले को मंजूर कर लिया और हमें अगर फाजिल्का अबोहर का हिन्दी भाषी प्रदेश मिल जाता है, जो कौटन के लिहाज से ऐसा रिच एरिया है कि सारे हिन्दुस्तान में सबसे बढ़िया किस्म की कौटन वहां पर पैदा होती है, तो हमें चण्डीगढ़ पंजाब को देने में कोई एतराज नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह जी से, या भजन लाल से या बंसी लाल से कि इस एवार्ड को बदलने की क्या जरूरत थी? राजीव–लौंगोवाल समझौते के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, यहं लिखा गया कि चंडीगढ़ पंजाव को फौरन दे दिया जाये, उसके लिये तारीख भी निर्धारित कर दी कि 26 जनवरी 1986 को रिपब्लिक डे के अवसर पर चंडीगढ़ पंजाब के हवाले कर दिया जायेगा। आपको पता होगा, अध्यक्ष महोदय, चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल महोदय द्वारा झंडा लहराने तक की तैयारियां हो गयी थी। लेकिन चौधरी देवी लाल के नेतृत्व में जो संघर्ष किया गया और हरियाणा की लारवों जनता चौधरी साहब के पीछे लगकर जब दिल्ली पहुंची और पार्लियामैंट का घेराव किया और ऐसे हालात पैदा हो गये तो केन्द्र सरकार की हिम्मत नही पड़ी कि वह निर्धारित दिन के उस मौके पर चंडीगढ़ पंजाब के हवाले कर दे। तो क्या समझोते की इस धारा का हम विरोध न करते? क्या हम इस बात को मान लेते कि चंडीगढ़ तो पंजाब के हवाले कर दिया

जाये और उसके बदले में जो कुछ हमें मिलना है, उसके लिये आयोग बिठाया जाये, उसके लिये कोई जज बिठाया जाये, उसके लिये कोई जांच–पड़ताल की जाये। यानी जो चीज पंजाब को मिलनी थी वह तो बिना शर्त हवाले कर दी जाये और जो बदले में हमें मिलना था, तत्कालीन प्रधान मन्त्री के अवार्ड के मुताबिक, उसके लिये आयोग बिठाया जाये। क्या ऐसे समझौते को हम स्वीकार करते? जहां तक सतलुज–यमुना सम्पर्क नहर का ताल्लुक है। अध्यक्ष महोदय, एस० वाई० एल० नहर के पानी की आपुको सारी स्थिति बतलाता हूं कि किस प्रकार से ना–इन्साफी हरियाणा के साथ हुई है। जब यह रावी–व्यास के पानी का पैक्ट हुआ, पाकिस्तान के साथ इंडस–वाटर ट्रीटी हुई, उस समय यह टोटल पानी था 15.85 मिलियन एकड़ फीट। इस पानी को तकसीम करने का केन्द्र सरकार ने एक फार्मूला बनाया और उसका सिद्धान्त यह बनाया कि जिस प्रदेश के जिस इलाके को पानी की ज्यादा जरूरत हो उस इलाके में पानी ज्यादा दिया जाये और जिस इलाके में पानी की कमी ज्यादा न हो, वहां पानी कम दिया जाये। यही कारण है कि 15.85. मिलियन एकड़ फीट पानी में से अकेले राजस्थान को आधे से ज्यादा पानी यानी छ मिलियन एकड़ फीट दिया गया। यह इसलिये दिया गया कि राजस्थान एक सूखाग्रस्त इलाका है। वहां पर पानी की ज्यादा दिक्कत रहती है। पंजाब को 7.20 मिलियन एकड़ फीट और जम्मू और काश्मीर को 0.65 मिलियन एकड़ फीट पानी दिया गया। इस प्रकार से जब पंजाब और हरियाणा का विभाजन हुआ और दोनों अलग–अलग प्रदेश

बनाये गये तो हमारी हरियाणा की जनता ने और हरियाणा की सरकार ने यह क्लेम किया कि बंटवारे के मुताबिक हमें भी पानी का हिस्सा दिया जाये। यह 7.2 मिलियन एकड फीट जो यानी था, यह तो संयुक्त पंजाब का था। जब दो भाई अलग–अलग होते हैं, हरेक चीज का बंटवारा होता है। हमने यह मांग की कि क्योंकि पंजाब के मुकाबले में हरियाणा को पानी की ज्यादा जरुरत है, इसलिये हमें पानी ज्यादा दिया जाये। लेकिन पंजाब नहीं मानता था। पंजाब यह कहता था कि हरियाणा तो राइपेरियन स्टेट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, राइपेरियन स्टेट उसको कहते हैं जहां से पानी बहकर आता है। पंजाब का कहना था हरियाणा को कोई पानी नहीं मिलेगा। इस पानी पर इसका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन क्या राजस्थान राइपेरियन स्टेट है? उसको आधे से भी ज्यादा पानी कैसे दे दिया गया? यह पानी, अध्यक्ष महोदय, न पंजाब का था, न हरियाणा का था और न ही राजस्थान का था। पानी केन्द्रीय सरकार का था। 110 करोड़ रुपया मुआवजा देकर पाकिस्तान से यह पानी लिया गया था। इसलिये और प्रदेशों की भांति हमारा भी इस पानी पर हक था। लड़ते रहैं, आखिर सन 1976 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मन्त्री थीं और मैं हरियाणा का मुख्य मंत्री था, पंजाब में ज्ञानी जैल सिंह जी थे, उस वक्त इंदिरा जी ने इस पानी का फैसला कर दिया। आधा पानी यानी 3.5 मिलियन एकड़ फीट हमें दे दिया और आधा पानी यानी 3.5 मिलियन एकड़ फीट पंजाब को दे दिया और 0.2 मिलियन एकड़ फीट यानी जो बचा वह दिल्ली की ड्रिकिंग वाटर की कमी

को पूरा करने के लिए दे दिया। यह फैसला श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। अध्यक्ष महोदय, यह फैसला मार्च, 1976 के सैन्ट्रल गवर्नमैंट के गजट के अन्दर छपा हुआ है और इस फैसले के बाद आखिर में एक लाइन जोड़ी गई कि जब दरियाओं में पानी बढ़ेगा तो पंजाब को 3.5 मिलियन एकड़ फीट से ज्यादा पानी कभी नहीं दिया जाएगा। बढ़ा हुआ पानी हरियाणा को दिया जाएगा। (विघ्न) महैंन्द्र प्रताप सिंह आ गए हैं। वे कान खोलकर सुन लें। ये बारबार कहते हैं कि इस सरकार ने राजीव लौंगोवाल समझौता नहीं माना इसलिये यह नहर नहीं बन रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसका इतिहास बता रहा हूं कि कितनी बार हमारे साथ बेइन्साफी हुई। अध्यक्ष महोदय, वह गजट नोटिफिकेशन की कापी मेरे पास है अगर महैंन्द्र प्रताप सिंह देखना चाहैं तो मैं दिखा सकता हूं। उसमें लिखा हुआ है कि हरियाणा का 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी का हिस्सा तुरन्त मिलना शुरू हो जाएगा और पंजाब का हिस्सा तब मिलेगा जब थीन डैम बनकर तैयार हो जाएगा। उसके साथ ही यह लिखा हुआ है कि जब कभी दरियाओ में पानी बढ़ेगा तो बढ़ा हुआ पानी हरियाणा को दिया जाएगा। पंजाब को किसी भी हालत में 3.5 मिलियन एकड़ फीट से ज्यादा नहीं दिया जाएगा।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो कुछ ये कह–रहैं हैं, मैं भी इस बारे में कुछ बता देता हूँ।

Mr. Speaker : Mahender Partap, ji, please sit down.

This is not the way.

श्री बनारसी दास गुप्ताः उसके बाद अध्यक्ष महोदय, 31–12–1981 को तीन प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों को दिल्ली बुला लिया गया। राजस्थान के श्री शिव चन्द माथुर थे। हरियाणा के श्री भजन लाल और पंजाब के सरदार दरवारा सिंह थे। उनकी गैर मौजूदगी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने फिर फैसला किया और उस फैसले में हरियाणा का तो हिस्सा उतना ही रख दिया जो 1976 का फैसला था लेकिन बढ़े हुए पानी में से पंजाब का 72 मिलियन एकड़ फीट बढा दिया और राजस्थान का 33 मिलियन एकड फीट बढ़ा दिया। अध्यक्ष महोदय, इस सारे बढ़े हुए पानी पर हरियाणा प्रदेश का हक था। इन्दिरा गांधी ने अपने हाथ से कस्सी चलाकर कपूरी गांव के अन्दर उस नहर का उद्घाटन किया। हरियाणा के साथ बेइन्साफी हुई। उस वक्त श्री भजन लाल को चाहिए था कि गजट नोटिफिकेशन निकालकर दिखाते कि बहन जी इस बारे में आपका फैसला किया हुआ है कि बढ़ा हुआ पानी हरियाणा को मिलेगा अब आप हरियाणा के साथ बेइन्साफी कर रही हैं। लेकिन किसी की भी हिम्मत ऐसा कहने की नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, उस 1981 के नये फैसले के अन्दर यह लिखा गया कि दो साल के अन्दर नहर बनाकर तैयार करनी हैं। अध्यक्ष महोदय, कम पानी मिलने के कारण हरियाणा प्रदेश के साथ बेइन्साफी तो हुई लेकिन हरियाणा के लोगों ने इस बात पर सबर कर लिया कि चलो दो साल में नहर बनकर तैयार हो जाएगी और हमारे खेतों में दो साल में पानी तो लग जाएगा। अध्यक्ष महोदय, फिर जब राजीव

लौंगोवाल अकौर्ड हुआ तो राजीव गांधी जी ने अपनी मां के द्वारा किए गए फैसले को रही की टोकरी में डाल दिया और एक नया ट्रिब्यूनल बनाने का फैसला ले लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि इस बात की क्या जरूरत थी जब फैसला हो गया और गजट नोटिफिकेशन हो गया तो दुबारा रिवाइज करने की क्या जरूरत थी? जब तीनों मुख्य मन्त्रियों के हस्ताक्षर हो चुके थे तो उसको बदलने की क्या जरूरत थी? अध्यक्ष महोदय, जो ट्रिब्यूनल ने फैसला किया वह भी मैं बता देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ट्रिब्यूनल ने पंजाब को 5 मिलियन एकड़ फीट पानी यानी 1 मिलियन एकड़ फीट पानी ज्यादा दे दिया, हरियाणा को दिया 3.8 मिलियन एकड़ फीट अर्थात 3 मिलियन एकड़ फीट अधिक और राजस्थान को उतना ही यानी 33 मिलियन एकड़ फीट पानी अधिक रखा गया। तो इस तप की सारी बातें हुई। हालांकि बढ़े हुए पानी पर केवल हरियाणा का ही अधिकार था। लेकिन इस प्रकार की हरियाणा के साथ बेइन्साफी होती रही। अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० नहर जो है, यह हरियाणा की जीवन रेखा है। अगर किसान को पूरा पानी ही न मिलेगा तो आप ही बताइये कि प्रदेश की खुशहाली किस प्रकार से होगी? जब राजीव लौंगोवाल समझौता हुआ तो केन्द्र में हरियाणा की ओर सें श्री भजन लाल, चौधरी बंसी लाल तथा राव वीरेन्द्र सिंह जी थे। क्या इनका यह फर्ज नहीं बनता था कि केन्द्र से यह अपना विरोध प्रकट करते और कहते राजीव जी, आप हरियाणा के गले पर छुरी क्यों चला रहैं हो? लेकिन इन्होंने चूं तक नहीं की और अब भजन लाल जी

यही कहते हैं कि मैंने मुख्य मंत्री पद से इस्तीफा इसलिये दिया था कि मेरी मानी नही गयी और चण्डीगढ़ पंजाब को देने का फैसला कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, वे बिल्कुल–गल्त कह रहैं है। क्या हरियाणा का कोई व्यक्ति ऐसी गल्त बात को कभी गले में उतार सकेगा?

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः गुप्ता जी, वे बातें भी बता दें कि जो ट्रिब्यूनल के फैसला देने के बाद हमारे अधिकारियों ने मानी थीं और आप लोगों ने खुशी जाहिर की थी। (शोर)

श्री बनारसी दास गुप्ताः आप शान्ति से सुनिये मैं उसी बात पर आ रहा हूं। हम्ने खुशी इसलिये व्यक्त की थी कि इराडी कमीशन ने कम से कम इस पानी में हमारा अधिकार तो माना। पंजाव वाले तो हरियाणा का राइपेरियन स्टेट न होने के कारण पानी में हक ही नहीं मानते थे। हमने ट्रिब्यूनल के फैसले पर इसलिये खुशी जाहिर की थी, यह नहीं कहा था कि हमें हमारा पूरा हिस्सा मिल गया है। हमें खुशी थी कि ट्रिब्यूनल ने कम से कम हमारा अधिकार तो ऐस्टेबलिश कर दिया। और साथ में हमने यह बात भी कही कि जिस मिकदार में हरियाणा को पानी दिया गया वह कम है। हमारा हक हमें मिला नहीं। हम अब भी अपना केस ट्रिब्यूनल के सामने अधिक पानी के लिये लड़ रहैं हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार ये लोग, कांग्रेस के भाई हरियाणा के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ रहैं। यह पानी हरियाणा के जीवन और मौत का सवाल था। इन्हैं इस तरह का समझौता नहीं

करना चाहिये था जिससे हमारा पानी कम होने की आशंका हो। चौधरी देवी लाल जी को इसलिये वहां पर नहीं बुलाया गया क्योंकि वे विपक्ष के थे लेकिन राव वीरेन्द्र सिंह, बंसी लाल और चौधरी भजन लाल तो वहां थे। वे पूछते और जोर से कहते कि राजीव जी यह आप हरियाणा के हितों के साथ क्या खिलवाड़ कर रहैं हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे मंगल सैन जी ने बताया कि जब इस बात का फैसला हो रहा था, तो चौधरी भजन लाल जी प्रधान मंत्री जी के कमरे के बाहर चपड़ासी के पास बैठे रहैं। अन्दर से घण्टी की आवाज आई तो भजन लाल जी ने पूछा कि क्या मुझे बुलाया है? तो चपड़ासी ने कहा कि नहीं, पानी मंगवाया है (हंसी) अध्यक्ष महोदय, वह हरियाणा के मुख्य मन्त्री थे। उनके लिये यह शोभा नहीं देता था कि वे चपड़ासी के पास बैठे रहते। सारी रात मीटिंग चलती रही। आधी रात के पश्चात समझौते पर साईन हुए। तब तक भजन लाल जी बाहर चपड़ासी के पास ही बैठे रहैं। जब भी अन्दर से घण्टी की आवाज आती थी और चपड़ासी अन्दर जाकर जब बाहर आता था तो वे उसे पूछते कि क्या मुझे बुलाया है? चपड़ासी झट से कह देता था कि नहीं जी, पानी मंगवाया है। (हंसी) तो यह हालत है इनकी। हरियाणा के साथ इस प्रकार की बेइन्साफी हो, इस प्रकार का अन्याय हो और कांग्रेस के नेता खामोशी के साथ बर्दाश्त कर जाएं, किसी को बोलने की हिम्मत न हो। इस हरियाणा में एक ही माई का लाल था चौधरी देवी लाभ जिसने खड़े हो कर यह कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन हरियाणा के साथ बेइन्साफी नहीं होने दूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम

है कि दस लाख लोग चौधरी देवी लाल के नेतृत्व में पैदल चल कर दिल्ली पहुंचे और पार्लियामैंट का घेराब किया। अभी हमारे मुख्य मंत्री जी एस०वाई०एल० नहर के बारे में प्रधान मन्त्री जी को मिले तो प्रधान मन्त्री जी ने यही बात कही कि आपने राजीव लौंगोवाल समझौता नहीं माना, इस लिए नहर नहीं बनी। तो यह तो सभी एक बोली बोलते हैं। जो बात०पर से निकलती है वही बात बंसी लाल बोलता है, वही भजन लाल बोलता है और उसके बाद उनके चमचे वही बात बोलते हैं। राजीव गांधी ने भी चौधरी साहब से यह बात कही थी क्योंकि आपने राजीव लौंगोवाल अकौर्ड नहीं माना इसलिये नहर क्यों बनवाएंगे? चौधरी साहब नें—कहा कि अगर मैं वह बात मान लेता तो मैं आज यहां न बैठा होता। मेरी हालत वही होती जो बंसी लाल की हुई है। जनता ने उस आदमी को सजा दी जो प्रदेश के हितों की रक्षा न कर सका और कहा कि उन्हैं इस गद्दी पर बैठने का हक नहीं है। फिर भी हम पर इलजाम लगाया जाता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कर रहैं हैं। बंसी लाल कहता है कि अगर मैं होता तो एस०वाई०एल० बना देता। हम रोज इलजाम लगाते हैं कि हरियाणा के साथ इसलिये पक्षपात किया जाता है कि यहां पर विपक्ष की सरकार है। इसका मलतब है कि अगर मुख्य मंत्री बंसी लाल होता तो बना देता। ऐसा कह कर वे खुद मानते हैं कि हमारे प्रदेश के साथ पक्षपात होता है। दूसरी बात और कह दी कि चौधरी देवी लाल तो प्रकाश सिंह बादल से मिलते हैं और उससे बात करते हैं जिसने यह नहर रुकवाई थी। मैं इनको बताना

चाहता हूं कि वे तो चार साल से जेल में पड़े हैं। अब पंजाब में राजीव गांधी का ही राज है यानी कांग्रेस का राज है। अब तौ प्रकाश सिंह बादल वहां नहीं हैं। फिर भी चार साल से यह नहर क्यों नही बन रही है? ये बहाने बाजी करते हैं।

13.00 बजे।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार किसानों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहती है और उसका सब से बड़ा सहायक पानी हो सकता है जिसके लिये हमने संघर्ष किया और आज भी कर रहैं हैं। मैं सदन में एक बात और बता देना चाहता हूं कि शायद चौधरी देवी लाल को बगावत का झण्डा एक बार और उठाना पड़े। अगर, वह नहर नहीं बनेगी तो हम खामोश नहीं बैठेंगे बल्कि चौधरी देवी लाल के नेतृत्व में संघर्ष करेंगे और आखिरी दम तक कुर्बानी देने के लिये तैयार रहैंगे। (तालियां) इसके अलावा दूसरी जो चीज है वह बिजली की है। किसान को अगर पूरी बिजली और पानी मिल जाए तो वह भी खुशहाल होगा और प्रदेश भी खुशहाल होगा। जहां तक हमारे साधन हैं उनके बारे में सारा प्रदेश जानता है कि जब से चौधरी देवी लाल जी की सरकार आई है तब से पहले किसान को 4–5 घंटे बिजली मिला करती थी और वह भी रात के समय मिला करती थी। किसान सांप आदि का खतरा उठाकर ही खेत में पानी लगाता था। अब 24 घंटे बिजली दी जा रही है। आज हमारी योजन। का सब से ज्यादा खर्च बिजली की मद पर है। इसके लिए 220 करोड़ रुपए

रखे गए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हम किसान को बढ़ावा देना चाहते हैं। जो कमजोर किसान है, छोटा किसान है जो कर्जे के बोझ से दबा हुआ था उसका कर्जा माफ किया गया। जो लोग यह कहा करते थे कि बैकों का कर्जा माफ नहीं किया गया उसका मुंह तोड जवाब आदरणीय मुख्य मन्त्री जी ने कल दे दिया था। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की हैरानी है कि चौधरी बंसी लाल ने किस मुंह से यह कह दिया कि एक आदमी का भी कर्जा माफ नही किया गया। जव आदरणीय मुख्य मन्त्री जी ने कल यहां हाउस में बताया और उन लोगों की लिस्ट दी जिनका कर्जा माफ किया गया उस समय चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह जी सदन से बाहर चले गए। उस लिस्ट में कई आदमी बंसी लाल के गांव गोलागढ के भी हैं लेकिन बंसी लाल को अपने गांव का क्या पता वह तो कभी अपने गांव में जाता नहीं। मुझे याद है कि जब उनके पूज्य पिता जी, चौधरी मोहर सिंह, का स्वर्गवास हुआ था तब बंसी लाल एक बार गांव में गए थे। गांव में तो क्या वह कभी भिवानी में भी नहीं आते। वह डेढ़ वर्ष तक दिल्ली के अन्दर एक कोठरी में बंद पड़े रहैं। अध्यक्ष महोदय, 1987 के चुनावों में उनको जो चोट पड़ी थी उसको उस कोठरी में पड़े सहलाते रहैं। कुछ होश आया तो 20–20 लाख रुपए खर्च करके रैली कर रहैं हैं और सारे हरियाणा में दुर्भाग्यपूर्ण प्रचार करके लोगों को फुसला रहैं हैं। कुछ लोग तो यह सोच' कर उनकी सभा में चले आते हैं कि यह 9 साल तक मुख्य मंत्री रहा था, रेल मंत्री रहा था, पिछले डेढ़ साल तक मुख्य मंत्री रहा था और अब डेढ़ वर्ष बाद बाहर निकला

है तो उसकी कैसी भाषा हो गई है, उसका कैसा शरीर हो गया है यह देखने के लिये चले जाते है। अध्यक्ष महोदय, उसकी यह आदत है कि जब वह कुर्सी पर बैठता है उस समय वह सबको खाऊं पाडू करता है। जब कुर्सी से दूर होता है तो बहुत नर्म होता है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, जो लोग कर्जे माफ की बात करते हैं और कहते है कि चौधरी देवी लाल की सरकार ने कोई कर्जा माफ नहीं किया। उनको मैं कहना चाहता हूं कि यह बात ठीक है कि चौधरी देवी लाल जी जितना कर्जा माफ करना चाहतें थे उतना नही कर पाए क्योंकि हमारे रास्ते में जो रोडा है, जो बाधा है, वह कांग्रेस की केन्द्रीय सरकार है। जिन बै–'कों पर हमारा नियन्त्रण है उन बैकों के हमने सारे कर्जे दस हजार रुपये तक के माफ कर दिए है। लेकिन जो कामर्शियल बैक हैं जिन पर रिजर्व बैंक और राजीव गांधी का कंट्रोल है उनका कर्जा माफ करवाने के लिये. हमने एक स्कीम बनाई थी। वह स्कीम तैयार करके मैंने यहां चण्डीगढ़ में एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें रिजर्व बैक के प्रतिनिधि भी थे और दूसरे बैकों के प्रतिनिधि भी थे। उनके सामने हमने वह स्कीम रखी और हमने उनसे कहा कि यह सारा कर्जा गरीब लोगों ने, कमजोर वर्ग के लोगों ने लिया हुआ है, इसको माफ कर दिया जाए क्योंकि डससे बैकों को कोई हानि नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, हमने उनसे यह भी कहा था कि जब गरीब लोगों को बैकों से कर्जा दिये जाने के बारे सें स्कीम बनाई गई थी, उस समय बैकों के प्रतिनिधियों ने यह कहा था कि बैक प्रधान मंत्री के कहने से लोगों को कर्जा तो देंगे लेकिन उस पैसे

को वसूल कहां से करेंगे। इस बात पर उस समय एक निगम एल० आई० सी० की तरह बनाया गया था जिसका नाम कर्जा गारंटी निगम रखा गया था। उस कारपोरेशन के जिम्मे यी काम लगाया गया था कि अगर कर्जा वसूल नही हो सका तो 75 परसैट मुआवजा यह निगम देगा। हमने बैक के प्रतिनिधियों से यह भी कहा कि हमने हर जिले के अन्दर एक कमेटी बना दी है और उसके चेयरमैन ए० डी० सी० होंगे तथा आपके बैक के प्रतिनिधि और बी०डी ओ०, तहसीलदार उसके मैम्बर होंगे। वह कमेटी. एक एक इनडिविजुअल केस की सक्रीनिंग करेगी। उस निगम से कम्पनसेशन लेने के लिये वह कमेटी केस तैयार कर देगी। सारी कार्यवाही हो जाएगी उससे आपकी जो रकम ब्लौक हो गई है वह भी वसूल हो जाएगी और जो लोनी हैं उनको लोन लेने का रास्ता भी खुल जाएगा। वे लोन ले सकेंगे। लेकिन बैंकों के प्रतिनिधियों ने जवाब दिया कि आप हमारा पैसा माफ करने वाले कौन होते हैं? हमने उनको रास्ता बताया, तरीका बताया जिससे उनको हर तरह से लाभ होता है, लेकिन क्या अध्यक्ष महोदय, वह उनके बाप का पैसा है, हमारा पैसा नही है, बैकों में आम जनता का पैसा है। हमने उनको कानून बताया, तरीका बताया। (शोर)

Chaudhri Mahender Pratap Singh :

.....

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. (Interruptions) Mahender Partap ji, you are a well learned person. You have interrupted like this. This is not the way.

Please do not interrupt in this way. (Noise & Interruptions)

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि किसान किसी देश और प्रदेश कीं आर्थिक व्यवस्था की धुरी होती है यानी रीढ़ की हड्डी होती है। जब तक उसको सुविधाएं नहीं दी जायेंगी, बिजली, पानी या दूसरे साधन उपलब्ध नही कराये जायेगे। तब तक उस प्रदेश की हालत अच्छी नहीं हो सकती। इसलिये चौधरी देवी लाल जी की यह नीति ' है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा उपलब्ध करवाई जाये। किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये ही हम नहर को खुदाई के लिये लड़ रहैं हैं और इसलिये हमने किसानों के कर्जें माफ किये हैं ताकि वे कर्जे के बोझ से मुक्त हो कर देश के अन्न भण्डार को भर सकें। इसीलिये हम किसानों के लिये बिजली के लिये लड़ रहैं है। उनको अधिक बिजली पहुंचाने के लिये हम बिजली पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर रहैं हैं। यह सभी किसानों के हित के लिये ही हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं मजदूरों की बात करना चाहता हूं। हमारा मजदूर बड़ी मेहनत से काम करता है। मैं सदन की जानकारी के लिये बतलाना चाहता हू कि 1–1–89 से हमने न्यूनतम मजदूरी हरियाणा में एक मजदूर की 625 रुपये महीना निर्धारित की है। यह मजदूरी सारे देश के अन्दर सबसे ज्यादा है। इस समय कामरेड हरपाल सिंह जी बैठे नहीं हैं। मैं उनकी

जानकारी में लाना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल में जो उनकी पार्टी सी० पी० एम० की सरकार है और जो मजदूरों की हिमायती ज्योतिर्मय बसु की सरकार है उससे भी ज्यादा हमने अपने हरियाणा के मजदूर की मजदूरी की हुई है। इसी प्रकार से जो हमारे औद्योगिक कामगार हैं उनको 24 रुपये प्रतिदिन कम से कम दिए जाते हैं। यह मजदूरी भी सारे देश में हरियाणा में सबसे ज्यादा है। इसी प्रकार से कृषक कामगारों की भी कम से कम 25 रुपये प्रति दिन मजदूरी फिक्स की गई है। हमारी सरकार ने मजदूरों को बढ़ावा देने के लिये और उनको सहारा, देने के लिये सारे देश से ज्यादा मजदूरी फिक्स की हुई है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं उनको भी 100 रुपया प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। यह मैं नहीं कहता कि इससे उनका गुजारा हो जाता है, यह केवल उनकी हौसला अफजाई के लिये दिया गया है। डन बेरोजगारों को 100 रुपया बेरोजगारी भत्ता चौधरी देवी लाल जी ने हरियाणा दिवस पर सार्वजनिक तौर पर अपने हाथों से दिया था। आने वाले साल के लिये यानी इस योजना के लिये यह राशि 6 करोड़ रुपये रखी गई है। अध्यक्ष महोदय, पता नही चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह जी कहां से यह फिगर्ज उठा लाये कि हमने बेरोजगारों को 350 रुपया महीना देने का वायदा किया था और लोगों के 1200 करोड़ रुपये के कर्जे माफ करने की बात कही थी। हमने वायदे नहीं किए थे बल्कि हमने जितने वायदे किए

थे उससे ज्यादा रुपये के कर्जे माफ किए हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक वृद्धावस्था पैंशन देने की बात है, यह कितना बड़ा सम्मान हमने अपने बुजुर्गों को दिया है। यहां पर कांग्रेस के एक साथी असलम खां जी जो बहुत शरीफ हैं और कम ही बोलते हैं, यह नुक्ताचीनी करने लगे कि यह वृद्धावस्था पैंशन सभी लोगों को नहीं दी जानी चाहिए थी बल्कि इसके लिये. कोई क्राइटेरिया इंकम का या आमदनी का रखना चाहिए था और जो उस क्राईटेरिया में आते हैं केवल उन्हीं को यह पैशन दी जानी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी को तो आप जानते ही हैं। मैं सदन की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि देहली में उनकी एक कोठी है जिसका 50 हजार रुपया महीना किराया आता है। मेरे मकान के चारों तरफ एक और तो सड़क है और तीन तरफ चौधरी बंसी लाल के परिवार की कोठियां हैं। इतना बड़ा आदमी है कि घर के जितने फैमिली मैम्बर्ज हैं उससे ज्यादा गाड़ियां हैं। इस से ज्यादा खुशहाल कोई आदमी क्या होगा? इनके पिता चौधरी मोहर सिंह थे। अध्यक्ष महोदय, उनकी हालत आपने तो नहीं देखी है लेकिन मैंने देखी है, चौधरी साहब ने देखी है। जब मैं चौधरी बंसी लाल के मंत्रिमण्डल में मन्त्री होता था और जब भिवानी जाता था तो मेरे पास मिलने के लिये सबसे पहले वही आते थे। मैं उनका बहुत सम्मान करता था। वे कहा करते थे कि मुझ से ज्यादा दुखी आदमी संसार में कोई नही। वे आज स्वर्ग में हैं, अगर मैं गल्त कहता हूं तो मुझ से बड़ा पापी कोई नहीं है। ऐसे ही लोगों को सम्मान देने के लिये चौधरी देवी लाल ने पैशन देने

के लिये कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया। अध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति मुझ से मिला और रोने लगा। उसके कपड़े फटे हुए थे और हालत बुरी हो रही थी। वह वृद्ध कहने लगा मेरे चार बेटे हैं, 100 एकड़ जमीन है, नहर लगती है, दो ट्रैक्टर हैं लेकिन मेरे लड़के मुझे चाय तक को नहीं पूछते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब से बूढ़ों को 100 रुपये महीना पैशन मिलने लगी है उनके घर वाले भगवान से दुआ करते है कि बुड्ढा और ज्यादा जीये ताकि घर में पैशन आती रहैं। पहले लोग भगवान से दुआ करते थे कि बुढ्ढे को जितनी जल्दी हो उठा ले। अभी पीछे 800 रुपये पैशन के इन्हैं मिले। जिन घरों में बुढ्ढा–बढ्ढी दोनों थे उन घरों में 1600 रुपये पैशन के मिले। लोगों को घरों में नोट रखने को जगह नहीं मिली इस बात को भी ये कांग्रेस के लोग नही मानते और कहते हैं कि पैशन– तो हम भी दे रहैं थे। चौधरी देवी लाल ने फिगर्ज दे कर सारे मामले को साफ किया है। सरकार ने किसानों को, खेतीहर मजदूरों और दूसरे मजदूरों को पूरा प्रोत्साहन दिया है। अध्यक्ष महोदय, समाज में जो कमजोर हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिये हमने पैशन दी, हरिजन और पिछड़े हुए जो लोग है, उनको बढ़ावा देने के लिये 8 करोड़ से अधिक रकम के उनके कर्जे माफ किये हैं। हरिजन कल्याण निगम और पिछड़े वर्ग कल्याण निगम के जरिये हरिजनों और पिछड़े लोगों के कर्जे माफ किये हैं। हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों के बच्चों के वजीफे बढ़ाए हैं, पूस्तकें, स्लेटें और वर्दियां मुक्त दी हैं। हरिजन कल्याण निगम और पिछड़े वंर्ग कल्याण निगम की जो जमा पूंजी थी उसे बढ़ाया गया है और

उनको और पैसा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिये हमारे मुख्य मन्त्री ' जी कितने चिन्तित हैं। शिक्षा में जो डिस्पैरिटी या असमानता है उसको दूर किया जाए यह चिंता उन्हैं लगी रहती है। हमारी शिक्षा मन्त्री जी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए पिछले दिनों कहा था जितने स्कूल इस साल अपग्रेड किये गये हैं, स्कूलों का दर्जा बढ़ाया गया है वे सभी लड़कियों के स्कूल हैं। अगले साल भी लड़कियों के नये स्कूल खोले जाएंगे और उनका दर्जा बढ़ाया जाएगा। मैचिंग ग्रान्ट की अनूठी परम्परा यहां शुरू की गई है। जन शक्ति का प्रयोग करने के लिये लड़कियों की शिक्षा के लिये भी दुगनी मैचिंग ग्रान्ट देने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार महिलाओं के उत्थान के लिये भी यह सरकार पूरी तरह से सजग है। विभिन्न बातों के साथ ही औद्योगीकरण के बारे में भी मेरे सभी सम्मानित सदस्यों ने सुझाव दिए हैं विभिन्न सदस्यों ने कहा कि बिना औद्योगीकरण के बेरोजगारी की समस्या हल नही हो सकती, यह बात बिल्कुल ठीक है और मैं इस बात से उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। सरकार की नीति है कि औद्योगीकरण को और वह भी छोटे उद्योगों को, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को ज्यादा से, ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। महात्मा गांधी केवल एक पोलिटीशियन ही नहीं थे, वे समाज शास्त्री और अर्थ शास्त्री भी थे। गांधीवादी अर्थ–व्यवस्था में इस बात पर जोर दिया गया है कि छोटे–छोटे उद्योगों को लगाया जाए जो कि घरों में, झुग्गी झोपड़ियों में चल सकें। आज उद्योगों का मशीनीकरण किया जा रहा है जिसमें हजारों आदमियों का

काम एक ही आदमी कर देता है। इस तरह से बेकारी की समस्या हल नहीं हो सकती। महात्मा गान्धी ने इसी बात पर बल दिया था कि छोटे और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। हमारे स्वर्गीय नेता चौधरी चरण सिंह भी मरते दम तक इस बात पर जोर या बल देते रहैं और बडे उद्योग लगाने के साथ–साथ छोटे लद्यु और कुटीर उद्योगों को सारे देश के अन्दर फैलाने की बात करते रहैं। हमारे सदस्यों ने भी चिन्ता व्यक्त की शै कि इस मद के लिए बजट में पैसा कम रखा गया है, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता है कि हमारे मुख्य मन्त्री जी के आदेश से हमने एकु नयी औद्योगिक नीति बनायी है। यह नीति प्रदेश में उद्यमी उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए बनायी है। हम और ज्यादा भी प्रोत्साहन देना चाह रहैं हैं। हमने नये उद्योगों में टैक्स में माफी का भी प्रावधान किया है, डैफरमेंट का भी प्रावधान किया है। जन रेटर सैट्स में सबसिडी बढ़ायी है और इलैक्ट्रोनिक्स इन्डस्ट्री में तो बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन देने की बात की है। जहां 15 परसैन्ट सबसिडी थी वहां 25 परसैन्ट सबसिडी कर दी हैं। इस तरह से उद्योगों पर सरकार ने द्रा पूरा ध्यान दिया है। इसके साथ ही जो पिछड़े इलाके हैं उन पिछड़े इलाकों के विकास पर सरकार का पूरा ध्यान गया है। अभी पिछले दिनों मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड को भी ज्यादा सहायता दी गई है। मोरनी हिल्ज के पहाड़ी इलाके जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं वहां जो गरीब आदमी हैं उनकी डिवैल्पमैंट के लिए अलग से बोर्ड का गठन किया गया

है। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, जो व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, जो इस प्रकार से मेहनत करते हैं जिस तरह से दूसरे लोग करते हैं, उनके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अनेक कसेशन और रियायतें दी गई हैं। कई आइटम्ज हैं जिन पर सेल्ज टैक्स कम किया है। डाक्टर मंगल सैन जी ने कहा है कि जहां बर्तनों पर 11 परसैन्ट टैक्स था अब वहां पर तीन परसैन्ट कर दिया है। इस प्रकार खल, बारदाने और कई चीजों पर टैक्स कम किया है। कुछ सदस्य साहैंबान ने कहा कि पड़ोसी राज्य के समान ही बिक्री कर की दर होनी चाहिए। हम भी इस हक में हैं लेकिन दिल्ली हमारे लिये बड़ी. परेशानी करता है। दिल्ली यूनियन टैरेटरी है। सीधा वह राजीव गाधी के अधीन है। दिल्ली के प्रसाशन को टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। वह सैन्टर के सिर पर पलता है लेकिन हरियाणा प्रदेश कहां जाये। हरियाणा प्रदेश का जो हक है वह भी केन्द्रीय सरकार से नही मिलता है। एक गाडगिल फार्मूला लागू कर रखा है जिसके कारण हमारा प्रदेश घाटे में रहता है। उस फार्मूले' के मुताबिक हमारे जैसे प्रदेश के साथ अन्याय करते हैं। जो प्रदेश मेहनत करते हैं, कुशलता से काम करते हैं, अपना विकास ज्यादा कर रहैं हैं उन्हैं केन्द्र सरकारी कम सहायता देती है। जो पिछड़े हुए इलाके हैं उन्हैं ज्यादा पैसा दें लेकिन जो हमारा हिस्सा है वह तो न काटें। जो हमारा हक है वह पूरा नहीं मिलता है और दिल्ली को जो पैसा दिया जाता है वह सारा केन्द्र सरकार देती है। दिल्ली के तीन तरफ हरियाणा लगता है। यह बात ठीक है जो हमारे माननीय सदस्य श्री देवी दास ने कही कि सोनीपत मन्डी

उजड़ गई है। सोनीपत की मंडी ही नहीं उजड़ी है बल्कि बहादुरगढ़, फरीदाबाद और सापला की मंडी भी उजड़ गई हैं। दिल्ली की मंडियों के अन्दर टैक्स वहुत कम है, मार्किट फीस लगती ही नहीं है। नरेला नजफगढ़ और नांगलोई जो पहले गांव होते थे अब वे शानदार मडिया बन गई हैं और दिल्ली के साथ लगती हमारी मंडियां उजड़ गई हैं। इस बारे में केन्द्र से बार–बार प्रश्न उठाया गया है। अभी 9–10 फरवरी को भी यह प्रश्न मुख्य मंत्रियों की कांफ्रेस में उठा था कि बिक्री कर की समान दरें होनी चाहिएं और खास तौर से दिल्ली के साथ या अन्य प्रदेशों के साथ जो फर्क है वह दूर होना चाहिए। इस फर्क को निकालने की तजवीजें हमारे विचाराधीन हैं। हमारा विभाग गहराई के साथ विचार कर रहा हैं कि पड़ौसी प्रदेश के बराबर बिक्री कर हो लेकिन दिल्ली का मुकाबला हम नही कर सकते।

नगरपालिकाओं को अनुदान देने के लिये, अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत सारे सम्मानित सदस्यों ने अनुरोध किया है। मैं भी मानता हूं कि नगरपालिकाओं की स्थिति बड़ी शोचनीय है। ज्यादा शोचनीय तो इसलिये हुई क्योंकि कांग्रेस ने 18 साल के राज में उनके चुनाव ही नहीं कराये। अधिकारी बिठा दिये गये और उन्होंने अपने मनमाने ढंग से उनका प्रबन्ध चलाया। जो कुछ भी उन्होंने किया, अपने मनमाने ढंग से किया। धीरे–धीरे उनकी हालत खराब हो गयी। अब उनकी हालत सुधारने की आवश्यकता हए। हमने अभी उनको दो करोड़ रुपये का अनुदान दिया है ताकि

बारिशों से या फ्लड से जो सड़कें वगैरा टूट गयी हैं, उन्हैं ठीक करा सकें। जितनी हमारी सामर्थ्य है, हमने उतना अनुदान दिया है। लेकिन अकेले सरकार के अनुदान से इनकी माली हालत या आर्थिक हालत अच्छी नहीं हो सकती। अभी चौधरी देवी लाल की सरकार बनने के बाद हमने संसाधन समिति नगरपालिकाओ के लिये बनायी थी। उसने कुछ सुझाव भी दिये थे। कुछ पानी का रेट और कुछ औक्ट्राय का रेट भी बढ़ाया था। औक्ट्राय का पिछले 20 सालों से जो रेट था, आज भी वही लग रहा है। मेन सोर्स औफ इन्कम नगरपालिकाओं का औक्ट्राय या चूंगी है। लेकिन जब देखा कि रेट बढ़ाने से जनता में रोष है, नराजगी है, उसको लागू होने से हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने रोक दिया क्योंकि हमारे मुख्य मन्त्री जी का नारा है कि लोक। राज लोक लाज से चलता है। लोक राज में लोगों की भावनाओं की और लोगों के रोष की चिन्ता करनी पड़ती है। उसके लिये एक मति परिषद की उप–समिति बनायी गयी है जो इस बात पर विचार करेगी कि आया इनको बढ़ाया जाये या न बढ़ाया जाये। अगर बढ़ाया जाये तो कितना बढ़ाया जाये। उसका फैसला अभी आयेगा। तब पता चलेगा कि नगर–पालिकाओं को कुछ संसाधन मिलने हैं या नहीं मिलने हैं। इसके अलावा एक और संसाधन है। ग्राम पंचायत की माली हालत को बेहतर बनाने के लिये एक रुपया प्रति बोतल देसी शराब पर जो टैक्स लगाया गया है, वह ग्रामीण क्षेत्र में जो बिक्री होगी, उसका टैक्स पंचायतों को दिया जायेगा, पंचायत समिति–यों को दिया जायेगा और नगरपालिकाओं की सीमा में जो बिक्री

होगी, उससे जो टैक्स आयेगा, वह नगर– पालिकाओं को दिया जायेगा। इस, तरह से इनको साधन उपलब्ध होंगे। इनकी कितनी हालत ठीक होगी, यह देखने की बात है। सी० ई० ओज० की बात डाक्टर मंगल सैन जी ने कही कि वहां पर बहुत बड़े –बड़े अफसर बिठा दिये गये हैं लेकिन जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनको कोई अधिकार नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात तो नही है।

बैठक का समय बढ़ाया जाना

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, आप कितना टाईम और लेंगे।

श्री बनारसी दास गुप्ताः 10 मिनट जी।

श्री अध्यक्षः यदि हाउस की सहमति हो तो सिटिंग का समय 10 मिनट के लिये बढा दिया जाये?

आवाजें: जी हां।

श्री अध्यक्षः बैठक का समय 10 मिनट बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1989– 90 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, उसके लिये भी एक मन्त्री परिषद की उपसमिति बनायी गयी है। यह मामला विचाराधीन है। हम यह बिल्कुल चाहते है कि जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनके अधिकारों पर कोई किसी प्रकार की एन्क्रोचमैंट

न हो। उनको पूरे अधिकार दिये जायें। हमने तो ऐसा सिर्फ इसलिये किया है कि नगरपालिकाओं का बजट चूंकि बहुत बढ़ गया इसलिए एक अच्छा अफसर वहां बिठाया जाये जो उसका प्रबन्ध कर सके। लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा कि निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं, उनके अधिकारों को कम न किया जाये। इसके अलावा हमारे दूसरे माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ बातें कही हैं। वैसे ती 'सभी विभागों का जवाब मेरे पास आया पड़ा है। ये सारी चिटें बिखरी पड़ी हैं। एक एक बात का मेरे पास जवाब है लेकिन यदि मैं उन सब का ब्यान करने लगू तो उसमें काफी ज्यादा समय लगेगा। डाक्टर मंगल सैन जी ने हुड्डा के बारे में बात कही थी। उसका जवाब मेरे साथी मन्त्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने दे दिया है।

डाक्टर मंगल सैन जी यहां पर बैठे नहीं हैं। अगर वे यहां पर होते तो शायद उनको संतोष होता। बड़ा ही माकूल जवाब इन्होंने दिया है। एस वाई. एल. सम्पर्क नहर की बात जो थी, उसका जवाब मैंने बड़े विस्तार से दे दिया है। पुलिस बल की जो बात उन्होंने कही कि चण्डीगढ़ में कोई घटना हो गयी जिसमें किसी के साथ ज्यादती हो गयी, उसके बारे में मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि मेरे पास पुलिस विभाग की सूचना है। उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया गया है। उनको गिरफतार भी कर लिया है। चण्डीगढ़ पुलिस कार्यवाही कर रही है। तफतीश भी उन्ही के हाथ में है। किसी को भी माफ नहीं किया

गया है। जहां तक कुरूक्षेत्र के अन्दर लज्जाजनक घटना का ताल्लुक है, उसकी अध्यक्ष महोदय, जांच चल रही है, केस भी रजिस्टर हुआ है। हमारी पुलिस बड़ी मुस्तैदी के साथ उस बारे में काम कर रही है।

श्री सतबीर सिंह कादियान ने कहा कि खेल विभाग को कम पैसा मिलता है जिससे कि खिलाड़ियों को अधिक प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी सरकार ने एक नई नीति बनाई है। उसके अनुसार राजभवन में कोई समारोह होने वाला है। उस समारोह में घोषणा की जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन न केवल पंजाब के बराबर दिया जाए बल्कि उससे भी ज्यादा दिया जाए। सतबीर सिंह कादियान ने शिक्षा में अधिक धन देने की बात कही। अध्यक्ष महोदय, हम तो पहले ही शिक्षा के क्षेत्र में धन ज्यादा दे रहें हैं। उन्होंने प्राईमरी स्कूलों के भवनों की बात भी कही। मास्टर शिव प्रसाद ने भी इसका जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, जो प्राईमरी स्कूल किराये के मकानों में चल रहैं हैं उनके लिए नए सिरे से मकान, बनाने के लिए चार करोड़ कुछ लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है और जो कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनकी हालत खस्ता है उनकी मरम्मत के लिए पिछले दिनों मन्त्री परिषद ने फैसला किया है कि का जो पैसा पहले मुख्यालय में आता था उसका, सत्तर प्रतिशत स्कूल को ही देंगे और वह पैसा स्कूल के भवन की मरम्मत पर खर्च किया जाएगा। मास्टर

शिव प्रसाद ने अनपढ़ता का जिक्र किया। इसके बारे में मैंने बता दिया हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से 95 प्रतिशत अनुदान कालेज को दिया जाता है उसी तरह से स्कूल्ज को भी दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, कोठारी कमीशन ने या किसी और कमीशन ने जैसी सिफारिश की है उसके मुताबिक हम अनुदान दे रहैं हैं। शिक्षा उपयोगी हो इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया और कई सदस्य साहैंबान ने यह बात कही कि शहर और देहात में टीचर और विद्यार्थी की अनुपात में पैरिटी नहीं है। शहर के स्कूल्ज में ज्यादा टीचर रखे जाते हैं और देहात के स्कूल्ज में कम रखे जाते हैं। देहात में ऐसे भी स्कूल हैं जहां एक स्कूल में एक, ही टीचर है और विद्यार्थी ज्यादा हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में ब्लैक बोर्ड स्कीम चालू की गई है और कम से कम दो अध्यापक हर स्कूल में होंगे। इस स्कीम में अभी बीस ब्लौक्स कवर कर लिए हैं और बाकी भी कवर कर लिए जायेंगे। उन्होंने अम्बाला नगरपालिका की बात भी कही। वृद्धावस्था पैन्शनं की बात भी कही गई कि जो पैशन पाने के अधि कारी हैं उनको पैन्शन नही। मि लती और जो कम उभ र के लोग है उनको पैन्शन मि लती है। इस बारे में मुख्य मन्त्री जी ने आदेश दिए हैं कि उसकी एक बार फर छानबीन की जाए। यह भी कह। गया कि जब डा किया पैन्शन देने के लिए जाता है तो दस बीस रुपया डाकिया ले लेता है। इस बीमार को खत्म करने के लिए मुख्य मन्त्री महोदय ने डिप्टी कमिशनर्ज की एक कमेटी बना ई है कि इसको रोकने के लए वे कोई सही तरीके बताएं।

चौधरी भागी राम ने ऐलान के लिए ड्रेज की बात कही, पा नी की बात कही और अस्पताल की बात कही। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इन सारी बातों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। श्री रावत ने विधवा पैन्शन को बढ़ाने के बारे में कहा। अध्यक्ष महोदय, इसको पिछले दिनों पचास रु पए से बढ़ाकर सौ रुपए कर दिया गया है। पहले यह पचास रुपए दी जाती थी। अध्यक्ष महोदय, जला फरीदाबाद और गुड़गांव में आगरा कैनाल के बारे में किसाने की तकलीफ बतलाई गई। हमारी सरकार इस बात को समझती है और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हम सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री मामला टेकअप कर रहैं हैं। हम मंशा है कि इ सको जल्दी से जल्दी हल किया जाए। अध्यक्ष महोदय, बेकारी की समस्या के बारे में यहां पर कहा गया। श्री दुर्गा दत्त अत्री ने रामराय पिडारा और कलायत जै से स्थानों के लिए कुरूक्षेत्र डिवैल्पमैंट बोर्ड जैसा अलग से बोर्ड बनाने की बात क्ही। अध्यक्ष महोदय, जो कुरूक्षेत्र डिवैल्पमैंट बोर्ड है उसके नीचे राम राय पिडारा और कलायत आदि तीर्थ स्थान भी आते है। जब कुरुक्षेत्र के विकास से उसको फुरसत हो जाएगी तो दूसरे तीर्थ स्थानों के विकास का भी यह काम करेगा इसलिए अलग से इन जगहो के लिए बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। विकलांगों और नेत्रहीनो को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाए इसका भी जिक्र किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो नेत्रहीन है उनको मुफ्त यात्रा की सुविधा पहले से ही दी जाती है। जहां तक विकलांगो का ताल्लुक है जब वे इलाज के लिए साकेत आते हैं तो उनको की पास दिया जाता

है। अध्यक्ष महोदय, यहां यह भी कहा गया है कि देहातों के अन्दर उचित चिकित्सा सुविधा नही है। आहिस्ता–आहिस्ता इसका प्रबन्ध कर रहैं हैं और बहुत से गांव में पी० एच० सी० खोलने जा रहैं हैं। श्री देवी दास जी ने ड्रेन नम्बर 6 का जिकर किया। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने ऐलान किया था कि हम अगली बारिश आने से पहले सारी ड्रेन की सफाई अच्छी प्रकार से करवा देंगे। नगरपालिकाओं के अनुदान के बारे में भी, बताया गय। नैन साहब ने एक बात कही कि पुलिस के जो नौजवान हैं, वे बड़ी बहादुरी के साथ काम करते हैं और बड़ी बहादुरी के साथ आतकवाद का सामना कर रहैं हैं। मैंने पहले भी जिकर किया था कि आतकवाद पर नियंत्रण पाने के लिये हरियाणा पुलिस ने जिस बहादुरी का परिचय दिया है वह बहुत ही सराहनीय है और हरियाणा के अन्दर ला एण्ड आर्डर की स्थिति को बनाये रखने में उनका पूरा योगदान रहा है। इस के लिये हमारी पुलिस प्रंशसा के योग्य है। स्पीकर साहब, हरियाणा तो दिल्ली में आतकवाद के लिये दीवार बनकर बैठा हुआ है। अगर हरियाणा कोई कार्यवाही न करे तो आज दिल्ली बिल्कुल सुरक्षित नही रह सकती। अभी हमारे हरियाणा के अन्दर एक कमांडो फोर्स का गठन किया गया है। पिछले दिनों पंचकूला के अन्दर इसका प्रदर्शन भी हुआ है। बहुत अच्छे–अच्छे करतव वहां पर दिखाय गये कि किस प्रकार वी० आई० पीज० की रक्षा के लिये कमांडोज फोर्स अपना कार्य करेगी। उस प्रदर्शन में आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री रामाराव को नकली रूप से बनाया गया और उनकी रक्षा के लिये जो प्रदर्शन हुआ

उसमें एक आदमी मारा भी दिखाया गया। कैसे रक्षा होती हैं, कैसे रेड होते हैं, इस प्रकार भी हर तरह की ट्रेनिंग वहां दी जाती हैं। जहां तक आधुनिक हथियारों को सप्लाई करने का सवाल है, यह हमारे बस की बात नहीं है क्योंकि आधुनिक हथियार तो केन्द्र सरकार ही सप्लाई करती है। अध्यक्ष महोदय, पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिये हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने पुलिस की पे अनौमली को दूर करने की पूरे जोर से सिफारिश की है। अब पुलिस के अच्छे वेतनमान हरियाणा के अन्दर दिये जाएंगे।

श्री किशन सिंह सांगवान जी ने ड्रेन नं० 8 का भी जिक्र किया। कुछ माईनर्ज भी इन–कम्पलीट बतायी गयी हैं। सम्बन्धित मन्त्री महोदय इस को देखेंगे।

अध्यक्ष महोदय, दिन ब दिन विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। इसलिये स्कूलों के अप–ग्रेडेशन की बात भी विचाराधीन है।

श्री कैलाश चन्द शर्मा जी ने अपने इलाके महैंन्द्रगढ की बाट कही कि वहां पर सूखा पड़ा है, थह इलाका पिछड़ा हुआ है और वहां की नहरों में पानी चलता चाहिये। मैं हाउस के अन्दर यह बताना चाहता हूं कि चौधरी देवी लाल जी के नेतृत्व में बनी सरकार के दिनों में ही जवाहरलाल नेहरू कैनाल और लोहारू कैनाल में पानी चला है। (तालियां)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, मेरे विचार में टाईम और एक्सटैन्ड कर दें।

श्री बनारसी दास गुप्ताः ठीक है जी, 10 मिनट का समय और बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्षः अगर हाउस की– सहमति हो तो बैठक का समय 10 मिनट और बढा दिया जाए?

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः बैठक का समय 10 मिनट के लिये और बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1989– 90 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री बनारसी दास गुप्ताः इसके इलावा शर्मा जी ने बताया कि महैंन्द्रगढ़ में चूंकि मिनरल्ज काफी मात्रा में उपलब्ध हैं इसलिए वहां औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाए। औद्योगिक क्षेत्र तो सरकार वहां बना दे लेकिन लोग वहां जाते नहीं हैं। लेकिन मिनरल्ज के विकास के लिये एक मिनरल्ज कारपोरेशन बनाया है और इटली से एक कटर उपलब्ध करवाया है जिससे अच्छी प्रकार से उनकी कटाई की जाएगी।

चौधरी महैंन्द्र प्रतापः की बातों का जवाब तो मैं पहले ही दे चुका हूं। इनकी कुछ बातें तो बिल्कुल ही दिशाहीन और गलत थीं। मैंने सारे आकड़े यहां पर पढ़ कर सुरु दिए थे। ये कह

रहैं थे कि हमारे टाइम में अधिक बजट रखा गया था लेकिन जब मैं आकड़े दे रहा था तो ये उस समय गैर–हाजिर थे। अध्यक्ष महोदय, चौधरी रणजीत सिंह जा ने कई बड़े अच्छे सुझाव दिए। जहां तक एस० वाई० एल० नहर की बात है, मैंने उसके बारे में पूरा विवरण दिया है। जहां तक खालों की मुरम्मत की बात है वह बिल्कुल ठीक है। अध्यक्ष महोदय, ये खाल कांग्रेस के राज्य में बने थे, उन पर कैसा मैटिरियल लगा था वह तो ये जानते होंगे। उनकी मुरम्मत के लिए अब हम कदम उठा रहैं हैं। चौधरी रणजीत सिंह जो ने रेल को व फैक्टरी की भी बात की। उन्होंने कहा कि उस फैक्टरी को यहां से उठा कर पंजाब में ले गए। अध्यक्ष महोदय, करनाल रिफाइनरी के लिए भी ये कुछ ते सी ही साजिश कर रहैं हैं। मैं महैंन्द्र प्रताप जी से पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा ही करना था तो उसका शिलान्यास करने की क्या जरूरत थी। फरवरी 1987 में प्रधान मन्त्री ने खुद उसका शिलान्यास किया लेकिन आज तक वहां पर एक ईट भी नहीं रखी गई। क्या यह वोट लेने के लिए लोगों को बहकाने वाली बात नहीं है? मैं उनको बत। दूं कि लोग पागल नहीं है कि वे दिखावा करने मात्र से वोट दे देंगे। इसलिए केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि जिस योजना की घोषणा वह कर चुकी है उस हो पूरा करे। अध्यक्ष महोदय, गन्ने की कीमत 35 रुपए क्विंटल सब से ज्यादा हिन्दुस्तान में केवल हरियाणा सरकार दे रही है। यह भी किसान को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। इसके अलावा हमने प्राथमिक शिक्षा का जो अलग निदेशालय बनाया है चौधरी रणजीत सिंह जी ने उसकी भी

सराहना की। यह वास्तव में सराहनीय काम है क्योंकि जब तक शिक्षा का सुधार नहीं होगा तब तक हम उपयोगी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। खिलाड़ियों के बारे में भी चौधरी रणजीत सिंह ने कहा। मैं बताना चाहता हूं कि हम खिलाड़ियों को भी अधिक प्रोत्साहन देने जा रहैं हैं।

चौधरी रणजीत सिंह जी ने वीडियो पारलर के बारे में भी बताया तथा और सदस्यों ने भी इस बारे में जिक्र किया कि सिनेमाओं के०पर कई तरह की शर्तें हैं। उसके लिए 40—50 लाख रुपए का प्लांट मिलता है फिर उसकी बिल्डिग बनाने का खर्चा, एयर कंडीशन प्लांट उसमें हो तथा अच्छी सीटें हों। लेकिन वीडियो पारलर पर कोई शर्त नहीं हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इसी सैशन में एक विधेयक ला रहैं हैं। उसके मुताबिक एक सौ सीटों तक वीडियो पारलर पर हम कोई प्रतिबन्ध नहीं लगायेंगे। क्योंकि देहात में भी मनोरजन मिलना चाहिए। लेकिन अगर उससे ज्यादा सीटें होंगी तो उन पर वही शर्तें लागू होंगी जो सिनेमा घरों पर लगती हैं यानी उसी हिसाब से उन पर टैक्स लगाएंगे। चौधरी श्री कृष्ण हुड्डा ने खिलाड़ियों की बात कही जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। उन्होंने पशु पालन पर अधिक जोर देने की बात कही। उनकी यह बात ठीक है, सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। एक बात उन्होंने ट्रक, जीप और कार पर टैक्स लगाने की कही। इन पर टैक्स ठीक लगता है। पिछले दिनों हमने टैक्स कम किया था।

अगर अब भी ज्यादा होगा जिससे आय में कमी पड़ती होगी तो हम इस पर भी विचार करेंगे। डा० बृज मोहन ने डाक्टरों के वेतन की बात कही। एनोमली कमीशन की रिपोर्ट 27 तारीख को सर–कार के पास आ चुकी है। मेरा ख्याल है कि डाक्टरों की एनोमली उससे दूर हो जाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों की कन्फीडैंशियल रिपोर्ट लिखने का जिक्र आया कि रिपोर्ट उसी विभाग का अधिकारी लिखे जिसमें वह काम करते हैं। जहां तक मैं समझता हूं ज्यादातर रिपोर्टस उसी विभाग के उच्चाधिकारी ही लिखते हैं। अगर कोई खास बात हो तो हमारे नोटिस में लाएं, हम उस पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी के बारे में सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि 1990 तक जितने भी समस्याग्रस्त गांव है उन सब गावों को पीने का पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा। माननीय सदस्य श्री कान्ति प्रकाश भल्ला जी ने एक बात कही कि जब बारिश का पानी टांगरी और घग्गर नदी में आता है तो उससे बाढ़ आ जाती है उसका कोई इन्तजाम किया जाए। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि उसकी रोकथाम के लिए एक स्कींम बना ली गई है। उस स्कीम पर अमल होने वाला है। वहां पर एक बांध बना कर सारी नदियों के पानी को कंट्रोल किया जाएगा और खेती के लिए इस्तेमाल किया जायेगा। उन्होंने कालका में औद्योगिक क्षेत्र बनाने की बात कही। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पंचकूला पहले ही औद्योगिक क्षेत्र है।

अध्यक्ष महोदय, आर्य साहब ने शिक्षा में सुधार की बात कही इस बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। इसके अलावा उन्होंने एक बात यह कही कि कालेजों में छात्रों की संख्या बढ़ गई है इसलिए अध्यापक ज्यादा होने चाहिएं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि बजट का बहुत हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में खर्च होता है और अगर जरूरत हुई तो इसको थोड़ा ज्यादा करने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा सदन में एक बात यह भी कही गई कि कौन्फैड में ही नहीं बल्कि दूसरे महकमों में भी भ्रष्टाचार है। माननीय सदस्य ने परिवहन महकमे के बारे में बात कही। यदि माननीय सदस्य के नोटिस में ऐसी कोई बात है तो वह आदरणीय मुख्य मन्त्री जी के नोटिस में लाएं। अगर ऐसी कोई बात होगी तो उसकी जरूर जांच करवाई जाएगी और दोषी को सजा दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, राणा साहब ने अपने हल्के के बारे में बातें कहीं और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी बड़े अच्छे अच्छे सुझाव हमारे सामने रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, बजट पर बड़ी अच्छी बहस हुई है। स्वस्थ आलोचना भी की गई है जिससे मैं समझता हूं कि बहस का जो स्तर है वह०ंचा हुआ है। चौधरी महैंन्द्र प्रताप जी ने कुछ गलत बातें जरूर कही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा चौधरी महैंन्द्र प्रताप जी से प्रार्थना करूंगा कि सदन में दाखिल होते ही वह जो सामने पिलर पर लिखा हुआ है उसको पढ़ लिया करें उसके बाद अपनी जुबान खोला करें। अध्यक्ष

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपके और माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं तथा सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हू कि इस प्रगति शील बजट को सर्वसम्मति से पास करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः अब हाउस सोमवार, 13 मार्च, 1989, बाद दोपहर 2.00 बजे तक ऐडजर्न किया जाता है।

13. 47 बजे

(तत्पश्चात सदन सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 1989, बाद दोपहर 2.00 बजे तक स्थगित हुआ)